LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Friday, February 7, 2025 / Magha 18, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, February 7, 2025 / Magha 18, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **1 – 30**
(S.Q. NO. 61 – 66)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **31 – 50**
(S.Q. NO. 67 – 80)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **51 – 280**
(U.S.Q. NO. 691 – 920)

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, February 07, 2025 / Magha 18, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, February 07, 2025 / Magha 18, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 306

ELECTIONS TO COMMITTEES 307 - 08

(i) Governing Council of Indian Council of Medical Research 307

(ii) All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Gorakhpur 308

MOTION RE: 5TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 307

… 309

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 310 - 21

Shri Anurag Sharma 310

Captain Brijesh Chowta 311

Shri Ashish Dubey 311

Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya 312

Shri Lumba Ram 312

Shri Jugal Kishore 313

Shri Ravindra Shukla *Alias* Ravi Kishan 313 - 14

Shri Bibhu Prasad Tarai 314

Shri Rudra Narayan Pany 315

Shri Gaurav Gogoi 315

Adv. Dean Kuriakose 316

Shri Pradyut Bordoloi 316

Shri Rahul Kaswan 317

Shri Rajmohan Unnithan 317

Sushri S. Jothimani 318

Shri Devesh Shakya 318

Shri T.M. Selvaganapathi 319

Shri Dinesh Chandra Yadav 319

Shri Bhausaheb Rajaram Wakchaure 320

Shri Shrirang Appa Chandu Barne 320

Shri Chandan Chauhan 321

Shri Rajesh Ranjan 321

UNION BUDGET – GENERAL DISCUSSION 322 – 80
(Inconclusive)

Dr. Dharamvira Gandhi 322 - 36

Shri Rao Rajendra Singh 337 - 46

Dr. Shivpal Singh Patel 347 - 49

Shri Abhishek Banerjee 350 - 60

Shri Daggumalla Prasada Rao 361 - 63

Shri Dinesh Chandra Yadav 364 - 65

Shri Tariq Anwar 366 - 68

@ Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar 369

Shri Sudheer Gupta 370 - 77

Shri Naresh Ganpat Mhaske 378 - 80

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 380
6th Report

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar in Marathi, please see the Supplement (PP 369A – 369D)

UNION BUDGET – GENERAL DISCUSSION **381 - 428**
(Contd. - Inconclusive)

Shri Arun Govil **381 - 83**

Shri Benny Behanan **384 - 88**

Shri Rajeev Rai **389 - 91**

Shri Darshan Singh Choudhary **392 - 94**

Shrimati Satabdi Roy Banerjee **395 - 97**

Shri Pradyut Bordoloi **398 - 401**

Dr. Alok Kumar Suman **402 - 03**

Shri Chandan Chouhan **404 - 06**

@ Shri Gopal Jee Thakur **407**

 # Shri Balwant Baswant Wankhade **408**

Shri Sudama Prasad **409 - 11**

Shri Harendra Singh Malik **412 - 14**

Shrimati Lovely Anand **415 - 16**

Shrimati Anita Nagarsingh Chouhan **417**

Shri Brijendra Singh Ola **418 - 21**

Shri Eatala Rajender **422 - 25**

Adv. Chandra Shekhar **426 - 28**

xxxx

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Gopal Jee Thakur in Maithili, please see the Supplement (PP 407A – 407D)

 # For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Balwant Baswant Wankhede in Marathi, please see the Supplement (PP 408A – 408D)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, February 7, 2025 / Magha 18, 1946 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS **PAGES**

XXX XXX XXX XXX

Xxx xxx xxx xxx

Xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

UNION BUDGET – GENERAL DISCUSSION 369A - 69D & 407A - 08D

(Inconclusive)

xxx xxx xxx xxx

Shri Omprakash Bhupalsinh *Alias* Pavan Rajenimbalkar 369A - 69D

xxx xxx xxx xxx

Shri Gopal Jee Thakur 407A - 07D

Shri Balwant Baswant Wankhade 408A - 08D

xxxx

(1100/RV/RP)

(प्रश्न 61)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर - 61; श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर।

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, हमारे देश के आदिवासी क्षेत्रों, ग्रामीण इलाकों और विशेष रूप से विमुक्त जातियों (पी.वी.टी.जी.) में मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और दूर-दराज के इलाकों में अस्पतालों तक पहुंच न होना इस समस्या को और गंभीर बना रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मेरा सरकार से कहना है कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत कई योजनाएँ चला रही है, लेकिन आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ग्रामीण,आदिवासी और विमुक्त जातियों की महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना लाने पर विचार कर रही है? क्या सरकार इन क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ क्लीनिक, टेली मेडिसिन सुविधा और पोषण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और इस सदन को यह सूचित करना चाहती हूं कि जहां तक एम.एम.आर. और आई.एम.आर. का विषय है, तो दुनिया की तुलना में भारत ने बहुत बेहतरीन प्रगति की है। जहां पिछले तीस वर्षों में, वर्ष 1990 से लेकर वर्ष 2020 के बीच में, ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन फॉर एम.एम.आर. 42 प्रतिशत रहा है, वहीं भारत में यह 83 प्रतिशत तक पहुंचा है।

इसके साथ ही, जो इंफैन्ट मॉर्टैलिटी रेट है, इसमें ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन 55 प्रतिशत रहा है, लेकिन भारत में इसकी गिरावट की दर 69 प्रतिशत रही है। यह सब संभव हुआ है, क्योंकि हमने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कॉम्प्रिहेन्सिव मेजर्स चलाए हैं, जिसमें हम राज्य सरकारों और यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन को फाइनैंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। महिलाओं और बच्चों के हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करना, यह हमारे इस पूरे कार्यक्रम का फोकस रहता है। इसमें हम जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ऐसे तमाम कार्यक्रम चलाते हैं, जिसके माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हमें बेटर हेल्थ आउटकम्स मिल सकें और हमारी एम.एम.आर. और आई.एम.आर. में गिरावट हो।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न विशेष रूप से आदिवासी और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उठाया है, उसके संबंध में मैं उन्हें सूचित करना चाहती हूं कि हमारे स्पेशल आउटरीच कैम्प्स चलाए जाते हैं, जिसमें मोबाइल मेडिकल टीम्स भी इन दूर-दराज के इलाकों में जाती हैं। वहां हम गर्भवती महिलाओं को ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं और हम जो तमाम सुविधाएं ऐसी महिलाओं को दे रहे हैं, वे सुविधाएं उन्हें देने की कोशिश करते हैं। उनमें बहुत सारी हाई-रिस्क प्रेग्नैंसीज़ भी

होती हैं, जिन्हें कई बार हम आईडैंटिफाई भी करते हैं, जिससे कि हम एम.एम.आर. और आई.एम.आर. को कम कर सकें और मैटर्नल और इंफैन्ट हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकें।

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, स्पाइनल मस्क्युलर एट्रॉफी एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है, जिसमें नसों और मांसपेशियों का आपसी संपर्क टूट जाता है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डी.एम.डी.) जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली दुर्लभ बीमारियों में से एक है। मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बनने वाली इस समस्या के शिकार लोगों के लिए जीवन के सामान्य कामकाज काफी कठिन हो जाते हैं। ये दोनों बीमारियां न केवल बच्चों के लिए, बल्कि उनके माता-पिता के लिए भी जीवनभर का संघर्ष बन जाती हैं।

स्पाइनल मस्क्युलर एट्रॉफी (एस.एम.ए.) और ड्यूकेन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (डी.एम.डी.) जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज की समस्या बेहद गंभीर है। ये बीमारियां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसके उपचार के लिए उपलब्ध जीन थेरेपी और अन्य दवाएँ अत्यधिक महंगी हैं, जिनकी लागत 2-3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चा तक पहुंच जाती है।

(1105/KDS/NKL)

इतनी महंगी दवा होने के कारण एक सामान्य और गरीब परिवार इलाज के बारे में सोच भी नहीं सकता और इलाज के अभाव में कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार जीन थेरेपी और एसएमए, डीएमडी जैसी बीमारियों हेतु सस्ता इलाज कराने पर कोई विचार कर रही है? इसके लिए एनएचएम के तहत एक समर्पित रेयर डिजीज ट्रीटमेंट फंड बनाने की क्या कोई योजना है, जिससे जरूरतमंद परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आग्रह कर दूं कि सभी नए-पुराने अनुभवी सांसद यदि प्रश्न लिखकर भी लाए हैं, तो भी संक्षिप्त में लिखकर लाएं व संक्षेप में पूछें । माननीय मंत्रीगण से भी अपेक्षा है कि वे उनका संक्षेप में जवाब दें, ताकि हम ज्यादा प्रश्न ले सकें।

माननीय मंत्री जी।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेटरनल और इनफेंट हेल्थ आउटकम से जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वह रेयर डिज़ीज की मेडिसिन्स को लेकर है। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को केवल इतना बताना चाहती हूं कि रेयर डिज़ीज़ेज के लिए हमारा अलग कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी जो बजट आया, उसमें 36 ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन्स व ड्रग्स हैं, जिनमें से कुछ रेयर डिज़ीज की भी दवाएं हैं। इनको हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन भी दिया है। इनके जो अन्य सवाल हैं, उस हेतु ये अलग से मेरे साथ जब बैठेंगे, तो हम रेयर डिज़ीज पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय केन्द्रीय मंत्री जी, कृपया इस बारे में बताएं, क्योंकि यह सारे सदन की चिंता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, उससे ऐसी ध्वनि हाउस में आई कि जैसे ट्राइबल क्षेत्रों में, जैसे मेटरनल विषयों व एंटीनेटल चेकअप्स पर विशेष ध्यान नहीं

दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग व जो सभी प्रदेश हैं, उनके द्वारा एक साथ मिलकर इसमें बहुत अच्छा काम किया गया है। इस बारे में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमारे जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी एमएमआर व इन्फैंट मॉर्टेलिटी रेट यानी आईएमआर हैं तथा जो हमारी अंडर फाइव मॉर्टेलिटी है, ये ग्लोबल डिकलाइन से कहीं ज्यादा, यानी दोगुने से ज्यादा डिकलाइन है। मल्टी इंटरवेंशन्स के कारण हम ये कर पाए हैं। जैसा कि हमने ट्राइबल क्षेत्रों की बात की, तो बीजापुर, कोंटा, नारायणपुर, बस्तर, दन्तेवाड़ा, गढ़चिरौली ओडिशा के सारे ट्राइबल जिलों के हेल्थ पैरामीटर्स यदि आप देखें, तो जो एमएमआर, आईएमआर व अंडर फाइव मॉर्टेलिटी है, वह उसी तरीके से डिकलाइन कर रहा है, इसलिए यह ध्वनि नहीं जानी चाहिए कि ट्राइबल क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं बताना चाहूंगा कि जब हम वैक्सीनेशन और इनॉक्युलेशन की बात करते हैं, तो हमारे लद्दाख के जो दूरस्थ इलाके हैं, वहां से लेकर, गढ़चिरौली से लेकर, बस्तर से लेकर ये सारे उसके दायरे में आते हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उन सबके लिए आगे बढ़कर वहां तक काम को पहुंचाते हैं।

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूं और बधाई देना चाहती हूं कि उनके प्रयासों व योजनाओं की वजह से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट व इन्फैंट मॉर्टेलिटी रेट काफी कम होकर 33 प्रति लाख लाइफ बर्थ पर आ चुका है। हम सर्वाइकल कैंसर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जो एमएमआर का एक बहुत बड़ा कारण है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर के लिए हो चुकी है। वित्त मंत्री जी ने भी वर्ष 2024 के बजट भाषण में कहा था कि ह्यूमन पैपीलोमा वायरस का जो वैक्सीन है, उसे राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जाएगी।

मेरा प्रश्न यह है कि सर्वाइकल कैंसर से आज लगभग 20 प्रतिशत महिलाओं की मौत हो जाती है और डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि यदि एचपीवी वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इनक्लूड किया जाएगा तो उससे लगभग 16 गुना आर्थिक लाभ देश को होगा। मैं पूछना चाहती हूं कि इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब तक शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन महिलाओं को मिलेगा, जो आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं हैं और शोषित व वंचित वर्ग से आती हैं। धन्यवाद।

(1110/PC/VR)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि सर्वाइकल कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, उनमें हमारी सरकार ने, जो भी हमारी 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं, उनके लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है।

जो चिंताएं माननीय सदस्य ने व्यक्त की हैं, हम उनसे पूरा सरोकार रखते हैं। एचपीवी वैक्सीन को लेकर अभी सरकार तमाम प्रकार के चिंतन-मंथन कर रही है, यह प्रक्रिया में है। जैसे ही इसके संबंध में कुछ तय होगा, हम सदन को सूचित करेंगे।

फिलहाल, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यह विषय इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। इस पर हम अलग से बैठकर बात भी कर सकते हैं।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Speaker, Sir. I would like to invite the attention of the hon. Minister to a very serious matter. We have many schemes like Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha Karyakram, etc.

Sir, a serious incident happened just two months before in my constituency, and that is why I am bringing it to your notice. One lady named Anish delivered a newborn child with serious problems. Now, her mouth does not open. She cannot raise her hands. Basically, she is not in a position to live. This issue came to the media, the public and everywhere.

Sir, during her pregnancy period, the doctors advised her to go for a scan for about four times. But they did not find any problem. Then, the question arises, 'why did this happen'? All over Kerala, people are asking this question. The Government is giving enough funds. She was treated in a Government hospital. The problem is that either they are not caring much or there is a nexus between the hospital and the scanning centres. So, proper scanning is not being done. Now the child is in a critical condition.

My question to the hon. Minister is, has the Minister put any strong mechanism in place to monitor whether these schemes are going to benefit the concerned people in a proper way?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, as I told you, we have a very robust system of monitoring, and because of that the results are better than the global outcomes.

The hon. Member has mentioned about an individual case. I do not know about that individual case. But certainly, if you give it to me in writing, I will get it inquired, go into the details of it and see what rectification can be done by the State Government and the State Health Department because the execution part is with the State Department. So, I will discuss it with them.

(ends)

(प्रश्न 62)

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि विगत पांच वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

क्या सरकार की उर्वरकों की अधिक खपत वाले बिहार जैसे राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

क्या सरकार आयातित उर्वरकों की कीमत कम होने के कारण देश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक नहीं है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(1115/GG/SNT)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब 07 अक्टूबर, 2014 को छह नए फर्टीलाइज़र के प्लांट्स लगाने का निर्णय किया, जो चार पब्लिक सैक्टर में थे और दो प्राइवेट सैक्टर में थे। एक रामागुंडम, तेलंगाना में, एक गोरखपुर में, एक सिंदरी में, एक बरौनी में और जो प्राइवेट सैक्टर के थे, उनमें से एक राजस्थान और एक पश्चिम बंगाल में थे। इस तरीके से लगभग हरेक फर्टीलाइज़र फैक्ट्री की कैपेसिटी में लगभग 12 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। कुल मिला कर 76 लाख मीट्रिक टन, छह नए न्यू प्लांट्स में बढ़े हैं और वर्ष 2014 में हमारी कैपेसिटी 225 लाख मीट्रिक टन थी। इसी बीच में गैसिफिकेशन के माध्यम से भी और एनर्जी को इंप्रूव करते हुए, इन्हीं प्लांट्स की कैपेसिटी को 20 से 25 लाख मीट्रिक लाख टन और बढ़ाया गया। अब हम 315 लाख मीट्रिक टन फर्टीलाइज़र प्रोड्यूज़ कर रहे हैं।

जहां तक फर्टीलाइज़र की फैक्ट्री को लगाने का सवाल है, यह कंजम्पशन के बेस पर नहीं होता है। यह वहां के रॉ मटीरियल और उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। ईस्टर्न इंडिया की तरफ इसका ध्यान कम दिया गया था। इसलिए ईस्टर्न इंडिया की तरफ ये सारे के सारे प्लांट्स लगे हैं। जैसे-जैसे उपलब्धता और उसकी आवश्यकता होती है, हम इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है कि सीज़न के समय बिहार एवं अन्य राज्यों में किसानों को समय पर खाद और उर्वरक नहीं मिलता है और उन्हें मजबूरन खेती के लिए ब्लैक में उर्वरक खरीदना पड़ता है। समय पर स्टॉक कैसे किसानों के पास पहुंचे, यह व्यवस्था की गड़बड़ी है। सरकार कंपनी को सीधे सब्सिडी देती है। खाद निर्माता कंपनी को उर्वरक किसानों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी है। किंतु उर्वरक निर्माता रेलवे ट्रैक से खाद आगे पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वहीं से डीलर या स्टॉकिस्ट को ब्लैक करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक भी समय से नहीं मिल पाता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

दूसरा प्रश्न है कि बिहार में खाद, विशेषकर यूरिया की किल्लत और ब्लैक का मुख्य कारण बिहार का नेपाल के साथ बार्डर सटा होना है। इस कारण खाद डीलर आसानी से बिहार से नेपाल

यूरिया की सप्लाई कर देता है। पकड़े जाने पर कार्रवाई सीधे डीलर पर होती है, किंतु गाड़ियों और ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में शराबबंदी है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया है।

माननीय मंत्री जी।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड फार्मर्स वैलफेयर के साथ मिल कर डेटवाइज़, मंथवाइज, वीकवाइज़, एरियावाइज़ तय होता है कि किसको खाद डीएपी कब कहां पहुंचेगी। हम उसके अनुसार उसको पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। इसका इंटिग्रेटिड डिज़िटाइज़्ड बेस्ड सिस्टम है, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें टाइम पर मॉनिटर होती रहती हैं। जहां तक इसके डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है, उसमें कई लोग अनावश्यक रूप से यह क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्मेंट के साथ हम रैग्युलरली कॉन्टैक्ट में रहते हैं। एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शन लेने का काम स्टेट गवर्मेंट का है। वे एक्शन लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंश्योर करते हैं कि किसानों को समय पर खाद मिल जाए।

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार नैनो-यूरिया एवं अन्य उर्वरक लिक्विड बना रही हैं। खाद निर्माता कंपनी किसानों को नैनो-फर्टीलाइज़र ही इस्तेमाल करने के लिए मज़बूर कर रही हैं। लिक्विड खाद का इस्तेमाल स्प्रे द्वारा ही हो सकता है और स्प्रे के लिए सरकार का ड्रोन पर फोकस है। अब किसानों को यही परेशानी होती है, क्योंकि ड्रोन से बड़ी खेती में स्प्रे तो हो सकता है, किंतु मेरे बिहार राज्य में छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास पांच कट्ठा, दस कट्ठा और ज्यादा से ज्यादा एक बीघा ज़मीन है।

(1120/CP/AK)

उसमें ड्रोन से स्प्रे नहीं हो सकता है। किसानों को छोटी स्प्रे मशीन चाहिए। क्या सरकार बिहार में किसानों को स्प्रे मशीन की खरीद के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है? लिक्विड उर्वरक निर्माता कंपनी नैनो खाद के फायदे के संबंध में बिहार में जानकारी के लिए कोई एडवरटाइजमेंट नहीं करती है। किसानों को उसके फायदे की जानकारी देने संबंधी कोई कार्यक्रम चलाने के लिए क्या सरकार उस कंपनी पर कोई दबाव डालेगी?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार नैनो खाद का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करती है, प्रेरित करती है। हम उन्हें प्रेरित करते हैं।

दूसरी बात, यह क्वैश्चन ओरिजनल क्वैश्चन से अलग है। ये ड्रोन और स्प्रे के बारे में अलग से क्वैश्चन करेंगे तो हम उसके बारे में उत्तर देंगे। यह मेन क्वैश्चन से जुड़ा हुआ नहीं है।

इस सदन की जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि कई बार खाद के बारे में चर्चा होती है। यूरिया जो हम 266 रुपये एमआरपी, 45 किलोग्राम का दे रहे हैं, उस पर सब्सिडी 1,617 रुपये हैं, यानी 1,400 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 किलोग्राम पर दे रही है। हम डीएपी 1,350 रुपये पर दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप यूरिया का रेट भी इनको बता दीजिए। यूरिया का बैग कितने रुपये का देते हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: यूरिया का 45 किलोग्राम का बैग 266 रुपये।

माननीय अध्यक्ष : मैं इसलिए कह रहा हूं कि जय प्रकाश जी उस दिन कह रहे थे कि 1,300 रुपये का देते हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 300 रुपये से कम में देते हैं। मैं इसलिए 266 रुपये याद दिला रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यूरिया के बारे में बात कर रहे थे।

… (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैं बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने, जब इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत किल्लत हुई थी, तब भी वर्ष 2020 से कोरोना के टाइम में इसकी कॉस्ट को 1,350 रुपये एमआरपी, 50 किलोग्राम प्रति बैग से नहीं बढ़ने दिया है और आज के दिन भी यह 1,350 रुपये में मिल रहा है।

तीसरी बात, इसमें जो कॉस्ट बढ़ती है, वह 3,000 रुपये प्रति बैग पड़ती है, यानी 1,650 रुपये प्रति बैग भारत सरकार डीएपी के लिए पे कर रही है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए।

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों हमारे लोक सभा क्षेत्र धौरहरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत रही। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि आगे यूरिया की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और पहली बात माननीय सांसद महोदय, हमारे सदस्य को बताना चाहता हूं कि कभी भी किल्लत नहीं रही। …(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।… (व्यवधान) मैं आपकी मदद चाहता हूं।… (व्यवधान) किल्लत क्रिएट की जाती है। कुछ लोग मार्केट को इंटरवेंशन करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आप हमसे पता कीजिए, मंत्रालय से पता कीजिए कि जिस दिन तय किया है, रैक्स उस दिन पहुंचते हैं, लेकिन अननेसेसरली क्राइसिस क्रिएट करके कुछ लोग उसमें मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्टिव होना चाहिए और आप सांसदों को हमारी मदद करनी चाहिए कि पब्लिकली इन चीजों को लाया जाए।… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ने के बावजूद हमारे किसानों पर बोझ नहीं पड़ने दिया, इसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बहुत प्लानिंग के साथ यह तय किया जाता है कि कब, कहां खाद पहुंचनी चाहिए। मेरा केवल एक सवाल है, जिसके दो भाग हैं। हम

सेल्फ रिलायंट बनने की बात करते हैं। रॉ मैटेरियल तो हम विदेशों से लाते हैं, तो हम सेल्फ रिलायंट इसमें कैसे बन सकते हैं? आपने कहा कि बीच में मुनाफाखोरी करने की वजह से मार्केट में कमी आती है, खाद नहीं पहुंच पाती। मैं जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? कृपया इस बारे में अवगत कराएं।

(1125/NK/UB)

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार प्रदेश सरकार को समय-समय पर चेताती रहती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन बातों को इन्श्योर करते हैं कि मार्केट में डीएपी सही रेट पर मिल सके।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, the Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) is a pioneer institution which produces fertilizers and chemicals in the country. It was established in 1943 right before the pre-Independence Movement. This particular institution has been a backbone of the farmers of the country and many times, it has incurred losses, but for the last four years, it has been making profits. However, for the last one year, they do not have a CMD as no CMD has been appointed yet. When there was a CMD, the institution was functioning very well.

Earlier, the previous Minister promised a nano-urea plant for FACT. Will measures be taken to establish a nano-urea plant? Secondly, will the CMD be appointed very soon as it is a very critical unit which has been making profits for the country and providing fertilizers and chemicals to the farmers?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I will look into the matter and see what we can do. As far as establishing a nano-urea unit is concerned, I would like to ask the hon. Member to give me in writing, the Department concerned will examine it.

(ends)

(प्रश्न 63)

श्री अनूप संजय धोत्रे (अकोला) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का आभार मानता हूं, जिन्होंने बजट में कपास किसानों के लिए कॉटन रिसर्च पर पांच सौ करोड़ रुपये का बजट रखा है, इसके साथ ही हाइब्रिड सीड्स डेवलपमेंट के लिए अच्छा बजट रखा है। सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे कपास के किसानों को अच्छी राहत मिलेगी। एक निर्णय लिया है कपास के नाइट्रेट फाइबर पर दस से बीस परसेंट की कस्टम ड्यूटी की गई है, जिससे टेक्सटाइल किसानों को अच्छी राहत मिलेगी।

मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, जो एक अच्छा एफपीओ चलाते हैं और सोयाबीन रिसर्च के लिए एक अच्छा काम करते हैं। मेरा प्रश्न है कि मेडिसीनल प्लांट्स और हर्बल प्लांट्स के एक्सपोर्ट के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है?

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, मेडिसीनल प्लांट्स एक्सपोर्ट का डाटा आयुष मंत्रालय संकलित नहीं करता है बल्कि डीजीएफटी संकलित करता है, उनके पास ही डाटा रहता है। उनके आंकड़ों के अनुसार लगभग चार हजार करोड़ रुपये मेडिसीनल प्लांट्स का निर्यात हुआ है।

आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से आयुष मंत्रालय का निर्माण किया गया, तब से मेडिसीनल प्लांट्स एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें 17 से 18 प्रतिशत की वृद्धि आयी है। मेडिसीनल प्लांट्स हम बहुत सारे देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं।

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): Sir, I would like to ask the hon. Minister to provide the details of any collaboration or partnership with the international organisations or countries with respect to conservation and sustainable use of herbal plants and medicines.

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, लगभग पिछले दस सालों में पांच देशों के साथ मेडिसीनल प्लांट्स के संवर्धन और एक्सपोर्ट करने के बारे में एमओयू भी साइन हुए हैं। वियतनाम, बांग्लादेश, साओ तोमे और प्रिन्सिपी, इक्वाडोर, गिनी, त्रिनिदाद और टोबैगो इत्यादि देशों के साथ हमने एमओयू साइन किया। हमारे मेडिसीनल प्लांट्स है, हम अपने देश में भी उनका संवर्धन कर रहे हैं, बाहर के देशों के साथ भी संवर्धन करने के लिए इन देशों का सहयोग लेकर वहां पर भी काम किया जा रहा है।

(1130/KDS/GM)

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी (बीरभूम) : सर, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 30 परसेंट मेडिसिन्स फेक और डुप्लीकेट हैं। यह रिपोर्ट आने के बाद भी मंत्रालय ने क्या स्टेप्स लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, मैं यह जानना चाहती हूं?

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : महोदय, यह प्रश्न विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वे सभी दुकानों से सैंपल सैंपल लेते हैं और वे हमारी स्टेट्स की लैब्स में दी जाती हैं। कुछ भी गैरकानूनी मिलने पर उन पर कार्रवाई भी की जाती है।

(ends)

(प्रश्न 64)

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत मरीजों को गंभीर बीमारी के कारण निजी अस्पतालों में भर्ती होने के पश्चात् यदि ऑपरेशन कराना हो, तो उसके लिए कार्ड को नैशनल हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूवल की आवश्यकता होती है। कई बार ऑपरेशन की काफी आवश्यकता होने पर अस्पतालों द्वारा मरीजों से पैसे लिए जाते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं या वे कहीं से पैसों का इंतजाम कर सकते हैं, तो उनका ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन कई मरीज पैसों के अभाव के कारण अपना दम तोड़ देते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ऐसी समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस स्कीम के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, जो वर्ष 2018 में लाँच हुई, वह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। जब यह शुरु हुई, तो इसमें 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर एक फैमिली को एक साल के लिए देना तय हुआ। 55 करोड़ लोग यानी 12 करोड़ 37 लाख परिवार इससे जुड़े और 55 करोड़ लोगों, यानी भारत की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को इस हेल्थ कार्ड के अंदर कवर किया गया।

महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में इसमें 37 लाख आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्प वर्कर्स को भी जोड़ा गया। जब प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, तो 29 अक्टूबर, 2025 को 6 करोड़ सीनियर सिटिजन्स यानी 70 साल से ऊपर के लोगों को जोड़ा गया। कुल मिलाकर 61 करोड़ से ज्यादा लोगों को हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज दिया गया। इसमें मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक 8.59 करोड़, मतलब 8 करोड़ 60 लाख अस्पतालों में एडमिशन्स हो चुके हैं, यानी 8 करोड़ 60 लाख लोगों को अस्पतालों में राहत दी गई है। 1.19 लाख करोड़ की ऑथराइजेशन, यानी 1.19 लाख करोड़ रुपये, गरीबों के इलाज के लिए खर्च हुए हैं और उनके जीवन को बचाने का काम हुआ है।

महोदय, इन्होंने कहा कि इलाज में दिक्कत आती है, यह मांगा जाता है, वह मांगा जाता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत स्कीम में सब-कुछ फ्री है। 1 हजार 961 सर्जिकल इंटरवेंशन की व्यवस्था है। 30 हजार अस्पताल इम्पैनल्ड हैं और 30 हजार इम्पैनल्ड अस्पतालों में 1,961 सर्जिकल इंटरवेंशन्स की व्यवस्था है, which includes bypass surgery, which includes chemo-therapy, which includes radio-therapy, which includes other surgical interventions, ये सभी किए जाते हैं। उनमें घुटने यानी नी ट्रांसप्लांट को लेकर इन सारी व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है। अगर इनके पास कोई स्पेसिफिक केस है, तो ये जरूर हमारे ध्यान में लाएं। हम उस विषय को अवश्य स्टेट अथॉरिटी के साथ बातचीत करके डिसकस करेंगे।

(1135/MK/SRG)

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत की तरह कई निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा देरी से भुगतान होने के कारण उनके द्वारा इलाज से इनकार किया जा रहा है। इस समस्या को हल करने और इलाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र द्वारा कहीं भी किसी के साथ पैसे को पहुंचाने में कोई देरी नहीं की जा रही है। हमारे तीन किस्म के फंड्स हैं। एक वह है, जो स्टेट एश्योरेंस पर चलता है, दूसरा स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिलाकर एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से जाता है और तीसरा डायरेक्ट तरीके से जाता है। जहां पर स्टेट का जो शेयर होता है, वह कभी-कभी नहीं आ पाता है, इसलिए उसके कारण दिक्कत आती है। लेकिन भारत सरकार सजग रहती है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर पैसे का भुगतान डिजिटली टू द हॉस्पिटल टाइम पर किया जाता है।

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): I would like to know whether the Government plans to include economically poor persons in addition to BPL card holders under the Ayushman Bharat Yojana. What steps have been taken to address the shortage of doctors, resources, and infrastructure? Also please share the State-wise data of the number of hospitals currently empanelled under the Scheme. Also, does the Government have any plans to strengthen the infrastructure facilities and doctors' availability, specialists in particular, to reduce burden on the prestigious AIIMS and other prestigious institutions?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: May I know your first question?

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): It was whether the Government planned to include economically poor persons other than the BPL card holder.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह बीपीएल कार्ड होल्डर को नहीं दिया जाता है। सोशियो इकॉनामिक कॉस्ट सेंसस के तहत जिन लोगों का चयन हुआ है, उनकी संख्या, जैसा मैंने अभी बताया कि उसमें 12 करोड़ 37 लाख परिवार इनक्लूड किए गए हैं। उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। बाई प्रोफेशन भी, जैसे मैं कई बार बताता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, फेरी वाला, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बार्बर, हमारे शूज बनाने वाले, रैग पिकर्स इत्यादि, ऐसे जो गरीब लोग हैं, जिनको हॉस्पिटल जाने में दिक्कत आती हैं, वे नहीं जा पाते हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना में यह फैसिलिटी दी जा रही है।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, the Jan Aarogya Yojana is an important programme, but it is alarming to know from the reply of the hon. Minister that 1,114 hospitals are involved in the fraud, a penalty has

been levied for 1,504 hospitals and suspension of 549 hospitals is there. Can the Minister share the State-wise list of the hospitals which come under these three categories? Can the hon. Minister provide the list of hospitals in Tamil Nadu which are in that list of fraud, penalty and suspension?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I would elaborately give the answer accordingly. For the Ayushman Bharat Yojana, we have got National Anti-Fraud Unit (NAFU), and we have got State Anti-Fraud Units. For that, we always identify the suspicious cases. Here, I would also like to share with the hon. Member that we have got 57 triggers for detecting fraud, and 44 are rule- based. For example, if a patient goes for a bypass surgery, he has to stay in the hospital for 10 days. That is the rule. If he is discharged after the third day, then something suspicious is there. This is called rule-based trigger. So, there are 40 rule-based triggers which digitally come to us and this is the methodology. The same way under the artificial intelligence and machine learning, there are 13 artificial intelligence-based and machine learning triggers which work.

(1140/RCP/SJN)

We have got image analytics. For example, if a procedure has been done, the same photograph is given for another patient also. So, that is also detected. So, image analytics are there; four types of image analytics are there. Image classification is there. Optical character recognition is there. Deep learning process is also there. Having said that, this is a continuous process because there are people in the market who try to develop new types of frauds. We also develop digitally new types of triggers to see to it that the fraud is detected and action is taken. As you also have mentioned, we have taken action against 1140 hospitals. A penalty of Rs.122 crore has been imposed. This is not a small amount; Rs.122 crore is the penalty which has been enforced. There is suspension of 549 hospitals. Nine doctors have been suspended. This is about a particular State.

As you have asked about Tamil Nadu, I will give you a separate answer for that.

(ends)

(प्रश्न 65)

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट और विस्तृत उत्तर दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा प्रश्न है कि 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के अंतर्गत कौन-सी तकनीक में प्रगति की गई है? कृपया उसके बारे में बताया जाए।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, समता और सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। आंगनवाड़ी को सक्षम और प्रभावशाली बनाने तथा इसके इको सिस्टम को और मजबूत करने के लिए 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपये स्वीकृत हैं। हमने लगभग 2,00,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए स्वीकृत किया है।

उसको उन्नत करने के लिए बुनियादी ढांचे में वाई-फाई, इंटरनेट, एलईडी स्क्रीन के साथ-साथ पोषण वाटिका में टॉयलेट्स और पेयजल की सुविधा तथा बच्चों के संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हमने शिक्षण उपकरण आदि भी शामिल किए हैं। कई ऐसे इंटरवेन्शंस हैं, 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के माध्यम से बच्चों को सिर्फ पोषण ही न मिले, बल्कि हम पढ़ाई और बेहतर स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं। हम इसके माध्यम से लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लाभकों को लाभ भी पहुंचा रहे हैं।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में क्या अन्य मंत्रालयों से भी सहयोग लिया जा रहा है?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में कई मंत्रालय शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लगभग 18 मंत्रालयों के कन्वर्जन के साथ चलता है। विशेषकर ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत हम आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें मनरेगा के तहत 8,00,000 रुपये देते हैं, 15वें वित्त आयोग की असंबद्ध राशि के तहत 2,00,000 रुपये देते हैं और हम विभाग के माध्यम से प्रति आंगनवाड़ी को 2,00,000 रुपये देते हैं, ताकि उसकी आधारभूत संरचना का विकास हो।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' (पीएम जनमन) के तहत 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। विशेष रूप से यह योजना 75 कमजोर जनजाति समूहों के लिए है। इसके माध्यम से हमें 2,500 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करना है। हमने अभी तक 2,139 आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृति दे दी है। उसमें लगभग 1,001 आंगनवाड़ी कार्यशील भी हैं।

(1145/SPS/PS)

उसके तहत लगभग 22,800 लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ-साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से भी दो हजार नए आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्थापित किया जाना है और सक्षम बनाना है। उसके साथ-साथ वहां पर अन्य 6,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम बनाना है। इसके लिए हम कई विभागों के साथ मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं, ताकि उसका लाभ सही ढंग से लोगों को मिल सके।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे यह प्रश्न पूछने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आंगनवाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और यह एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। आंगनवाड़ी बहनों को जो मानदेय मिलता है, वह कितना है? अगर यह सम्मानजनक मानदेय है तो उसकी भी जानकारी दें। अगर यह सम्मानजनक मानदेय नहीं है तो जब आप इसका उत्तर देंगी तो यह भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि में किसी कार्यक्रम की रूपरेखा है? उनसे काम तो बहुत लिया जाता है, लेकिन उनको सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलता है।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : अध्यक्ष महोदय, जो कार्यकर्ता है, वे उसी ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं। हम उनसे 6 घंटे के लिए काम लेते हैं। निश्चित रूप से वे आज बहुत ही बेहतर काम कर रही हैं और विभिन्न राज्य सरकारें भी उनसे अलग-अलग तरीके से काम ले रही हैं। हम उन्हें भारत सरकार के माध्यम से अलग-अलग मानदेय देते हैं और समय-समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। हमने मानदेय के अलावा भी उनको जीवन बीमा और आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ कवरेज स्कीम से भी जोड़ा है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा भी उनको सुविधा दी जाती है। उनको अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा भी राशि दी जाती है और वह राशि कहीं 15 हजार रुपये और कहीं 10 हजार रुपयेहै। … (व्यवधान) अलग-अलग राज्य टॉप अप देते हैं। अगर टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के मानदेय एक रूप में नहीं है।… (व्यवधान) चूंकि यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसलिए हम आपको डिटेल दे देंगे कि किस राज्य में कितने पैसे दिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने समय-समय पर पैसा बढ़ाया है और वर्ष 2018 में भी पैसा बढ़ाया है। जब हम महसूस करते हैं, तब उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

श्रीमती संध्या राय (भिण्ड) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी लाभ मिले, उस दिशा में हमारी सरकार की पहल है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र या आसपास सरकारी स्कूलों या पंचायती भूमि पर पोषण वाटिकाएं बनाई जाएं, जिससे हमारी महिलाओं और बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अभी तक पूरे भारतवर्ष और मध्य प्रदेश में कितनी पोषण वाटिकाएं संचालित हैं और हमारी सरकार का आगामी लक्ष्य क्या है?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : अध्यक्ष महोदय, पोषण वाटिका मिशन आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं। अभी तक पूरे देश के अंदर सक्षम आंगनवाड़ी निर्माण के लिए

दो लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है। सक्षम आंगनवाड़ी में पोषण वाटिकाएं भी होती हैं। पोषण वाटिका के साथ-साथ बेहतर आधारभूत संरचना, टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी

की व्यवस्था और आरओ सिस्टम की भी व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों को ईसीसीई में अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं। उसके लिए भी एक एलईडी स्क्रीन देते हैं, ताकि उसके माध्यम से बच्चे अनौपचारिक तौर पर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

इसके तहत राज्य सरकार से हमारे पास 2 लाख प्रस्ताव आए हैं, जिसकी हमने स्वीकृति दी है। लगभग 15 हजार से ज्यादा सक्षम बन चुके हैं, जहां पोषण वाटिकाएं भी हैं। अगर आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर जगह नहीं है तो हम राज्य सरकार से कहते हैं कि दूसरी सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर पोषण वाटिकाएं बनाएं, ताकि उस पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन और हरी साग सब्जियां खिला सकें।

(1150/MM/SMN)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सर!

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, यह महिलाओं का विषय है।

*SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG): Honourable Speaker, Sir, thank you for the opportunity to raise my question. My Lok Sabha Consistency is Arambag. My journey to this Parliament started with me being an ICDS worker.

The honourable minister has mentioned that upgradation was done to forty thousand Anganwadi Centres and they were also modernised. The sanctioned amount for nutrition is meagre. It is Rs. 1.63 for a mother and it is Rs. 1.04 for a child. With such an amount, how do you even ensure the quality of nutrients? Inflation is skyrocketing. In the present scenario, how can we provide supplementary nutrition? I have an additional request.

माननीय अध्यक्ष : आप केवल प्रश्न पूछिए, कृपया भाषण मत दीजिए।

*SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG): Today, we need to update all the specifics to the POSHAN portal. I believe without wasting time on the POSHAN app, if the government had prioritised nutrition, we could have

* Original in Bengali

hoped for a brighter future. Handling this POSHAN portal is complex due to bad internet connectivity, and sometimes, it is also practically difficult to update all details of the workers. My question is, due to inflation, the prices of daily commodities are skyrocketing. How do we ensure the quality of nutrition under such circumstances?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा कि प्रधान मंत्री जी के लक्ष्य और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से बेहतर सुविधा 10 करोड़ लाभार्थियों को मिल सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और उसी के तहत वर्ष 2023 में बच्चों को कितनी कैलारी देनी है, इसके लिए नार्म्स बने हैं और उसके तहत माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में घोषणा भी की है। आपकी जो चिंता है, वह सरकार की भी है और हम चाहते हैं कि बाजार मूल्य के आधार पर उन्हें सहायता मिल सके तो इस बजट में उसका प्रावधान भी हुआ है। आने वाले समय में जो आपकी चिंता है, उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी।

*But I would like to request that since you hail from West Bengal, you kindly request *Didi* to expedite the process while implementing the ongoing schemes. She is merely renaming many of these schemes.

(ends)

* Original in Bengali

प्रश्न (66)

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश को वर्ष 2022 तक कुपोषित मुक्त बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया था? यदि हां, तो उक्त अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा हासिल की गयी उपलब्धि का ब्यौरा दें तथा उक्त अभियान को पूरा करने के लिए आयी कठिनाइयों का ब्यौरा दें। महाराष्ट्र में भन्डारा-गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र में कुपोषण जैसी गम्भीर समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है? सरकार के द्वारा उक्त अभियान के तहत भन्डारा-गोंदिया जिले में अब तक प्रदान की गयी धनराशि का ब्यौरा दें।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी प्रणाली को सशक्त बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसी के तहत हम सुपोषित भारत, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं और खास तौर पर अगर हम देखें तो कुपोषण की बात माननीय सदस्य ने की है तो वर्ष 2018 में पोषण अभियान का आरम्भ किया गया। यह मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कुपोषण, जो एक दिन का नहीं है, इसके लिए कई दिन तक हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है तभी इसको ठीक किया जा सकता है।

(1155/YSH/SM)

पोषण अभियान के तहत हमारे लगभग एक करोड़ से ज्यादा कार्यक्रम हुए हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चूँकि खान-पान के साथ-साथ जागरूकता भी बड़ी चीज है। हम उनके बिहेवियर चेंज के लिए भी उनको जागरूक करते हैं। उसके साथ-साथ कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक सहभागिता, लाभार्थियों के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष पोषण माँ और पोषण पखवाड़ा के माध्यम से हम गतिविधियां आयोजित करते हैं। अभी तक अगर हम देखें तो लगभग 13 करोड़ गतिविधियां हुई हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, जो हमारे 10 करोड़ लाभार्थी हैं, जो सैम और मैम बच्चे हैं, उनको हम टीएचआर के माध्यम से और हॉट कुक मील के माध्यम से खाना देते हैं।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदय, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। भारत का जीएचआई स्कोर 27.3 है, जो पिछले वर्षों की तुलना में मामूली सुधार को दर्शाता है। हालांकि भारत की रैंकिंग पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका - 56, नेपाल - 68 और बांग्लादेश - 84 से पीछे है। हम इस वास्तविकता में क्या कुपोषण मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं? भारत के पड़ोसी देश भी भारत से आगे हैं और क्या हम मेडगाड जैसे क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं? क्या हम उनको न्याय दे सकते हैं? क्या वहां के कुपोषित बालकों की मदद कर सकते हैं, जहां पर आए दिन काफी बालकों की मृत्यु हो रही है?

(pp. 19-30)

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : अध्यक्ष महोदय, अगर हम एनएफएसएच के डेटा को देखें तो एनएफएसएच – 4 के अनुसार जिन बच्चों में ठिगनापन 38.4 परसेंट था, वह अभी एनएफएसएच – 5 में लगभग 35.5 परसेंट हुआ है, यानी कि वह घटा है। उसी तरह से वेस्टिंग में भी 35 परसेंट से 32 परसेंट हुआ है और दुबलेपन में भी 21 परसेंट से 19 परसेंट हुआ है। इसके साथ-साथ पोषण ट्रेकर का जो डेटा है, उसको देखा जाए तो भी बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। डेटा में पहले की अपेक्षा अब धीरे-धीरे सुधार भी हो रहा है। इसी तरह से जो उसके घटक हैं, उनमें भी हमें निश्चित रूप से सुधार दिख रहा है। इसके अलावा विभाग के माध्यम से भी हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, ताकि माननीय प्रधान मंत्री जी का कुपोषण मुक्त भारत का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम हासिल कर सकें। उसके लिए हेल्थ विभाग के माध्यम से मिलकर हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसमें जल्दी ही हमें लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल कस्वां।

समय हो गया है, इसलिए आप शॉर्ट में प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं यह कहना चाहता हूँ कि 33 साल पहले इस देश के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होना शुरू हुआ। 33 साल के पश्चात् भी हम स्टंटिंग, अंडर वेट और वेस्टिंग कंट्री में उस पैमाने पर कम नहीं कर पाए, जितना हमें कम करना चाहिए था। मेरा प्रश्न इतना ही है कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वर्ष 2021 के अंदर 16 करोड़ बच्चे इस कंट्री के अंदर थे, जो पांच साल से कम उम्र के थे। उनमें से हम सिर्फ आधे बच्चों का ही डेटा कलेक्ट करके एनएफएचएस के अंदर शामिल कर पाए हैं। क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान रखती है कि जो 'आभा' आईडी है, उस आईडी के माध्यम से इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का डेटा रखा जाए, ताकि हम कंट्री को मालन्यूट्रिशन से फ्री कर सकें।

1158 बजे (श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : सभापति महोदय, सांसद महोदय ने जो सवाल उठाया है, उस पर मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें लगातार सुधार हो रहा है। सिर्फ खान-पान ही नहीं, बल्कि व्यवहार परिवर्तन भी इसकी बड़ी वजह है। हम जन-जागरूकता के माध्यम से, पोषण अभियान के माध्यम से लोगों के खान-पान में सुधार ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब के बच्चे ही कुपोषित हैं, बल्कि अन्य बच्चे भी उस श्रेणी में आते हैं। इसलिए व्यवहार परिवर्तन बहुत मायने रखता है इसलिए हम इसको लेकर लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी जो चिंता है, विभाग उसको लेकर काम कर रहा है। आने वाले समय में हमारा जो हस्तक्षेप है, उस हस्तक्षेप के माध्यम से हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

(1200/RAJ/RP)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर – 2, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Hon. Chairperson Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2025-2026.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2025-2026.

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2025-2026 के लिए आयुष मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2025-2026 के लिए आयुष मंत्रालय का निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 4875 जो दिनांक 11 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजन के लिए सरोगेसी बोर्ड की संशोधित संरचना को उसमें उल्लिखित दिनांक 4 मई, 2022 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा (च) को प्रतिस्थापित कर अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.4878 जो दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डॉ. वनिता जैन, विभागाध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्री रोग, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ को चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में प्रख्यात पंजीकृत चिकित्सा वृत्तिक की श्रेणी में सदस्य के रूप में शामिल किया जाना अधिसूचित किया गया है।

(3) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपरोक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपरोक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपरोक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपरोक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपरोक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपरोक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) एम्स, अवंतीपुरा कश्मीर के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम्स, अवंतीपुरा, कश्मीर के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 तथा 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपरोक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2025-2026 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2025-2026 के लिए विद्युत मंत्रालय का निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण का सरकार द्वारा समीक्षा विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपरोक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, देवनार, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, देवनार, मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपरोक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण।

(दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण।

(दो) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग) (एक) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, एर्नाकुलम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, एर्नाकुलम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(घ) (एक) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण।

(दो) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ड़) (एक) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(च) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(छ) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ज) (एक) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कामकाज की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(17) उपर्युक्त (16) की मद संख्या (घ से ज तक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपरोक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपरोक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :-

(एक) भारतीय नर्स परिषद (कार्डियोथोरेसिक विशेषज्ञता नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा – रेजीडेंसी प्रोग्राम) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.11-1/2024-आईएनसी(एक) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय नर्स परिषद (आपातकालीन और आपदा विशेषज्ञता नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा – रेजीडेंसी प्रोग्राम) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.11-1/2024-आईएनसी(दो) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय नर्स परिषद (उपशामक देखभाल विशेषज्ञता नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा – रेजीडेंसी प्रोग्राम) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.11-1/2024-आईएनसी(तीन) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय नर्स परिषद (वृद्धावस्था नर्सिंग में नर्स प्रैक्टीशनर (एनपीजीएन) – स्नातकोत्तर रेजीडेंसी प्रोग्राम) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.11-1/2024-आईएनसी(चार) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय नर्स परिषद (प्रत्यारोपण नर्सिंग में नर्स प्रैक्टीशनर (एनपीटीएन) – स्नातकोत्तर रेजीडेंसी प्रोग्राम) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.11-1/2024-आईएनसी(पांच) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय नर्स परिषद (फोरेंसिक नर्सिंग प्रोग्राम में एम.एससी.) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.11-1/2024-आईएनसी(सात) में प्रकाशित हुए थे।

(23) उपरोक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले छः विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) वर्ष 2025-2026 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2025-2026 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(तीन) वर्ष 2025-2026 के लिए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of External Affairs for the year 2025-2026.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Paradip Port Authority, Paradip Port, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Paradip Port Authority, Paradip Port, for the year 2023-2024, together with audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paradip Port Authority, Paradip Port, for the year 2023-2024.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the audited accounts of the Paradip Port Authority, Paradip Port, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2023-2024.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Mumbai Port Authority, Mumbai, for the year 2023-2024.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2025-2026.

(ii) Defence Services Estimates for the year 2025-2026.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2024-2025.

(ii) Memorandum of Understanding between the Hindustan Aeronautics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2024-2025.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 350 of the Cantonments Act, 2006:-

(i) The Babina Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 182(E) in Gazette of India dated 20th November, 2024.

(ii) The Nainital Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 161(E) in Gazette of India dated 14th November, 2024.

(iii) The Barrackpore Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 183 in Gazette of India dated 20th November, 2024.

(iv) The Badamibagh Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 186(E) in Gazette of India dated 21st November, 2024.

(v) The Kamptee Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 166(E) in Gazette of India dated 18th November, 2024.

(vi) The Pachmarhi Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 159(E) in Gazette of India dated 14th November, 2024.

(vii) The Mhow Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 165(E) in Gazette of India dated 14th November, 2024.

(viii) The Mathura Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 191(E) in Gazette of India dated 21st November, 2024.

(ix) The Aurangabad Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 184(E) in Gazette of India dated 20th November, 2024.

(x) The Bareilly Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 153(E) in Gazette of India dated 13th November, 2024.

(xi) The Almora Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 157(E) in Gazette of India dated 14th November, 2024.

(xii) The Ferozepur Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 180(E) in Gazette of India dated 19th November, 2024.

(xiii) The Jalapahar Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 200(E) in Gazette of India dated 2nd December, 2024.

(xiv) The Roorkee Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 144(E) in Gazette of India dated 12th November, 2024.

(xv) The Jalandhar Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No.

S.R.O. 178(E) in Gazette of India dated 19th November, 2024.

(xvi) The Lansdowne Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 141(E) in Gazette of India dated 11th November, 2024.

(xvii) The Subathu Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 192(E) in Gazette of India dated 21st November, 2024.

(xviii) The Clement Town Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 140(E) in Gazette of India dated 11th November, 2024.

(xix) The Ajmer Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 179(E) in Gazette of India dated 19th November, 2024.

(xx) The Varanasi Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 156(E) in Gazette of India dated 14th November, 2024.

(xxi) The Wellington Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 189(E) in Gazette of India dated 21st November, 2024.

(xxii) The Ahmedabad Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 172(E) in Gazette of India dated 18th November, 2024.

(xxiii) The Lebong Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 176(E) in Gazette of India dated 18th November, 2024.

(xxiv) The Fatehgarh Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No.

S.R.O. 146(E) in Gazette of India dated 12th November, 2024.

(xxv) The Landour Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 163(E) in Gazette of India dated 14th November, 2024.

(xxvi) The Allahabad Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 139(E) in Gazette of India dated 11th November, 2024.

(xxvii) The Agra Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 138(E) in Gazette of India dated 11th November, 2024.

(xxviii) The Dehu Road Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 201(E) in Gazette of India dated 2nd December, 2024.

(xxix) The Dehradun Road Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 145(E) in Gazette of India dated 12th November, 2024.

(xxx) The Kasauli Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 170(E) in Gazette of India dated 18th November, 2024.

(xxxi) The Clement Town Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 104(E) in Gazette of India dated 8th August, 2024.

(xxxii) The Dehradun Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 105(E) in Gazette of India dated 8th August, 2024.

(xxxiii) The Dalhousie Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 79(E) in Gazette of India dated 2nd August, 2024.

(xxxiv) The Jammu Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 89(E) in Gazette of India dated 6th August, 2024.

(xxxv) The Jhansi Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 110(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(xxxvi) The Shahjahanpur Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 148(E) in Gazette of India dated 13th November, 2024.

(xxxvii) The Bakloh Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 164(E) in Gazette of India dated 14th November, 2024.

(xxxviii) The Morar Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 167(E) in Gazette of India dated 18th November, 2024.

(xxxix) The Pune Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 194(E) in Gazette of India dated 22nd November, 2024.

(xl) The Ambala Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 154(E) in Gazette of India dated 13th November, 2024.

(xli) The Chakrata Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 147(E) in Gazette of India dated 12th November, 2024.

(xlii) The Nasirabad Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 158(E) in Gazette of India dated 14th November, 2024.

(xliii) The Danapur Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 137(E) in Gazette of India dated 8th November, 2024.

(xliv) The Jabalpur Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 149(E) in Gazette of India dated 13th November, 2024.

(xlv) The Amritsar Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 151(E) in Gazette of India dated 13th November, 2024.

(xlvi) The Kamptee Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 123(E) in Gazette of India dated 12th August, 2024.

(xlvii) The Ramgarh Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 125(E) in Gazette of India dated 12th August, 2024.

(xlviii) The Mhow Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 91(E) in Gazette of India dated 6th August, 2024.

(xlix) The Ranikhet Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.O. 81(E) in Gazette of India dated 2nd August, 2024.

(L) The Chakrata Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.O. 94(E) in Gazette of India dated 7th August, 2024.

(Li) The Agra Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 87(E) in Gazette of India dated 6th August, 2024.

(Lii) The Bareilly Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 93(E) in Gazette of India dated 7th August, 2024.

(Liii) The Allahabad Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 101(E) in Gazette of India dated 8th August, 2024.

(Liv) The Landour Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 96(E) in Gazette of India dated 7th August, 2024.

(Lv) The Ayodhya Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 92(E) in Gazette of India dated 7th August, 2024.

(Lvi) The Kanpur Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 111(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(Lvii) The Lansdowne Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 100(E) in Gazette of India dated 8th August, 2024.

(Lviii) The St. Thomas Mount cum Pallavaram Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 130(E) in Gazette of India dated 13th August, 2024.

(Lix) The Deolali Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 107(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(Lx) The Meerut Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 86(E) in Gazette of India dated 5th August, 2024.

(Lxi) The Bakloh Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 78(E) in Gazette of India dated 2nd August, 2024.

(Lxii) The Cannanore Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 122(E) in Gazette of India dated 12th August, 2024.

(Lxiii) The Dehuroad Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 106(E) in Gazette of India dated 8th August, 2024.

(Lxiv) The Fatehgarh Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 108(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(Lxv) The Dagshai Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 83(E) in Gazette of India dated 5th August, 2024.

(Lxvi) The Sagar Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 115(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(Lxvii) The Aurangabad Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 120(E) in Gazette of India dated 12th August, 2024.

(Lxviii) The Secunderabad Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 126(E) in Gazette of India dated 12th August, 2024.

(Lxix) The Badamibagh Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 82(E) in Gazette of India dated 2nd August, 2024.

(Lxx) The Shillong Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 116(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(Lxxi) The Ahmednagar Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 118(E) in Gazette of India dated 12th August, 2024.

(Lxxii) The Barrackpore Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 121(E) in Gazette of India dated 12th August, 2024.

(Lxxiii) The Babina Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 127(E) in Gazette of India dated 13th August, 2024.

(Lxxiv) The Danapur Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 88(E) in Gazette of India dated 6th August, 2024.

(Lxxv) The Ajmer Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 119(E) in Gazette of India dated 12th August, 2024.

(Lxxvi) The Ranikhet Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No.

S.R.O. 142(E) in Gazette of India dated 11th November, 2024.

(Lxxvii) The Ramgarh Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 171(E) in Gazette of India dated 18th November, 2024.

(Lxxviii) The Shillong Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 187(E) in Gazette of India dated 21st November, 2024.

(Lxxix) The St. Thomas Mount Cum Pallavaram Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 181(E) in Gazette of India dated 19th November, 2024.

(Lxxx) The Belgaum Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 185(E) in Gazette of India dated 20th November, 2024.

(Lxxxi) The Secunderabad Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 198(E) in Gazette of India dated 2nd December, 2024.

(Lxxxii) The Kasauli Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 84(E) in Gazette of India dated 5th August, 2024.

(Lxxxiii) The Ranikhet Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 80(E) in Gazette of India dated 2nd August, 2024.

(Lxxxiv) The Ambala Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 77(E) in Gazette of India dated 2nd August, 2024.

(Lxxxv) The Pune Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 114(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(Lxxxvi) The Amritsar Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 102(E) in Gazette of India dated 8th August, 2024.

(Lxxxvii) The Jutogh Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 90(E) in Gazette of India dated 6th August, 2024.

(Lxxxviii) The Mathura Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 112(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(Lxxxix) The Ferozpur Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 95(E) in Gazette of India dated 7th August, 2024.

(xc) The Subathu Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 131(E) in Gazette of India dated 13th August, 2024.

(xci) The Kirkee Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 128(E) in Gazette of India dated 13th August, 2024.

(xcii) The Cannanore Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 199(E) in Gazette of India dated 2nd December, 2024.

(xciii) The Sagar Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 193(E) in Gazette of India dated 21st November, 2024.

(xciv) The Dagshai Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 162(E) in Gazette of India dated 14th November, 2024.

(xcv) The Merrut Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 143(E) in Gazette of India dated 12th November, 2024.

(xcvi) The Jammu Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 168(E) in Gazette of India dated 18th November, 2024.

(xcvii) The Ayodhya Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 152(E) in Gazette of India dated 13th November, 2024.

(xcviii) The Delhi Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2023 published in Notification No. S.R.O. 23(E) in Gazette of India dated 22nd September, 2023.

(xcix) The Ahmednagar Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 177(E) in Gazette of India dated 19th November, 2024.

(xc) The Lucknow Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 160(E) in Gazette of India dated 14th November, 2024.

(xci) The Jutogh Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 173(E) in Gazette of India dated 18th November, 2024.

(xcii) The Dalhousie Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 169(E) in Gazette of India dated 18th November, 2024.

(xciii) The Kirkee Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2023 published in Notification No. S.R.O. 174(E) in Gazette of India dated 18th November, 2024.

(xciv) The Ahmedabad Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 117(E) in Gazette of India dated 12th August, 2024.

(cv) The Lucknow Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 85(E) in Gazette of India dated 5th August, 2024.

(cvi) The Jhansi Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 190(E) in Gazette of India dated 21st November, 2024.

(cvii) The Deolali Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 188(E) in Gazette of India dated 21st November, 2024.

(cviii) The Kanpur Cantonment Board Solid Waste Management Bye-laws, 2024 published in Notification No. S.R.O. 150(E) in Gazette of India dated 13th November, 2024.

(cvix) The Varanasi Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 97(E) in Gazette of India dated 8th August, 2024.

(cx) The Morar Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 129(E) in Gazette of India dated 13th August, 2024.

(cxi) The Shahjahanpur Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 98(E) in Gazette of India dated 8th August, 2024.

(cxii) The Pachmarhi Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 113(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(cxiii) The Nasirabad Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 124(E) in Gazette of India dated 12th August, 2024.

(cxiv) The Belgaum Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 103(E) in Gazette of India dated 8th August, 2024.

(cxv) The Jabalpur Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 109(E) in Gazette of India dated 9th August, 2024.

(cxvi) The Roorkee Cantonment Board (Digging and Use of Bore Wells) Regulations, 2024 published in Notification No. S.R.O. 99(E) in Gazette of India dated 8th August, 2024.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI V. SOMANNA): Sir, on behalf of my colleague Shri Ravneet Singh, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the progress made in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion categories on the Railways for the year ending 31st March, 2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under of Section 199 of the Railway Act, 1989:-

(i) The Indian Railways (Open Lines) General (Second Amendment) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 778(E) in Gazette of India dated 23rd December, 2024 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.21(E) (in Hindi version only) dated 7th January, 2025

(ii) The Indian Railways (Open Lines) General (Third Amendment) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 01(E) in Gazette of India dated 1st January, 2025.

(iii) The Kolkata Metro Railway General (First Amendment) Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R. 80(E) in Gazette of India dated 28th January, 2025.

(4) A copy of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 725(E) in Gazette of India dated 19th December, 2024 under sub-section (3) of Section 30 of the Railways Claims Tribunal Act, 1987.

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2023-2024, together with Audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nalanda University, Nalanda, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nalanda University, Nalanda, for the year 2023-2024, together with Audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nalanda University, Nalanda, for the year 2023-2024.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Governing Council of Indian Council of Medical Research

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Hon. Chairperson Sir, I beg to move the following:-

"That in pursuance of rules 1 (xxiv) and 15(ii) of the Rules and Regulations of the Indian Council of Medical Research (ICMR), the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the Governing Council of Indian Council of Medical Research, subject to the other provisions of the said Rules and Regulations."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नियमों के नियम 1 (xxiv) और 15(ii) तथा विनियमों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की शासी परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

MOTION RE: 5TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to move the following:

"That this House do agree with the Fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 6th February, 2025."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 6 फरवरी, 2025 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

(1205/NKL/SK)

ELECTIONS TO COMMITTEES – contd.

(ii) All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Gorakhpur

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Hon. Chairperson Sir, I rise to move the following:-

> "That in pursuance of Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Act, 1956 read with Section 6 of the AIIMS (Amendment) Act, 2012, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Gorakhpur subject to the other provisions of the said Act."

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : प्रश्न यह है:

> "कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के साथ पठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन गोरखपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्रीमती कनिमोझी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं कनिमोझी जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। आप सब लोग बैठ जाइए। पहले आप अपने आसन पर बैठिए। यह चर्चा विदाउट सिटिंग नहीं होगी। यह सदन की मर्यादा है इसलिए आप मर्यादा को बनाए रखें।

… (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, you have given me time to speak. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, you have been given the chance.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: All of you, please be seated in your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, everybody is seated now. Please allow her to speak now. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, everybody should sit first. Some of the Members are still standing.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

Now, hon. Member, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the fishermen from Tamil Nadu are being harassed and arrested by the Sri Lankan Army regularly. … (*Interruptions*) Over 97 fishermen have been arrested and are in Sri Lankan jails. They have been tortured in unbelievable ways. Over 210 boats of the fishermen, which is the basic of their livelihood, have been taken away and nationalised by the Sri Lankan Government. How will our fishermen live? Our Chief Minister has been consistently requesting the Union Government and the hon. Prime Minister to resolve this issue. … (*Interruptions*) But you are not bothered about it. … (*Interruptions*) We want a permanent solution to it. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay. Your concerns will be taken up by the Ministry concerned of the Government of India.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): We want a permanent solution. … (*Interruptions*)

नियम 377 के अधीन मामले– सभा पटल पर रखे गए

1208 बजे

माननीय सभापति : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, सभी माननीय सदस्य अपने अनमुोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने का कष्ट करें।

Re: Need to create 'Divyang Kavach', a mobile application to address the challenges faced by Divyangjan in the country

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): I rise to address the urgent need for technological innovation to support the Divyang (persons with disabilities) community. As India progresses into a digital era, it is imperative that we develop solutions fostering accessibility, safety, and empowerment for persons with disabilities. I propose the creation of a dedicated mobile application, Divyang Kavach, to tackle the unique challenges faced by the Divyang community. Then key features of Divyang Kavach would be to seamlessly link UDID cards for easy identification and access to essential services; incorporate a panic button to alert nearby police stations or emergency services during distress; real-time tracking to provide authorities with precise locations of individuals in need; and enable swift responses by equipping police stations with real-time information on emergencies involving the Divyang community. This app would strengthen safety, enhance self-reliance, and foster inclusivity, while promoting better coordination among administrative bodies. I urge the Government to prioritize such initiatives, aligning with the vision of "Sabka Saath, Sabka Vikas," ensuring that no one is left behind in India's journey toward a more inclusive and equitable society.

(ends)

Re: Need to introduce a mandatory internship progamme for Nursing students to ensure quality healthcare in hospitals

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): I rise to bring to the attention of the House a pressing concern that is affecting the people of Mangalore, particularly those seeking treatment at the Wenlock district Hospital, Mangalore. The hospital is facing a dire shortage of nurses, which is causing significant issues in treating patients. Despite having skilled and experienced doctors, the lack of supportive nursing staff hinders the process of providing quality healthcare to our people. Recent reports have highlighted that several hospitals, particularly in rural India, are struggling to cope with the shortage of nurses, forcing patients to rely on untrained attendants and leading to delays in patient care. To address this critical issue, I urge the Ministry of Health and Family Welfare to request the Nursing Council of India to introduce a mandatory internship program for nursing students similar to the internship mandated under the MBBS course. This program would not only provide hands-on experience to nursing students but also facilitate their equitable distribution across Government hospitals in India, particularly in rural and underserved areas. By introducing such a program, we can ensure that nursing professionals are more evenly distributed, bridging the gap in healthcare delivery and providing quality care to patients across the country.

(ends)

Re: Need to sanction funds for development of Jabalpur as a Smart City

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनन्दन करना चाहूँगा। आपके योग्य नेतृत्व में जबलपुर को स्मार्ट सिटी की सूची में सम्मिलित किया गया, जिसके कारण शहरवासियों को समुचित विकास की जिज्ञासा भी बढ़ी है एवं शहर सहित सम्पूर्ण क्षेत्र में शहर का समुचित विकास के साक्षी बनने का गौरव भी सभी को प्राप्त होने जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, कि "स्मार्ट सिटी" योजना के तहत शहर में योजनाओं का रणनीतिक रूप से चरणबद्ध कार्य होना अभी शेष है, इस योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों सहित अन्य सहायतार्थ योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाये। यह ऐतिहासिक शहर अपने आप में एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है, इसलिए यहाँ इस योजना का समग्र रूप से क्रियान्वयन होना अत्यंत आवश्यक है। टाउन प्लानिंग के अनुरूप एवं अन्य सम्बंधित विकास कार्यों का जल्द ही साकार रूप में संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। सरकार से विनम्र निवेदन है कि "जबलपुर" स्मार्ट सिटी योजना को विस्तारित करते हुए 2 हजार करोड़ रुपये अनुमोदित करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Construction of new railway lines in Gujarat

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया (साबरकांठा) : गुजरात में हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा और मेहसाणा से हदाद, अंबाजी होते हुए माउंट आबू तक नई रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। माता अंबाजी (51 शक्तिपीठों में से एक) और तरंगा हिल स्थित अजितनाथ जैन मंदिर के दर्शन के लिए यात्रा सुगम होगी। बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाणा (गुजरात) और सिरोही (राजस्थान) जिलों के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अहमदाबाद-आबू रोड रेलवे लाइन के लिए यह एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगी। साथ ही क्षेत्रीय कृषि और स्थानीय उत्पादों के परिवहन में तेजी आएगी। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इस परियोजना को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और साथ ही खेड़ब्रह्मा से हदाद तक 22 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन को मंजूरी प्रदान की जाए ताकि साबरकांठा जिले के यात्रियों को माता अंबाजी और माउंट आबू तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिल सके। ये दोनों परियोजनाएँ न केवल यात्रियों की सुविधा और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, बल्कि गुजरात और राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी।

(इति)

Re: Railway related issues of Jalore Parliamentary Constituency

श्री लुम्बा राम (जालौर) : मैं मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर (राजस्थान) के रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण माँगो को सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ – (1) सिरोही जिला केन्द्र को पिण्डवाडा या स्वरूपगंज से बागरा तक नई रेलवे लाइन से जोडा जाए। (2) नवजीवन एक्सप्रेस 12655/12656 का विस्तार जोधपरु तक , चेन्नई अहमदाबाद 22919/22920 का विस्तार हिसार ,सालासर ऐक्सप्रेस 22421/22422 तथा भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस 15623/15624 को गॉधीधाम (क्रमशः वाया जालोर) तक किया जाए। (3) गॉधीधाम से अमृतसर नई ट्रेन (वाया जालौर) चलाने की आवश्यकता है। (4) जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेस (JU JP EXP 22977-78) को जालौर तक विस्तार किया जाए। (5) कोयम्बतूर-भगत की कोठी स्पेशल 06181/82 रेल गाडी को पुनः शुरूकर इसे नियमित किया जाए। (6) पिंडवाडा स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस (12915/12916), गरीबरथ एक्सप्रेस (12215/12216), वन्देभारत एक्सप्रेस 12461/12462 , अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस 19409/10 तथा भगत की कोठी बंगलौर एक्सप्रेस 16507/16508 तथा स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार मेल, आश्रम एक्सप्रेस, गरीबरथ एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। (7) ट्रेन संख्या 19735/36 को जयपुर से अहमदाबाद तक पुनः संचालित किया जाए। (8) डी0एम0यू0 (79437/79438,79431/79432) को आबूरोड से फालना तक विस्तारित किया जाए। (9) स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे लाइन के दोनो तरफ आने जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निमार्ण किया जाए। (10) अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस 19409/10 को दैनिक चलाया जाए।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर की उपरोक्त रेल संबंधी मुद्दों पर शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जायें।

(इति)

Re: Need to resume payment of compensation to farmers whose land was acquired by Army for construction of ditches in 1971 in Reasi Assembly segment in Jammu Parliamentary Constituency

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से यह मांग रखना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू लोकसभा रियासी विधानसभा छम्ब गाँव सामवा से हमीरपुर जिसमे (कमवा, पंच्तुत, पलातन, गरार, सैन्य, हमीरपुर) सभी की जमीने Ditch बनाने के लिए ली गई थी 1971 में आर्मी द्वारा जमीन 2381 कनाल, 1972 से लेकर मुआवजा वहाँ के किसानो को मिलता आ रहा था जो सितम्बर 2012 तक मिलता रहा उसके बाद मुआवजा देना बंद कर दिया गया है सभी गाँव में गरीब किसान रहते है जिनकी रोजी रोटी इसी जमीन से चलती थी अब वो बहुत तंगी से अपना जीवन जीते है उन्हें जल्द से मुआवजा दिया जाय पिछला भी और आगे से सही से मिले जिससे वो किसान अपना गुजर बसर कर सकें।

(इति)

Re: Need to establish a Skill Development University in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कई बार यह कह चुके हैं कि देश का हमारा युवा वर्ग हमारी ताकत है, हमारा धन है। हमारे देश में 65 से 70 प्रतिशत युवा कामकाजी है। अभी तक होता आया था कि पारंपरिक स्नातक कोर्स, परास्नातक कोर्स की पढ़ाई की जाती थी, जो हमारे देश की युवा है वह BA, MA करके भटकते रहते थे, सरकारी नौकरी की तलाश में रहते थे किन्तु अधिकांश को कोई नौकरी नहीं मिलती थी। उनके पास इतना धन भी नहीं होता था कि वह अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि उन्होंने इस बात को समझा और स्किल इंडिया का नारा दिया। उन्होंने कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना की। इस मंत्रालय के अधीन देश में हजारों ऐसे केंद्र खोले गए जहां पर कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन अभी भी कौशल विकास में जो गति मिलनी चाहिए थी वह गति देश पकड़ नहीं पा रहा है क्योंकि जो यह कौशल विकास के छोटे-छोटे केंद्र खुले हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश के अलग-अलग हिस्सों में कौशल विकास विश्व विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

पारंपरिक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश को पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, लोगों के पास लैंड होल्डिंग नहीं है, खेत की कमी है, युवा सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तलाश में रहता है। सरकारी नौकरियां देश में कम होती जा रही हैं इसलिए आवश्यक है कि एक कौशल विकास विश्व विद्यालय गोरखपुर में खोला जाए जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 14, 15 जिलों के साथ-साथ पश्चिमी और उत्तरी बिहार के कई जिलों के छात्र लाभान्वित हो सकते हैं।

पूरे विश्व में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के वर्कफोर्स की बहुत कमी है और यही उचित समय है कि जब हम इस कमी को पूरी कर सकते हैं , लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि युवाओं को व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें इस प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की डिग्री दी जाए। छोटे-छोटे केंद्र सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं लेकिन जो मान्यता डिग्री कोर्स की होती है वो सर्टिफिकेट कोर्स की नहीं होती है।

भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था के विकास में कौशल शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके माध्यम से हमारे विश्व की सबसे युवा शक्ति को दिशा देने में, अपने देश के निर्माण में और विदेशों में भी भारत की छवि उत्कृष्ट बनाने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित यूनिवर्सिटी में अलग-अलग तरह के कोर्स होंगे जिसमें विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमारी यही कहती है कि युवाओं को उनके पसंद के विषय में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, कौशल विकास किया जाए।

भविष्य में होने वाले बदलाव को हमें अभी से भांपना पड़ेगा और उनकी चुनौतियों पर खरा उतरने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता हो गई है। मेरी सरकार से मांग है कि गोरखपुर में कौशल विकास विश्व विद्यालय खोलने पर शीघ्र विचार किया जाए।

(इति)

Re: Need to establish airport in Paradip in Jagatsinghpur Parliamentary Constituency

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Paradip is an industrial hub in Odisha. Many heavy industries, including Paradip port, are operating from Paradip. Two mega steel plants are going to be set up soon. Ministry of Shipping, Ports and Waterways, is going to set up an International Maritime University and a Shipyard factory. Many ancillary, small and medium industries are within the periphery of Paradip town. Paradip port is one of the largest ports in India's coast, which provides direct and indirect employment to lakhs of household. Among others, major countries in Paradip include, Paradip Refinery, Paradip Phosphates Limited, Multi Modal Logistics Park, Container Corporation of India Limited, Paradip Plastic Park Limited, Goa Carbon Ltd., Petroleum Coke Calcination Plant, IFFCO's fertilizer plant, IOCL, BPCL and HPCL Marketing terminals, Cargill's edible oil plant, Skol Breweries Ltd., East Coast Brewery etc. The road distance from Paradip to the nearest airport Bhubaneswar is 120 KM, which takes almost 2.5 hours to reach Paradip. Many executives and officials of these industries/companies located in Paradip are facing logistic difficulties in managing time. Also, there has been a long demand from the public to establish a full-fledge airport in Paradip to connect to major metros and cities in India. In this regard, I would like to draw the attention of the Ministry of Civil Aviation to look into the matter on an urgent basis.

(ends)

Re: Need to provide adequate compensation to the families of persons who have lost their lives due to wild animal attacks

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : समग्र देश में मानव-वन्य प्राणी संघर्ष (Human-Animal conflict) अब बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि इसका कारण जलवायु परिवर्तन ही है यह भी कहा जा सकता है कि व्यापक औद्योगिकीरण के कारण भी मानव-वन्य प्राणी संघर्ष बढ़ रहा है। मेरे लोकसभा क्षेत्र ढेंकानाल विशेषकर उड़ीसा के दो जिले ढेंकानाल और अंगुल में पिछले चार वर्षों में 31 हाथियों की मृत्यु हुई है जबकि 162 लोगों की हाथी आक्रमण से मृत्यु हुई है।अन्य वन्य प्राणियों द्वारा भी जनजीवन के नुकसान के साथ-साथ फसल की भी हानि व्यापक पैमाने पर होती है। हाथियों के आक्रमण से लोग भी अनेक स्थान पर अपंग हो जाते हैं, अधमरे हो जाते हैं। गंभीर रूप से घायलों की चिकित्सा भी बहुत महंगी होती है। अधमरे लोगों का आगे का जीवन यापन भी बहुत ही कष्टकर हो जाता है। अत: मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि हाथी तथा अन्य वन्य प्राणी आक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को वर्तमान से अधिक आर्थिक राशि की सहायता प्रदान की जाए। गंभीर रूप से घायलों की चिकित्सा का पूरा खर्च सरकार उठाए। साथ-साथ उनके आगे के जीवन यापन हेतु भी सरकार गहराई से सोचे। मेरे विचार से फसल हानि का भी जो मुआवजा दिया जाता है वह कतई पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकारों को भी इस संबंध में अधिक संवेदनशील होने हेतु कहा जाए। दोनों सरकार मिलकर इस दृष्टि से कदम उठाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। अभ्यारण (Sanctuary) को लेकर जो कठोर कानून है, वे भी थोड़ा नरम किए जाएं, ऐसी भी मेरी प्रार्थना है।

(इति)

Re: Need to set up a Special Investigation Team to investigate into illegal mining operations in Assam

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): On January 6, 2025, 10 coal mine workers were trapped in an illegal rat-hole coal mine in the Dima Hasao district of Assam after water inundated the mine, causing a collapse and flooding the narrow tunnels. Four bodies have been recovered since then in the rescue operations. Illegal rat-hole mining in Assam has persisted despite being banned by the National Green Tribunal in 2014. The 2021 Justice Katakey report highlighted that inadequate law enforcement, corruption, and lack of accountability enable illegal mining activities in Assam. Despite Government awareness, local authorities' complicity and failure to take action have led to numerous fatal accidents and ongoing environmental damage. Moreover, Karbi Anglong and Tinsukia continue to see rampant mining. Despite the gravity of the situation, no Minister or Government official has been found guilty of dereliction of duty. The Union Government must form a Special Investigation Team (SIT) to thoroughly investigate the illegal operation of mines, the failure to enforce mining bans, compliance with safety conditions, and the complicity of local authorities.

(ends)

Re: Need to increase salaries for doctors and allied staff of AYUSH

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): AYUSH doctors and allied staff in Government hospitals of India continue to be underpaid, despite being eligible for pay equal to allopathy sector. There is a huge gap in budget allocation for AYUSH and allopathic medicine. The Government is also aware of the fact that although people are turning towards allopathy, many still prefer Ayurveda and homeopathy medication. The Supreme Court in 2021 had ruled that allopathy and Ayush doctors working at Government hospitals are entitled to equal pay, and if there is discrimination in pay, then it's a violation of right to equality under Article 14. Modern medicine and Ayush medicine are different streams, but their ultimate goal is the same. All doctors are professionals, and on the field nobody is inferior or superior. The pay scales in the AYUSH sector have been stagnant for the last 6 years. Hence, I request the Central Government to consider increasing the salaries for all the posts like doctors, nurses, technicians, attendants, pharmacists, therapists, care-takers, field assistants, sanitation workers etc. in AYUSH.

(ends)

Re: Need to universalize the HPV Vaccine to fight cervical cancer effectively in the country

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAGAON): Last year, the Finance Minister in her interim budget speech, spoke of fighting cervical cancer by encouraging the HPV vaccine amongst girls. However, the Government still hasn't included it in the universal immunisation programme. Cervical cancer is the second most common cancer amongst women in India, with the Northeast suffering heavily. Only 1.2% of Indian women have been screened for cervical cancer according to NFHS-5, with 6 Northeastern states recording far below average screening levels. Many sites from the National Cancer Registry with the highest incidence rates like Arunachal's Papumpare district are in the Northeast. A Lancet study of 11 registries showed that survival rates after 5 years in the region are amongst the lowest in the country - low as 31% in Tripura, reflecting late detection and treatment due to inadequate awareness and facilities. I thus urge the Government to universalise the HPV vaccine - the Northeast will benefit immensely.

(ends)

Re: Need to expedite disposal of insurance claims pertaining to Kharif Season 2023

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू के किसानों के द्वारा खरीफ 2023 के लंबित बीमा क्लेम को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही हैं | खरीफ 2023 के बीमा क्लेम पर बीमा कंपनियों द्वारा लगाई गई आपतियों के निपटारे के लिए राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा SGRC का गठन कर बीमा क्लेम के मुद्दे का निपटारा किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन आज दिनांक तक SGRC के द्वारा इस पर अभी तक कोई निर्णय नही किया गया हैं | जिसके कारण क्षेत्र के किसानों में भारी असंतोष हैं व किसानों के द्वारा आगामी समय में धरना प्रदर्शन किये जाने का विचार हैं | राज्य सरकार कि SGRC के द्वारा लगातार किसानों के साथ कुठाराघात किया जा रहा हैं | अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्र के किसानों की इस उचित मांग को देखते हुए खरीफ 2023 के बीमा क्लेम के निपटारे हेतु जल्द से जल्द राजस्थान सरकार को निर्देशित किया जाय कि राजस्थान सरकार द्वारा गठित SGRC द्वारा इस मुद्दे पर विचार कर किसान हित में निर्णय किया जाते हुए क्षेत्र के किसानों को खरीफ 2023 का बीमा क्लेम जल्द से जल्द जारी किया जाये।

(इति)

Re: Decline in Hajj Pilgrims choosing Khozhikode embarkation point amid soaring costs

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): The number of Hajj pilgrims choosing the Kozhikode embarkation point has significantly decreased due to rising costs. Last year, there were 10,051 pilgrims from Kerala, while this year, 15,231 pilgrims were selected through the Hajj Committee. Among these, 4,026 chose Kannur and 5,422 opted for Kochi.

Kozhikode's charges are approximately Rs 40,000 higher than those at other embarkation points. This fare disparity became apparent after the tendering process for Hajj flight services was completed. The Hajj Committee quoted a fare of Rs 1.24 lakh from Kozhikode, whereas the costs from Kannur and Kochi stood at just Rs 86,000. Many pilgrims have criticized the Kozhikode fares as excessive.

In contrast, private Hajj groups operating from Kozhikode reportedly charge significantly less. Even with connecting flights or direct services, the maximum cost for a return ticket to Saudi Arabia is around Rs 75,000. Hence, I urge the Government of India to rectify this anomaly as early as possible.

(ends)

Re: Need to enhance budgetary allocation under MGNREGS and ensure its effective implementation

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): The MGNREGA scheme is not being effectively extended to everyone and depriving people from their fundamental right to work because of a series of harmful decisions. A recent visit to my Parliamentary Constituency highlighted the detrimental impact of these actions. The scheme did not receive any additional budgetary allocation in the revised estimates for 2024-25, despite the Ministry of Rural Development being short of Rs.4,000 crores for wages. MGNREGA mandates that wages be disbursed within a week - or at most a fortnight - after work is completed. Yet, many workers are still waiting for wages after over five weeks, largely due to the poorly implemented Aadhar Payment Bridge System (APBS). The Centre owes over Rs.5,000 crore for material components, limiting the number of projects that can be undertaken. New rules also prevent adding new works to the recognized projects under the Scheme until the end of the 5-year term, almost restricting many of the usual works taken up, practically reducing the persondays. As a result, many workers have been left without opportunities, leading to a drastic decline in overall persondays. I urge the Union Government to increase the budget allocation for MGNREGA, remove restrictions on the works that can be undertaken, and pay the workers on time.

(ends)

Re: Implementation of Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana in Uttar Pradesh

श्री देवेश शाक्य (एटा) : क्या माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में यह देखा गया है कि इस योजना के अंतर्गत जो जिलेवार विशेषज्ञ बनाए गए हैं, वह न तो जो नियम है उसके आधार पर बनाए गए हैं, ना ही जिस जाति के लिए यह योजना है, उस जाति के हैं। तो वह इस योजना के लाभार्थियों को चिन्हित कैसे कर सकते हैं? इस संबंध में लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए देश के साथ साथ विशेषकर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद में विशेषज्ञों को बनाने में तयशुदा मानको को पूरा किया गया है क्या? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसमें दोषियों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है?

(इति)

Re: Construction of rail over bridge at Vembadithalam railway station in Tamil Nadu

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): The narrow rail underpass near Vembadithalam Railway Station is causing heavy vehicular traffic as well as creating frequent road accidents. This road which has an underpass at Vembadithalam connects Chennai-Kochi National Highway resulting into heavy movement of road traffic. Apart from that, there are many textile hubs situated in and around Vembadithalam like Edanganasalai, Illampilai , etc. The said rail underpass is a narrow one, it takes hours for the road commuters to reach their destinations although it is a one-way path. It has been a long pending demand to have a road over bridge at said rail underpass to reduce the ever-increasing vehicular traffic as well as to prevent road accidents. The textile units situated over there are finding it very difficult to move out their produce as well as to bring in raw materials. The woes of a common man using the said rail underpass are plenty; their remedy is to have a rail over bridge. The people are finding it difficult to reach hospitals in emergencies to save their near and dear. Therefore, it is urged that the Government may immediately take up this issue and construct a road over bridge at Vembadithalam very urgently.

(ends)

Re: Desiltation of Kosi Riverbed

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी में प्रत्येक साल बरसात के समय भारी बाढ़ आती है। पानी के साथ इतना मिट्टी (गाद) रहता है कि नदी का सतह उँचा होने के साथ किसानों के खेतों मे भी प्रत्येक वर्ष 3 से 4 फीट मिट्टी का सतह भी ऊँची हो जाती है। नदी में तो इतना सिलटेसन हो गया है कि कम बाढ़ आने पर भी दोनों तटबंध पर टूटने का खतरा मंडराने लगता है। इसी वर्ष नेपाल क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण भीमनगर बैराज से लगभग 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए सभी फाटक खोल दिए गए। एक रात में ही प्रभावित क्षेत्रों के घरों में 5 से 6 फीट पानी आ गया। यदि पश्चिमी तटबंध नहीं टूटता तो भारी जान-माल की क्षति होती। कोसी नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इस कारण गाद निकालने पर पूर्ण रोक है। यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी उस गाद को निकालकर घर दरवाजा भी ऊँचा नहीं कर सकते है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि एक योजना बनाकर कोसी नदी का सतह नीचे रखने के लिए मिट्टी (गाद) निकाली जाय। जिससे बाढ़ का पानी भी सुगमता से निकल सकें।

(इति)

Re: Need to include places in Ramayan circuit associated with Bhagwan Shri Ram in Maharashtra

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख पुराणों में हुआ है। भगवान श्रीराम ने अपनी यात्रा में महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया और इस दौरान वे अकोला के अगस्त्य आश्रम भी गए। इसके अलावा भगवान श्रीराम ने कोपर गांव के पास गोदावरी नदी में अपने पूज्य पिता श्री दशरथ का श्राद्ध किया था और सीताहरण के बाद नासिक में आए थे। जटायु ने उन्हें बताया था कि रावण ने सीता का हरण किया है। भगवान श्रीराम ने अयोध्या जाने के दौरान तीन बार अकोला में अगस्त्य ऋषि के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया था अगस्त्यमुनि के दिए गए बाण से ही भगवान श्रीराम ने महापंडित महाज्ञानी रावण का वध किया था। महाराष्ट्र के उपरोक्त सभी स्थलों के साथ कई स्थलों का महत्त्व रामायण से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के रूप में है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि शिरडी संसदीय क्षेत्र के साथ ही महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण स्थलों को रामायण सर्किट स्कीम में शामिल किया जाए और इस संदर्भ में एक समिति का गठन कर महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र स्थलों का सर्वेक्षण करें और उन्हें रामायण सर्किट स्कीम में शामिल करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(इति)

Re: Terms and conditions of Optional Travel Insurance for E-Ticket passengers of IRCTC

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ई-टिकट बुक करने वाले कन्फर्म/आरएसी रेलवे यात्रियों के लिए 01.09.2016 से एक निश्चित राशि प्रति यात्री के प्रीमियम पर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना शुरू हुई। इस योजना के तहत, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 और 124ए के साथ धारा 123 के तहत परिभाषित ट्रेन दुर्घटना/अप्रिय घटनाओं के कारण आरक्षित यात्रियों की मृत्यु/चोट लगने की स्थिति में पीड़ित/परिवार या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को बीमा राशि का भुगतान किया जाता है, बीमा कंपनी द्वारा वह यात्री को या उनके वारिस को बीमा कंपनी से २ से १० लाख रूपये की राशि मिलती है, जबकि यह बीमा राशि तभी मिलती है बशर्ते कि कवरेज प्रारंभिक स्टेशन से ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से लेकर गंतव्य स्टेशन पर ट्रेन के वास्तविक आगमन तक वैध होगा, जिसमें ट्रेन में चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया भी शामिल है। जबकि रेलगाड़ी अपने समय से नहीं चल पाती है और कोई भी दुर्घटना होने पर यह बीमा राशि नहीं मिलती है। अतः मेरी मांग है कि किसी भी यात्री का बीमा ट्रेन के चलने से गंतव्य तक पहुचने मे कवर होना चाहिए, चाहे रेलगाड़ी अपने तय समय से देर से चले या पहुंचे।

(इति)

Re: Need to restore train services stopped during Covid period in Bijnore Parliamentary Constituency

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : मेरे संसदीय क्षेत्र बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत पुरकाजी विधान सभा के रोहाना कला स्टेशन पर सन 1940 से संचालित रेलगाड़ियों का ठहराव होता था जो कोरोना काल के पश्चात से लंबित है, जिसके कारण आम जन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अत: मैं माननीय रेलमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि दिल्ली-अंबाला गाड़ी संख्या – 14521/22, साबरमती-ऋषिकेश (गाड़ी संख्या 19031/32), दिल्ली- हरिद्वार (गाड़ी संख्या – 14303/04) के बीच चलने वाली उपरोक्त रेलगाड़ियो का ठहराव रोहाना कला स्टेशन पर पूर्व की भांति करने की कृपा करें। इससे लाखों की संख्या में आमजनों को लाभ होगा। इसके साथ ही एक नई एक्सप्रेस ट्रेन कोटद्वार से नई दिल्ली तक चलाई जाए। कोटद्वार से नई दिल्ली मार्ग पर लगभग 50 लाख की आबादी का प्रतिदिन अपने काम से आना जाना रहता है। यह एक्सप्रेस ट्रेन कोटद्वार से नजीबाबाद , मौजमपुर, किरतपुर, बिजनौर, हल्दौर, चांदपुर, घरौना मंडी, गजरौला, जंक्शन होते हुए हापुड़, गाजियाबाद शाहदरा दिल्ली को पहुँचेगी। इस एक्सप्रेस ट्रेन को भी जनहित हेतु चलाया जाना अति आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र के चंदक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या- 13152/ 13151 का ठहराव भी कोरोना काल के पश्चात से बंद है व सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन संख्या 54251/54252 भी करोना काल से पश्चात से बंद है।

अत: आपसे आग्रह है की इन उपरोक्त ट्रेनों को संचालित करने का कष्ट करें। बिजनौर लोकसभा की जनता आपकी सदा आभारी रहेगी।

(इति)

Re: Need to run Amrit Bharat Express trains from Sealdah to Saharsa and from Purnia Junction to New Delhi

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : केन्द्रीय सरकार देश भर में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है, इस ट्रेन के कोच का निर्माण यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सीसीटीवी कैमरे, बायो वैक्यूम शौचालय, सेंसर आधारित पानी के नल, एलईडीलाइट्स और बेहतर लगेज रैक की सुविधा होगी। मै कोशी-सीमांचल क्षेत्र की जनता के लिए दो मुख्य अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेने चलाने की माँग करता हूँ। जो निम्नवत है:- 1. सियालदह से वाया कटिहार-पूर्णिया ज०- मधेपुरा- सहरसा तक। 2. पूर्णिया ज० से वाया पूर्णिया कोर्ट-बनमनखी- मुरलीगंज- मधेपुरा- सहरसा- नई दिल्ली तक।

(इति)

केन्द्रीय बजट – सामान्य चर्चा

1208 बजे

माननीय सभापति : आइटम नंबर 16 – केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा।

डॉ. धर्मवीर गांधी जी।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: All of you, please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Dharamvira Gandhi ji, please start.

… (*Interruptions*)

1208 hours

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Thank you, Sir, for allowing me to speak on the Union Budget. I am thankful to the Chair as well as to my Party for allowing me to stand before you and before the country to give my comments on the Union Budget for 2025-26.

Sir, before I start giving my regular comments on the Budget, I would like to raise a basic question. India is a Union of States. This simply means that it is not our country, India, which has carved out States but it means that it is the States like Punjab, Maharashtra, Tamil Nadu, or West Bengal, which submerged their identities and made this country. It is we, who have made India, and not that India has carved out the States. So, the States are primary. Our Constitution makers and our forefathers have rightly said that this is a Union of States. So, I would like to say that the entire Budget-making process and the Budget itself is unitary in nature and not federal. The States have either little or practically no say in making the Budget, and the spirit of the Constitution is being trampled year after year by the budgetary process. … (*Interruptions*) So, if we look at the overall scenario, the States are primary. … (*Interruptions*)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, the Finance Minister is not present in the House … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The MoS is sitting here.

… (*Interruptions*)

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): India is a diverse country. … (*Interruptions*) India is a country of different identities like religious, cultural, linguistic. … (*Interruptions*)

(1210/VR/KN)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, the Finance Minister is not present in the House. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Venugopal ji, please sit down. The hon. MoS for Finance is sitting here. He is capable. Please allow the hon. Member to speak.

Dr. Dharamvira ji, please continue your speech.

....(Interruptions)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): This is not a good practice. *....(Interruptions)* Let the hon. Finance Minister come to the House. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Venugopal ji and Gaurav ji please sit down.

....(Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I just want to inform that MoS is here. I will inform the hon. Finance Minister. *....(Interruptions)* You have raised your points. *....(Interruptions)*

Yesterday also, the Finance Minister came and waited. But the House was disrupted. *....(Interruptions)* The Finance Minister was always here. You had disrupted the House. *....(Interruptions)* You have raised this issue just now. I will convey this to the Finance Minister. In the meantime, let the discussion continue. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, please hear the hon. Minister.

....(Interruptions)

श्री किरेन रिजिजू : यह क्या बात है? … (व्यवधान) ये आवाज उठाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। … (व्यवधान) I

Sir, I am again informing this House that the Finance Minister was ready from the beginning. *....(Interruptions)* But because of disruption in the House yesterday, the discussion could not be taken up. *....(Interruptions)* Now, the House is ready to take up the discussion. *....(Interruptions)* I will inform the hon. Finance Minister. In the meanwhile, my only request is that as the hon. MoS is sitting here, let the discussion begin. *....(Interruptions)* I will inform the hon. Finance Minister. What is wrong in that? *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: I have one thing to say to all the hon. Members. Venugopal ji, you are a very senior Member of the House. There is no such rule that the Finance Minister should be present in the discussion. There is no such rule. This is a convention only.

The hon. Minister has already answered your concerns. I would request Dr. Gandhi ji to continue his speech.

....(Interruptions)

1214 hours

(At this stage, Shri Shafi Parambil came and stood near the Table)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, Dr. Gandhi ji, please continue your speech.

....(Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य धर्मवीर गांधी जी, अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो आपको बाद में बुलवायेंगे। गांधी जी, क्या आप नहीं बोलेंगे?

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The next hon. Member to speak is Shri Rao Rajendra Singh ji. गांधी जी, आपको बाद में मौका मिलेगा।

… (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, धन्यवाद। … (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): What is this, Sir? *....(Interruptions)* You cannot do this. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: He will be given a chance later.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Okay. Hon. Members, please sit down.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Venugopal ji, please raise your concern in 30 seconds.

....(Interruptions)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): You cannot bulldoze this. *....(Interruptions)* Where is the Finance Minister? *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Venugopal ji, please speak.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I am allowing Shri Venugopal ji to raise his concern. He is a senior Member of the House.

....(Interruptions)

1215 hours

(At this stage, Shri Shafi Parambil went back to his seat.)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, with due respect to the Chair, I would like to bring this to your notice. There are conventions in this Parliament. Whenever the Budget discussion is initiated in the House, I am stressing the word 'initiated', the hon. Finance Minister who presented the Budget should be there in the House. *....(Interruptions)*

(1215/SNT/VB)

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): This is a convention. This is not a rule.

… (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : माननीय सभापति जी, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी भी यहाँ पर हैं।… (व्यवधान) जब हम भी विपक्ष में थे तब भी यूपीए की सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहते थे, उस समय भी हम भाषण करते रहते थे।… (व्यवधान) इनके पास तर्कों की कमी है, इनके पास बात रखने की कमी है।… (व्यवधान) इसलिए इनको रोज़ हल्ला करने की आदत बन गई है। कल पूरा दिन वित्त मंत्री जी यहाँ पर थीं… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Dharamvira Gandhi ji, please start.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dharamvira Gandhi ji, please continue.

… (*Interruptions*)

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Thank you, Sir, for allowing me to speak.

HON. CHAIRPERSON: I have given my ruling that there is no such type of rule that the Finance Minister should be present. Yes, you are right that there is a convention that the Finance Minister should be present but she will come later on. Our hon. MoS, Finance is capable enough. He is sitting here.

… (*Interruptions*)

1217 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आपकी भावनाएं ठीक हैं। मैं इन्श्योर करूँगा कि भविष्य में पहले वक्ता के भाषण के समय माननीय मंत्री जी रहेंगे।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं सत्ता पक्ष के मेम्बर को बोलने के लिए बुलाता हूँ।

… (<u>व्यवधान</u>)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, whenever the Budget discussion is initiated, the hon. Finance Minister is present. The Finance Minister presented the Budget. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने चेयर से एन्श्योर कर दिया है। यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं।

… (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : सर, आप दो-तीन ज़ीरो ऑवर के मुद्दे ले लें।… (व्यवधान)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, this is not the first time. She is making a habit of not coming here when the discussion is being initiated. This is not done. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने एंश्योर कर दिया है। दयानिधि मारन जी, यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं और कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए यह कहीं पर रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं लिखा है कि कैबिनेट मंत्री रहें। हम नियम-प्रक्रियाओं से चलते हैं। नियम-प्रक्रियाओं में राज्य मंत्री का साथ में रहना इन्श्योर्ड है। यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री बैठे हुए हैं।

… (व्यवधान)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, this is a very important discussion.

माननीय अध्यक्ष : मैंने एन्श्योर कर दिया है, प्लीज।

… (व्यवधान)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, you are the protector. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): She is disrespecting us. This is not fair. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, जितनी कैबिनेट मंत्री की है। यह नियम और प्रक्रियाओं में कहीं भी नहीं लिखा है। ये परम्पराएं हैं। परम्पराओं का हम लोग पालन कर रहे हैं। यह अलग बात है। लेकिन आप इस विषय पर डिबेट मत कीजिए। इस विषय पर आप डिबेट मत कीजिए, मिस्टर। आप सीनियर मंत्री रहे हैं। आप इस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, this is not fair. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : राज्य मंत्री के रहते हुए भी, कई बार सदन में चर्चा हुई है। इसलिए आप इस पर डिबेट मत करिए। आप रूल-रेगुलेशन से चलेंगे, तो हम भी रूल-रेगुलेशन से चलेंगे। मैं आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं एन्श्योर कर रहा हूँ। मेरे पास 25 उदाहरण हैं।

… (व्यवधान)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, let me make my point to you. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपकी बात सुन ली है।

… (व्यवधान)

THIRU DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, with all due respect, you are being a very fair Speaker. You have been protecting us. But this has been a practice of the Finance Minister of not being present whenever the discussion is being initiated. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज बैठिए, माननीय वित्त मंत्री जी आ गई हैं।

… (व्यवधान)

(1220/AK/PC)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, if the Speaker is giving the assurance that this will not happen in the future, then we are ready. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. धर्मवीर गांधी जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है। प्लीज़, आप बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको नहीं बोलना है?

… (व्यवधान)

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Thank you, Sir. I am going to speak on the Budget. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : हां, मैंने आपका नाम लिया था। आपने बैठे-बैठे टिप्पणी की थी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य को खड़ा करने का आपको अधिकार नहीं है। यह आपका काम नहीं है। यह मेरा अधिकार है, मैं किसको बोलने दूं, किसको न बोलने दूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. धर्मवीर गांधी जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Budget 2025-2026. I also thank my Party for giving me this opportunity.

At the outset, before I go for my regular comments on the Budget, I would like to address a basic question that India, as per our Constitution, is a union of States, and the Budget itself and the entire budgetary process is not federal in nature. … (*Interruptions*) It is unitary in nature and the States have neither been consulted exhaustively nor are allowed to participate in the Budget-making process. So, this is anti-federal. This is against the spirit of federalism and spirit of the Constitution.

1221 hours (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

Here, I would like to say that India, our country, is not an India that carved out States out of it like Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu or West Bengal. Instead, it is the States that submerged their identities and made this country. So, in the Budget-making process this entire concept of a federal structure is being mitigated; is being destroyed; and not being taken into consideration. The Budget is unitary in nature. You are homogenising the country.

Every State has its own problems; its own specificities; and its own particularities in education, health, and even the disease patterns are different in many States. They have their own needs and priorities which are never taken into consideration. They are never consulted, and the Budget is made by sitting in the room, and the States are not exhaustively consulted in making the Budget. This is my first contention on this Budget stating thereby that it is unitary in nature and not federal.

Secondly, this Budget is not just a question of data here and there or some promises here and there. It is about the nature as to how the present Government is going to mobilise or going to use our resources to benefit the people of India and to benefit the entire population.

I am coming back to the issue of federal character. I would like to ask this. Where is the entire GDP produced? It is in the States. Where are the entire resources of the country located? It is in the States. Where does the best innovation take place? It is in the States again. But when it comes to the Budget, nobody bothers about the concerns of the States. A country is not just a geographical entity, but a country means the geographical country itself; a

country means the resources of the country; and a country means most importantly the most livid part of it, that is, the people of the country -- 142 crore people of India. So, Budget means that it should be directed in a way so that the people of the country are given the benefits of the natural resources, their sufferings are mitigated, and their income is commensurate to the modern level of economic and human development in the world. So, I will comment on this Budget from this perspective.

I believe that Budget is one that guarantees work for every hand; that guarantees education for every child; that guarantees standard healthcare for every family; and that guarantees a farmer in a field or a worker in the factory or an entrepreneur in a small town or a student in a remote village finds hope and opportunity.

(1225/UB/CS)

In this context and under these broad considerations and parameters, which include inclusive growth, sustainable development and future where fruits of development and prosperity are shared by all.

Let me now come to agriculture. In spite of the fact that a major part of GDP in 2025 comes from either manufacturing or from the service sector and only 15 per cent is contributed by the agrarian sector, but the fact of the matter is that agriculture still remains the employer for 45 per cent of the population; almost half of the population relies on agriculture for their livelihood. This sector has been neglected very badly, not only in the past years but even in this Budget and this Government has little to offer to the farmers and the farming community or the labour community of this country in this Budget.

The present regime has a very skewed approach towards the farming community. On the other hand, the policies are made in favour of the few mega corporate houses. Therefore, it did not offer any relief to the farmers in regard to the legal guarantee on MSP, waiving off loans of farmers and the farming labourers. The Government is not lifting or withdrawing GST from the farming equipment and machinery and not giving a robust farm insurance or crop insurance scheme in the Budget. So, it has totally failed to address the grievances of our farming community.

There is a lot of unrest all over the country, which is evident from the ongoing agitations all over the country, and thousands of farmers are committing

suicide every year across the country. Farming has become unsustainable and unreliable. It is an unprofitable proposition. More and more people are going out of farming and there is no corresponding industrial growth to absorb this surplus workforce because the Government has not paid any attention to the development of MSME sectors which can create jobs for the people who are leaving farming. There has been an all-time high unemployment for the last 60 years in the country. It is a result of this gross unemployment situation that the sons and daughters of Punjab farmers, Haryana farmers or western UP farmers are going to greener pastures at the cost of their lives, and they are being humiliated the way they were sent back to Amritsar airport in the most humiliating and insulting manner.

That shows that this Government, which promised two crore jobs every year, has failed on this front very badly and the youth of the country is in the total dark with total hopelessness, and they are compelled to leave their homes, their land, their parents and go thousands of kilometres away to earn their livelihood. It is happening because of this Government's ... (*Expunged as ordered by the Chair*) neglect towards the farming sector. In spite of the fact that a long agitation took place where 800 farmers lost their lives, it did not concern our hon. Finance Minister to give any relief to the farmers. It did not even pay a proper lip service.

What the Government did was that it promised some sums like increasing loan limits without promising any real help to the farmer who is already indebted to the unsustainable level. It is nothing less than rubbing salt on the wounds when it talks of "building rural prosperity and resilience" by scaling investment and bringing newer global technologies. This is a plan more for big agro-corporations and companies like Amazon and Google and less for the debt-ridden Indian farmers.

(1230/GM/IND)

Sir, there are no provisions for the agro-based and value-adding industry in the regions of green revolution to capture global market as is being done by China, Israel and many Scandinavian countries. There are no budgetary plans to mitigate the suffering of rural India. So, this Budget on the agrarian front is a total trash, total failure and does not represent the aspirations of farmers who are the majority of our Indian population.

Sir, as I already told you, because of the anti-farmer policies of the present Government, thousands of farmers are committing suicide every year. Further, because of farming being unsustainable and not a profitable profession, the farmers are leaving their land and they are not finding any suitable employment in the industry because industrial development is very sluggish and MSME sector is not developing at the pace where the surplus force from the farming sector can be absorbed. The growth there is abysmal, rather negative. So, it is a great crisis our farming community has landed into because of the continuous neglect of this sector for the last 10 years.

Sir, let me talk on the micro, small and medium enterprises. MSMEs are the backbone of economy in a country like India which is very thickly populated. It can only be the small and medium scale industry which is labour-intensive. In the corporate sector, there are factories worth Rs.10,000 crore, there are machines and computers only, there are assembly lines, etc. Companies worth Rs.10,000 crore generate 500 jobs whereas there are jobs in Ludhiana in Punjab, in Kanpur in UP and in hundreds of such towns and cities across the country where MSME sector has been continuously neglected at the cost of a few mega corporates and which is dying gradually. In 2024 only, 19828 MSME units were forced to close down because of this financial mismanagement and misplaced priority of the Government. The Congress, during its rule, had championed the cause of small businesses. It introduced priority lending to the MSME and a robust rural banking system, which the BJP has failed to sustain. The Budget has precious little to offer for reviving MSME sector, and through this, reviving the economy.

Coming on to education, health and education are two basic needs of every individual born on this earth, born in any country. If we talk of education, the Right to Education is a fundamental right of every child. I must emphasize here that education does not mean just knowing how to read and write. Education means full-blown development of mental faculties of a person. It is not just primary or secondary education. So, this aspect is being ... (*Expunged as ordered by the Chair*) ignored on which lies the foundation of new India.

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Again, this word ... (*Expunged as ordered by the Chair*) should be expunged.

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Why is the Government not spending enough on education as compared to US, China and other advanced economies? There is a continuous neglect. States are not consulted; their specific needs are not being addressed, and over the years, the Government, it seems, is running away from its responsibility to impart standard education to its children, to its citizens. Because of this utter failure of the Government, there is mushrooming of private institutions from schools to colleges to universities, from medical to engineering institutions, and which has rendered education very costly and students don't have to access to these costly institutions. Not only for the poor and underprivileged, but have become unapproachable or unaffordable for various sections of the middle class also.

(1235/SRG/RV)

So, it is not the poor and the underprivileged, but even the middle classes cannot afford the private education of medical or engineering universities and colleges. So, here the Government did not make enough efforts to expand the budget, to increase the budget on education in a significant way, so that the problem of young India can be addressed too. This is in sharp contrast to our times when primary to university education was within very much the reach of almost all sections of the society.

On research and analysis, again, which is linked to education and development, I will say that a very paltry sum of budget is allotted to research and development in the key sectors and in the important sectors like new technologies, which is 0.64 per cent of GDP, significantly lower than China, Israel and other advanced countries.

The private sector is not doing enough to augment the development story of India. I know very well, I was a young man, when our corporate sector, Tata, for example, did wonders for the development of the country. Nobody invests in fundamental sciences. Tata built the Tata Institute of Fundamental Research, Tata Cancer Research Institute, Tata Institute of Social Sciences and many other institutions of world standard to augment India's progress and to take further the story of developing India. But in the last 10 years, no corporate sector has invested significantly in R&D or in the development of standard institutions of engineering technology and other new technologies to take India forward. So, this is a sad story.

I do not know why Governments have special attraction towards certain corporate houses and why those corporate houses are not investing enough to take India forward on the way to the recovery of the economy and take India forward and put it in the race for an advanced economy. It really disturbs me because the private sector in India is only contributing 36 per cent to R&D, whereas Japan is contributing 70 per cent or even more than 75 per cent to the R&D sector, whereas our corporates are doing little on this account also. So, the profit-oriented private institutions in the education sector are not only exploiting students and their parents, they are exploiting the teaching community also. The teachers from university to college level are not only very low paid, but the very respected and revered profession of teaching is being mocked at by giving them either this *theka*-type system or contract system, which is not to the standard of teacher community. So, teachers have become like daily wage workers, which is a *… (Not recorded)* on all of us, on this Government and on this country.

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Please remove the word *… (Not recorded)* from the record.

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): That is teachers are not being given proper pay so that they can devote all their time to their profession and they can take the country forward. Moreover, the ongoing education system does not invoke the sense of reason, inquiry, inquisitiveness and scientific temper in our children. It does not fully unleash their creative and innovative potential.

Finally, I come to health. Madam Finance Minister, WHO long back gave a very great definition of health, very fine and very, very accurate definition of health. It states, and I quote, 'health is not mere absence of disease or infirmity. It is a state of complete physical, social and psychological well-being.' So, looking at all the three parameters of health, if I talk of physical health, the problem of India is so, so great. We are slipping deeply into a big problem. Because of chronic hunger, because of poverty, because of malnutrition, because of communicable diseases like TB, water-borne diseases like gastroenteritis, dehydration and many other of the sort, lakhs of people die every year.

(1240/RCP/GG)

On the one hand, people are dying from communicable diseases, water-borne diseases, and on the other hand, a small population is dying from lifestyle diseases like hypertension, diabetes, heart attack, dyslipidaemia, etc. So, on the physical front, we are practically poor because of malnutrition, because of communicable diseases and because of water-borne diseases and – randomly affluent sections – because of lifestyle diseases and non-communicable diseases like cancer, accidents, etc. So, on the physical health front, we are proven to be in a very bad shape.

On the social front, when we are living in the 21st century, the century of science, our country is riddled with issues like caste chauvinism, religious chauvinism and gender chauvinism. The society is sick with all these medieval mindsets. We are behaving like a sick society, like sick people who have gender bias, religious bias and caste bias which is making our society a very unhealthy one on the social front. Similarly, because of miseries, economic miseries, health problems, unemployment, the psychological health of the Indian people is also very poor. So, on all those parameters, we are in a very bad shape.

The Government should take care of all these problems. They should take them into consideration and should bring a robust health care system. Of course, it did talk of cancer care centres in 170 districts and increasing it in a phased manner. Yet, it did not talk of preventive cancer detection centres which will mitigate cancer in the first stage when treatment is possible. It will not only save life but save the economy of the family also. So, I think that the Government should come with a comprehensive cancer detection campaign and screening of all target population, for example regarding breast cancer in females or cervical cancer in females or oral cancer in tobacco chewers.

The target population should be marked and their extensive screening programme for early detection, early treatment should be started. Instead of just focusing on the curative approach, we should focus on the preventive approach on the diseases like cancer and other such ailments including lifestyle diseases like blood pressure, hypertension, coronary artery disease, heart attack and all that. We should go for mass education programmes and mass contact programmes to educate people, to make people aware of these problems and work on the preventive approach.

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Thank you, hon. Member. Please conclude.

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Sir, kindly give me some time.

HON. CHAIRPERSON: A number of Members from your party are there to speak.

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): But Sir, I am the principal speaker on it. I will tell you that the disease patten in a particular country changes with the conditions of that country, economic condition of that country. For example, one economic set or condition is for one set of diseases and another economic set is for another set of diseases. But India is embroiled in both the sets of diseases, the diseases of the poor and the diseases of the rich. So, we should take proper attention and attend to the twin problems of health in our country.

Coming to fiscal deficit, the Government has patted its back for bringing down the fiscal deficit in 2024-25 from the projected 4.9 per cent of GDP to estimated 4.8 percent and it promises to bring it further down to 4.4 per cent in 2025-26. But one has to ask, how is this being done? Who is being asked to tighten the belts? Given the hardships that people are facing today, given the dire conditions in the economy, the first thing that a Government should do is to increase spending on the social sector. Instead, this expenditure, especially on health and education, is either stagnating or even contracting relative to the overall growth in Government expenditure. The fiscal deficit is being controlled at the cost of the social sector. This is happening at a time when two-thirds of the Government revenue comes from direct taxes and borrowings and only one-third is coming from income and corporate sector.

(1245/PS/CP)

Now, I come to tax relief. The headline has been grabbed … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Thank you. Please conclude.

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I will conclude in five minutes only.

I come to unemployment. India had and still has the strongest demographic dividend for being the youngest nation in the world, which means we have 600 million people, that is, 60 crore people, that is equal to the population of entire Europe, who are in the young working age group from 18 to 35 years. It is such a huge population.

Sir, it is this young India which has the potential, and it is this aspirational India which can open the floodgates of development if given an opportunity to utilise its potential at the optimal level.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, hon. Member. Now, please conclude.

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Sir, please give me some more time.

HON. CHAIRPERSON: No, you have a number of Members from your Party to speak.

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): Sir, I have a final point to make.

The people of India are reeling under unprecedented hardships and economic stress. The Budget should always be an instrument in the hands of the Government for improving the lives of the people, but more so, in such dire conditions, it should not aim at … (*Interruptions*)

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Thank you, hon. Member.

Now, I call Shri Rao Rajendra Singh ji.

Shri Rao Rajendra Singh ji, please start.

… (*Interruptions*)

1246 बजे

श्री राव राजेन्द्र सिंह (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से अपने शब्दों के माध्यम से इस बात को अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि न्यायिकेतर संस्वीकृति से अभिप्राप्त वे सारी कामुक शक्तियां जिनका आविष्कार, उपनिवेश काल में इस मां भारती की मानव सम्पदा को गुलामी के कालदंश से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से प्रतियुक्त किया था, आज परिवर्तित प्रतिमानव में वह एक कालभ्रम सा साबित होती है। एक दशक से भारत सरकार जिस नेतृत्व के आगाज पर मानव सम्पदा को और मां भारती के मानव जीव को जिस प्रकार से राहत पहुंचा रही है और इस राष्ट्र को विकास के मार्ग पर प्रशस्त कर रही है, आज यह सदन इस बात का साधुवाद देता है, उनका अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है।

सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से आपके समक्ष कुछ विषयों को प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूं। एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जिनको वर्ष 2017 में नोबल मेमोरियल पुरस्कार से नवाजा गया, जिनका नाम रिजर्ड एच. थेलर है। इकोनॉमिक्स और मनोविज्ञान के साथ मानव का क्या संबंध रहता है, उस पर उनका एक लेख है। बिहैवियरल इकोनॉमिक्स पर उन्होंने अपनी बात कही है कि सिर्फ आंकड़ों के मायाजाल से आप मनुष्य को तब तक उत्साह, विकास और सम्पन्नता का मार्ग नहीं दिखा सकते हैं, जब तक वह मनुष्य मनोवैज्ञानिक तरीके से इस बात को स्वीकार न कर ले और संतुष्ट न हो जाए कि हां, उसके विकास और उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार ने काम किया है। मैं उन्हीं के शब्दों में इस बात को सदन के बीच में रखना चाहता हूं, and I quote:

> "You want to nudge people into socially desirable behaviour. Do not, by any means, let them know that their current actions are better than the social norm. A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people's behaviour in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives."

मैंने यह बात इसलिए कही कि विचारधाराओं के माध्यम से, मनन शक्ति के माध्यम से हम भारत की मानव सम्पदा को उत्कृष्ट मार्ग पर प्रशस्त करना चाहते हैं। अगर साधारण और सरल शब्दों में यह बात कहूं कि वर्तमान में पेश किया हुआ जो वित्त अभिलेखा है, उसको हम सामान्य रूप से बजट कहते हैं।

(1250/NK/SMN)

आज तक पांच दशकों के उपरांत दस वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्था को अंजाम दिया गया है, उसमें भी इस वर्ष का बजट सबसे ज्यादा उत्कृष्ट अभिलेखा है। मैं वित्त मंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मीमांशाओं और व्याख्या से संसार पटा पड़ा है, अपनी-अपनी बात को अपने तरीके से कहना और उसे सही मानने की प्रवृत्ति, वाद-विवाद के दायरे पैदा करती है, यही स्थिति हमारे प्रतिपक्ष की है। जब-जब भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा यहां के वित्त व्यवस्थाओं के माध्यम से आम व्यक्ति को राहत पहुंचाने का कार्यक्रम होता है तो प्रतिपक्ष की भूमिका उन चार मानव दृष्टि विदित मानवों के प्रति होती है जो हमारी योजनाओं के आकार को अपनी आंखों और बुद्धि से नहीं देखती, स्पर्श करके उसके आकार को परिभाषित करने की कोशिश करती है। ऐसे दृष्टिबाधित व्यवस्थाओं में आलोचना के माध्यम से साकार स्वरूप प्रदान करती है, लेकिन यह निराकार ब्रह्म है तो साकार व्यवस्था को सत्य के सेतु पर कुछ व्यवस्था से प्रतीत करता है, इसका आज की तारीख में वित्त अभिलेख है।

ज्ञान जैसे शब्द का उपयोग कर बजट दस्तावेज को चार भागों में बांटा है, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी। मैं सबसे पहले अन्नदाता की बात करता हूं। आप स्मरण कीजिए, वर्ष 1951 में जबकि उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था, चुनाव हो रहा था, वर्ष 1952 में चुनाव हुआ था। वर्ष 1950 में संविधान की व्यवस्था के उपरांत पार्लियामेंट के चुनाव से पहले हमारा खाद्य सुरक्षा का पहला सेन्सस आया। उस समय प्रति व्यक्ति खाद्य सुरक्षा 394 ग्राम था, सात दशक निकल गए। खाद्य सुरक्षा का अंजाम 60 वर्ष तक 394 से लेकर 468.7 ग्राम तक सीमित रहा। जिस वक्त भारत आजाद हुआ था, उस समय 35 करोड़ जनसंख्या थी और 394 ग्राम खाद्य सुरक्षा थी। हम 100 करोड़ पार कर गए, अब तक हम 468.7 और 468.8 के बीच झूल रहे थे।

वर्तमान सरकार पिछले एक दशक में 468 को उठाकर 510 ग्राम तक लेकर गई। मैं यह नहीं कहता कि आज भी यह बहुत बड़ा कीर्तिमान है, लेकिन एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि सात दशक तक अगर हर साल पांच ग्राम भी बढ़ता तो हजार ग्राम तक बढ़ जाता। किसानों की बात होती है, गरीब की बात होती है, युवाओं की बात होती है। बात चर्चा तक हो जाती है। अब तक ऐसी सरकार नहीं आयी थी, जिसने बात को यथार्थ में प्रस्तुत करने की कोशिश की हो। आज अन्नदाता के माध्यम से इस बात के स्वरूप को आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से किसान की व्यवस्था को अपनी वर्तमान स्थिति से निकाल कर एक खुशहाली की व्यवस्था में स्थापित करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह काम हुआ है।

अगर आपके अन्नदाता के स्वरूप में सबको अपने दायित्व का इस्तेमाल करते हुए संवेदनशीलता की व्यवस्था देनी है तो संवेदनशीलता में उस मानव जीव को हमें अन्न जैसी चीज उपलब्ध कराना है, उसको अपने धर्म के माध्यम से अपने कर्तव्य के रास्ते से सुनिश्चित करना है।

(1255/KDS/SM)

उसके घर में रोशनी हो, उसके घर में पानी हो, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और उसके लिए वह सारी व्यवस्था हो, जो किसी एक खुशहाल राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। ऐसा राष्ट्र तब बन सकता है, जब यहां का अन्नदाता इन सारी व्यवस्थाओं से पल्लवित हो। मैं मानता हूं कि इस बजट के कुछ दस्तावेज, जिन्होंने प्रधान मंत्री धन-धान्य योजना के माध्यम से जिस प्रकार से कृषि पद्धति की व्यवस्था को सुधारात्मक तरीके से विमोचित करने की कोशिश की है, उस हेतु वह साधुवाद के पात्र हैं।

महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार राष्ट्र की फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा शोर होता है। वित्त मंत्री महोदया विराजी हुई हैं। अचरज इस बात का है कि हमें हमारी ही सरकार की व्यवस्थाओं और कृति पर संकोच, संशय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति भारत में निवेश करने के लिए आतुर है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इस पूरी 21वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में भारत के अंदर 1ट्रिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा का निवेश फॉरेन इनवेस्टमेंट के माध्यम से हुआ है। आप अचरज करेंगे कि पिछले 25 सालों में इस 1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश में से विगत 10 सालों में 62 फीसरी हिस्से का निवेश आया है। उसमें 45 बिलियन तो केवल इस साल आया है। बाहर बैठा हुआ निवेश करने वाला व्यक्ति भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है, लेकिन भारत का प्रतिपक्ष इसी निवेश व अर्थव्यवस्था पर आक्षेप लगाता है।

महोदय, बातें बहुत बड़ी-बड़ी की जाती हैं। मध्यम आय वर्ग के लोगों के बारे में चिंता व्यक्त की गई। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? हमारे सामने वे सारे अभिलेख हैं। मैं आपके मध्य वे अभिलेख प्रस्तुत करना चाहता हूं। मध्यम आय वर्ग को जितना छूट व फायदा वर्तमान सरकार ने दिया है, पिछली किसी सरकार ने नहीं दिया है। यह मैं आंकड़ों से साबित करना चाहता हूं। मैं तुलनात्मक विवरण दूंगा। यह भी आरोप लगता है कि कॉरपोरेट जगत को ज्यादा दिया जाता है और व्यक्तिगत आय वाले व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है। यह कितना असत्य है, इसे मैं आपके मध्य पेश करना चाहता हूं।

महोदय, पिछले 5 वर्षों में जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उनको इंसेंटिव व राहत कितनी मिली, उसका टोटल 8 लाख 70 हजार 9 सौ 7 करोड़ रुपये, जबकि कॉरपोरेट को 4 लाख 53 हजार 3 सौ 29 करोड़ रुपये की राहत मिली। मेरे पास एक-एक वर्ष का आंकड़ा है। वर्ष 2019-20 में कॉरपोरेट जगत को हमने 94 हजार करोड़ रुपये की इंडिविजुअल बेनिफिट्स दीं, तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को हमने 1 लाख 55 हजार 525 करोड़ रुपये की इंडिविजुअल बेनिफिट्स दीं। वर्ष 2021 में यदि हमने कॉरपोरेट को 75 हजार करोड़ रुपये की इंडिविजुअल बेनिफिट्स दीं, तो टैक्स पेयर्स को हमने 1 लाख 28 हजार 244 करोड़ रुपये इंडिविजुअल बेनिफिट्स दी हैं। वर्ष 2021-22 को 96 हजार 892 करोड़ इंडिविजुअल बेनिफिट्स कॉरपोरेट को दीं, तो वहीं टैक्स पेयर्स 1 लाख 68 हजार 566 इंडिविजुअल बेनिफिट्स दीं। यदि वर्ष 2022-23 को देखें, तो 88 हजार 109 करोड़ इंडिविजुअल बेनिफिट्स कॉरपोरेट्स को दिए, वहीं टैक्स पेयर्स को 1 लाख 96 हजार 678 करोड़ रुपये इंडिविजुअल बेनिफिट्स दिए। वर्ष 2023-24 का अनुमान है कि 98 हजार 899 करोड़ रुपये इंडिविजुअल बेनिफिट्स यदि कॉरपोरेट्स को दिए गए, तो टैक्स पेयर्स को 2 लाख 20 हजार 9 सौ 88 करोड़ रुपये इंडिविजुअल बेनिफिट्स दिए।

महोदय, आंकड़े सही बोलते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष इस बात को स्वीकार करने हेतु तैयार नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था को अंजाम देने वाली वर्तमान भारत सरकार इस बात के लिए साधुवाद की पात्र है कि जहां इस बार के बजट में आपने 12 लाख रुपये तक की राहत जनता को पहुंचाई है, वह सोने पर सुहागा वाली व्यवस्था है, जो मैंने अभी आपके बीच में प्रेषित की है।

(1300/MK/RP)

अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अभिलेखों को अच्छी तरह से देखें तो हम पाएंगे कि भारत की सरकार ने अपने नौजवानों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारे सामने जितने भी अभिलेख हैं, उनमें सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की जो व्यक्तिगत टिप्पणी है, उसको पहले प्रस्तुत करना चाहता हूं-

> "India's economy has been remarkably resilient to the deteriorating external environment, and strong macroeconomic fundamentals have placed it in good stead compared to other emerging market economies,"

वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था को संसार के बाकी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था और बाकी व्यवस्थाओं के तुलनात्मक रूप से बेहतर, अच्छा और सुदृढ़ बताते हैं। मैंने बीच में एक चीज छोड़ दी है, जिसके बारे में जरूर बोलना चाहता हूं। भारत की सॉवरेन सिक्योरिटी को जे.पी.मॉर्गन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सचेंज में इमर्जिंग बांड एक्सचेंज में जगह मिली है। हम वर्ष 2013 से कोशिश कर रहे थे और वर्ष 2023 में उन्होंने सहमति दी। वर्ष 2023 के बाद, जुलाई, 2024 को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बांड्स का वहां ट्रेड हुआ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बांड्स के ट्रेडिंग के उपरांत हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारे भारतीय बांड्स हैं, उनको जिस प्रकार का एक्रेडिशन मिला है, उनको 10 परसेंटज तक वेट मिला है, जो 31 मार्च तक चलेगा।

महोदय, एफएआर के माध्यम से जो निवेश आता है, चाहे वह पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से आता हो या डायरेक्ट एफडीआई इंवेस्टमेंट के माध्यम से आता हो, निरंतर उसके अंदर इजाफा हुआ है। मैं इजाफे का क्वांटम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं that over the past decade, from 2014 to 2024, India received US$ 709.84 billion, Rs. 60,24,500 crore, accounting for 68.69 per cent of the total FDI since 2000. जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है that the Government has also introduced investor-friendly reforms such as allowing 100 per cent FDI in most sectors, and amending the Income Tax Act, 2024, to reduce taxes and abolish Angel Tax. These factors collectively position India as a strong global investment destination paving the way for sustainable economic growth. What more do you want from a Government?

आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। इन आंकड़ों को आप जिन शब्दों से सार्वजनिक व्यवस्था के अंदर सेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कई बार आपका आचरण असत्य कह देता है। आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं।

सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में जब वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था संभाली थी, उससे पहले की अर्थव्यवस्था क्या थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद जब यूपीए की पहली गवर्नमेंट आई थी तो वाजेपयी जी की सरकार ने इनको 8 परसेंट जीडीपी के साथ गवर्नमेंट ट्रांसफर की थी। उसके बाद आपने क्या किया? एनुअल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में 9.1 परसेंट था और यूपीए के दूसरे कार्यकाल में 9.4 परसेंट था। फाइनेंशियल ईयर 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक एवरेज एनुअल इंफ्लेशन 8.2 परसेंट पर रहा।

(1305/NKL/SJN)

अगर आप एनडीए सरकार के समय का डेटा देखें, तो वर्ष 2014-19 में एन्युल सीपीआई इन्फ्लेशन 3.4 प्रतिशत था। मैं वर्तमान सरकार के पहले कालखंड की बात कर रहा हूं। ये डबल से भी कुछ ज्यादा था। उसके उपरांत भी आप ये कहते हैं कि आपमें दोष हैं। दूसरे टर्म में थोड़ा ज्यादा था, 5.5 प्रतिशत था। आपकी फॉरेन करेन्सी और बैलेंस का क्या हाल था? During the UPA regime, the forex reserves had declined from USD 294 billion in July 2011 to USD 256 billion in August 2013. By September 2013, the forex reserves were just enough to finance little over six months of imports, down from 17 months in the end of 2004 when they took over. The Forex reserve to external debt ratio tanked from 95.8 per cent in FY11 to 68.8 per cent in FY14. आपके समय तो ऐसी अर्थव्यवस्था थी।

Recently, India’s Foreign Exchange Reserves surged to a record high, reaching a new peak of 666.85 billion, and the reserves saw an increase of 9.69 billion in just one week in the month of July last year. This is not something that I have fabricated. This is actually the data which the books and international communities have provided us.

1307 hours (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

Even if you see the present-day statistics, India's Current Account Deficit stands at 1.2 per cent of the GDP in Quarter 2 of FY25, lower than its long-term trend with support from world’s service sector, whose exports have grown to 11.6 per cent on a year-on-year basis. Fiscal Deficit and Revenue Deficits are being at a staunch 4.8 per cent and 1.9 per cent, with

an estimated rate of 4.4 per cent and 1.5 per cent in Financial Year 2026 to come. It only denotes that most of the post-COVID fiscal burden has been unbound, and India has a great chance of improving its sovereign rating, both being lower than pre-COVID levels.

Coming to the reduction in personal income tax, of course, I have already said about it. The capital and revenue expenditure ratio, a key marker to judge quality of fiscal spending, is budgeted to increase to 28.4 per cent, the highest in two decades. A great example of a fiscal prudence is Centre's outstanding liabilities in 2025-2026, which are estimated to be 56 per cent of the GDP. Outstanding liabilities had declined from 52 per cent of GDP in 2013-14 to 49 per cent of GDP in 2019, that is prior to COVID. But unfortunately, the COVID led to a lot of other things. From 2019-20 onwards, the outstanding liabilities unfortunately increased to 61 per cent of GDP in 2021 due to COVID and have moderated therefore, and is targeted to be less than 50 per cent by the time we reach 2030. Throughout the last 11 years of the Government, there has been a consistent rise in contribution of direct taxes as a share of the total tax revenue of the Government, indicating a rising trust in the Government, simplification of tax reforms and rising income levels.

For the State of Rajasthan, an increased allocation of Jal Shakti Ministry from Rs 47.95 crore to Rs 99,503 crore in 2025-2026 comes as a boon since the scheme has done wonders for the State. The Parbati-Kalisindh-Chambal- ERCP Linking Project, जो आज राजस्थान के अन्नदाता के लिए लाइफलाइन है। एक ऐसी व्यवस्था है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तुलनात्मक रूप से वहां के काश्तकार, किसान और लोगों को उतना ही ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। चूंकि अब वह नेशनल प्रोजेक्ट में आ गया है, इसलिए मैं इस सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं।

(1310/VR/SPS)

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। There are two industries which come under service sector. There is a World Trade Council on Travel Tourism Economic Impact Report, 2024. अगर आप उस चीज को देखेंगे तो आप पाएंगे और मैं आपके बीच में वह आंकड़ा पेश करना चाहता हूं। The tourism sector is

witnessing a remarkable recovery post-pandemic, with domestic tourism leading the way according to the World Travel and Tourism Council – WTTC-24 Economic Impact Research.

In 2023, the sector contributed over 19.13 trillion to the GDP, which is 10 per cent above 2019 levels, and created nearly 43 billion jobs, an eight per cent increase from 2019. वित्त मंत्री जी के पैरा 75-76 में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में, टूरिज्म के बारे में विस्तृत रूप से ब्यौरा है। मैं इस बात के लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हार्मोनाइज्ड मेन लिस्ट में आपने होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को व्यवस्थित करने की बात की है। वह आपके वर्ष 2022 के एक्ट के अंदर लिमिट करती थी कि ऐसी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और होटल, जिन शहरों की जनसंख्या दस लाख या उससे ज्यादा है, वे इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में आएंगे। अब आपने इसमें अभिलिखित किया है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि उस सीलिंग को हटाकर इस प्रकार की जहां भी एक्टिविटी हो, जो आपके टूरिस्ट सर्कल, सर्किट या जो आप 50 नए डिस्ट्रिक्ट्स चिन्हित करेंगी, उनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था के अंदर आप टूरिज्म व्यवस्थित स्वरूप को व्यवस्थित करने का सत्कर्म करेंगे। मेरा आपसे यह निवेदन है।

With the Government initiative like the Vision India@2047, I would like to inform the House about the total GDP contribution from travel and tourism sector. In 2019, the contribution of this sector to the GDP was 6.9 per cent, which has increased to about nine per cent in 2023. The jobs created in this sector are over 42 million, and this is reaching to 44, and will go up to 45. With the boost coming through the Budget, maybe, it will surpass even the 50 mark. मैं यूथ की बात कर रहा था, इसलिए मैंने रोजगार की बात की है।

इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है, वह एवियेशन इंडस्ट्री है। तकरीबन वर्ष 2030 आते-आते 1700 नए एयक्राफ्ट्स आपके पास आएंगे। जब एक एयरक्राफ्ट आता है तो उस एक एयरक्राफ्ट की खरीद से सीधे सौ व्यक्तियों को रोगार मिलता है और 600 व्यक्ति, जो उसके साथ अलाइड होते हैं, उनके जॉब्स की क्रिएशन होती है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक हजार भी आ जाते हैं तो कितने नए रोजगार के संसाधन और जॉब्स उपलब्ध होंगे? यह एवियेशन इंडस्ट्री की वह व्यवस्था है, जिसके बारे में मैंने आपको उल्लेख किया है।

आपके बीच में एक विषय और बहुत आदर के साथ रखना चाहूंगा। वह प्रमोशन ऑफ लेबर है। आप जितना ऑटोमेशन लेकर आ रहे हैं, उससे जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें नौकरियां कम होती हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, वहां ह्यूमैन रिसोर्स ऐसा है, जो धीरे-धीरे ऑटोमेशन के साथ फैक्ट्रियों में कम हो रहा है। होटल एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहां

कभी रोबोट काम नहीं कर सकता है। वहां आपको व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सरल सा अर्थमैटिक है कि अगर एक कमरा बनता है तो सीधे दो से तीन लोगों को रोजगार मिलता है और आठ लोग ऐसे होते हैं, जिनको उस कमरे के साथ रोजगार उपलब्ध होता है। इस प्रकार से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है और एवियेशन इंडस्ट्री बढ़ रही है।

मैं आपसे एक प्रमुख चीज ग्रीन एनर्जी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। ग्रीन एनर्जी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू वित्त मंत्री जी ने विस्तार से रखा है और वह भारत स्मॉल रिएक्टर्स है। आज से पहले जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं, वे 700 की क्षमता से ज्यादा लगे हैं। Then, it will come to small modular reactors with 300 megawatt or less.
(1315/MM/SNT)

इसमें एक बहुत बड़ी व्यवस्था और है कि भारत के रेल मंत्रालय ने यह निश्चित किया है कि उनकी जितनी भी ट्रैन्स हैं वे या तो इलेक्ट्रिसिटी पर चलें या ऐसी एनर्जी पर चलें जिसमें कार्बन फुटप्रिंट न्यूट्रल हो। रेलवे मिनिस्टर ने भी न्यूक्लियर प्लांट के जरिए एनर्जी की व्यवस्था करने का एक संकल्प लिया है। अब बात यह आती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर आप न्यूक्लियर प्लांट्स में निवेश करेंगे। यह बात सही है।

The year 2025 started on a bright and positive note for India-U.S. cooperation in civilian nuclear energy. Visiting India for the last time as the U.S. National Security Advisor on 6th of January 2025, Jake Sullivan noted that the U.S. is in the final stages to remove the long-standing regulations that have prevented civil nuclear cooperation between India's leading nuclear entities and the U.S. companies. Consequently, the U.S. Bureau of Security has removed the names of three Indian institutions – the Bhabha Atomic Research Centre, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, and Indian Rare Earths Limited – from the entity list, representing a core component of U.S. export control policy intended to prevent proliferation of weapons of mass destruction. The entity list basically consists of names of individual businesses and organizations to whom exports of certain technologies and goods are restricted. This development came after U.S. Assistant Secretary of State for Energy Resources, Jeffrey R. Byrd, in February 2024, termed the nuclear deal as an important piece of unfinished business which both countries had a shared interest in.

We were agitating the other day on the foreign policy, how we are behaving, and what we are doing. I am not quoting from a political act; I am

quoting from a genuine issue which got resolved. We had this confrontation from 2010. Gradually, we have been able to resolve it. Just imagine, 50 per cent of your entire energy that is coming comes from an energy which creates a lot of carbon footprints. Even the others that come from also have carbon. If we can do it, and if we can do it accordingly, I am sure it will go a long way.

There are a number of things that are happening. If I talk about the space industry, the space economy, we are the first one to give our country a space policy. The year 2023 is the year when we had space policy. Now we have launched the 100th satellite. It was 94 the last time when we met here in this House. Now, it is 100. The Prime Minister commemorated, congratulated the entire scientific world and the Department of Space and Research of what a wonderful job they have done. These are commercially viable deals. We do it in a much more economical way than what the world does in this field. I am sure it opens a lot of other avenues and opportunities for the coming generation to go into space technology, to go into nuclear, civil, academic studies, and also adopt certain other issues which will create self-employment or you create a knowledge which creates employment.

These are the things which the budget has actually adhered to. I am sure there are a lot of other statistics which the others would want to speak. I do not want to dwell upon them. I have given a little brief of what it is. All that shines may not be gold. But what shines in the Indian budget is nothing but gold. That is how I want to conclude it.

Thank you.

(ends)

1319 बजे

डॉ. शिव पाल सिंह पटेल (प्रतापगढ़) : धन्यवाद सभाति महोदया। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी का पक्ष रखने के लिए बोलने का अवसर दिया।

महोदया, बड़े दुख की बात है कि अमेरिका ने भारतवासियों का अपमान किया और सरकार संवेदनहीन नजर आ रही है।

(1320/YSH/AK)

बड़े दुख की बात है कि अमेरिका ने भारतवासियों का अपमान किया और सरकार संवेदनहीन नजर आ रही है। इसी तरह से चीन ने भी हमारी जमीन का एक बहुत बड़ा भू-भाग हथिया लिया और हमारे बहुत से जवानों को भी बीच-बीच में मौत के घाट उतारा, लेकिन हमारी सरकार मूकदर्शक बनी रही। इसीलिए ये देश हमें बहुत कम करके आंकते हैं। इनकी नजर में हमारी हैसियत कम है। आपको याद होगा हमारे विश्वगुरू ने कभी भारत के दिल्ली, मुम्बई, आगरा और अहमदाबाद में 'नमस्ते ट्रंप' करवाया था, जिससे वहां पर कोरोना भी फैल गया था और फिर डोनाल्ड ट्रंप जी के दूसरे चुनाव में अमेरिका जाकर 'अबकी बार ट्रंप सरकार' का नारा देकर प्रचार-प्रसार भी किया था। वे कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हैं, फिर भी इस ट्रंप सरकार देश की इतनी बेइज्जती क्यों की? यह एक विचारणीय विषय है।

दूसरी तरफ हम चीन को लें, जिसने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर जबर्दस्त काम किया है। अभी कुछ ही दिन पूर्व अमेरिका की एक एआई सॉफ्टवेयर कंपनी चैट जीपीटी, जिसे अमेरिका अजेय कहता था। उसके अनुसार उसे कोई बना भी नहीं सकता था। उस सॉफ्टवेयर को पूरी दुनिया में बेचकर वह खूब पैसे कमाता था। चीन ने ऐसे सॉफ्टवेयर पर सोचा, जो भारत नहीं कर पाया। चीन ने कुछ योग्य युवाओं को लगाकर नया एआई साफ्टवेयर 'डीपसीक' बनाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और अमेरिका को हजारों बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। इससे सारे अमेरिकी डर गए। इसे कहते हैं – नहले पर दहला। लेकिन हमारी सरकार ऐसा कुछ सोचने के बजाय आज भी वही, गाय, गोबर, गौमूत्र, कावड़ यात्रा, कुंभ, धार्मिक झगड़े और धार्मिक स्थलों की खुदाई में ही लगी रहती है।

यहां तक कि जब जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे जी भारत आए तो उनसे घंटों गंगा आरती करवाई गई। शायद इसीलिए ये देश आज भी हमारी संपेरे और आदिवासियों से ही तुलना करते होंगे। सरकार को चाहिए कि हम भी चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करें। नई-नई टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में जमकर उपयोग करें और हायर एजुकेशन में रिसर्च पर जोर दें और एजुकेशन का बजट अधिक से अधिक बढ़ाएं। एजुकेशन, जिससे देश के हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है, उसका बजट यह सरकार घटाती जा रही है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था से ही हम दुनिया के समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़े हो पाएंगे।

सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट से गरीब और गरीब तथा अमीर पिछले 10 वर्षों की तरह और अमीर ही बनेगा। देश में सबसे अधिक आबादी वाले किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग तथा छोटे व्यापारियों के लिए किसी भी तरह की राहत की घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। युवाओं के लिए रोजगार की कोई ठोस कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी। अत: बजट में युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देने हेतु विचार किया जाए।

प्रधान मंत्री जी तो अपने भाषण में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें कहते हैं। हमेशा की तरह कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। कुंभ पर सरकार ने हजारों-करोड़ रुपये खर्च किए, फिर भी कितनी बड़ी अव्यवस्था रही। उसके बारे में सब जानते हैं। कभी सैकड़ों टेंट जलकर भस्म हो जाते हैं, कभी भारी संख्या में लोग भगदड़ में दबकर मर जाते हैं, फिर भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रैंगती है, और तो और कुछ तथाकथित संत-महात्मा मरने वालों को मोक्ष प्राप्ती की संज्ञा दे डालते हैं। ऐसा केवल भारत और बीजेपी के ही शासनकाल में हो सकता है।

प्रधान मंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान बुद्ध पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, लेकिन वे भारत में कभी भी भगवान बुद्ध का नाम नहीं लेते हैं।

(1325/RAJ/UB)

वे डरते हैं कि यदि हम उनका नाम लेंगे, तो उनकी पार्टी के बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का भारत में उतना सम्मान हो। इसीलिए बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले बौद्ध सर्किट के निर्माण व रख-रखाव के लिए इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। यहां तक की कुशीनगर में बनाए गए एयरपोर्ट को शुरू करने के बाद भी बंद कर दिया गया है, जहां पर हजारों श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक आते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता और देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग मिलता। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बौद्ध सर्किट के विकास के लिए अधिक से अधिक बजट दिया जाए और कुशीनगर के एयरपोर्ट को शीघ्र ही चालू किया जाए।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की बजाय दूसरे धर्मों के स्थलों के लिए भी बजट की घोषणा की जाए, उनके लिए बजट दें एवं उनका संरक्षण भी करें, जिससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा और देश में खुशहाली होगी।

भारत सरकार मेक इन इंडिया का जोर-शोर से प्रचार करती है, लेकिन कितना मेक इन इंडिया है, यह सब जानते हैं। मेक इन इंडिया केवल कहने और दिखावे के लिए है, क्योंकि ज्यादातर सामान चीन अमेरिका और कुछ अन्य देशों से ही आयात किए जाते हैं।

हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। इनके दोहरे चरित्र पर यह शेर बहुत फिट बैठता है कि

“शब को मय ख़ूब सी पी सुब्ह को तौबा कर ली
रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई।”

इस बजट में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई भी नई घोषणा नहीं की गई है, जिससे देश में आयात और अधिक बढ़ेगा और देश विदेशी कर्ज में भी डूबेगा। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर-शोर से यह भी कहा है कि 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। इस पर मेरा प्रश्न है कि अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, तो 80 करोड लोगों को फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है? नल-जल योजना का यह हाल है कि गांवों में मात्र पाइप लाइंस बिछा दी गई हैं लेकिन वहां धरातल पर कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी की कहते हैं कि जाति की बात करना आज कुछ लोगों का फैशन हो गया है, जबकि वह स्वयं कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज का हूं। मेरी मां दूसरे के यहां बर्तन मांजती थी, मैं चाय बेचता था आदि आदि। बुनियादी चीजों पर ध्यान न देकर केवल वाह-वाही लूटने वाले काम करना इस सरकार की नियत रही है। जीडीपी में भारी गिरावट हुई है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

इस सरकार में रुपए का जितना अवमूल्यन हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ है। बढ़ती महंगाई के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस कदम नहीं है। इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। किसानों के लिए इस बजट में कोई नई योजना नहीं है और न ही एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई ठोस घोषणा की गई है। किसनों को फसल की लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसान दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। केसीसी पर लोन की लिमिट बढ़ाई जाने से किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। जब उन्हें फसल की लागत मूल्य नहीं मिल पाता है तो वे लोन लेकर कर्ज में और डूबेंगे। किसान का जब फसल बोने का समय आता है तो डीएपी और यूरिया का आकाल पड़ जाता है। सरकार के बिचौलिए खादों को अपने गोदामों में छुपा कर महंगे दामों पर भेजते हैं और किसान टाइम से फसल भी नहीं बो पाते। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि अन्नदाता किसानों को समय से सस्ता खाद और बिजली उपलब्ध कराए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्लीज, माननीय सदस्य आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए।

डॉ. शिव पाल सिंह पटेल (प्रतापगढ़) : सभापति महोदया, मुझे अभी और बोलना था, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी। धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, श्री अभिषेक बनर्जी जी।

(1330/GM/IND)

1330 hours

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Hon. Chairperson Madam and esteemed Members of this august House, today I rise here not just to respond to the Union Budget that was presented by the hon. Minister for the year 2025-26, but also to expose the grand illusion it weaves - a mirage, a deception, or rather a 'golden' deer' Budget. All of you must be wondering why I am referring to this Budget as a 'golden deer' Budget. The 2025 Union Budget is nothing but a Marich moment from the Ramayan, an elaborate illusion designed to deceive. Just as the demon Marich took the golden form of deer to lure Maa Sita away, the NDA Government has crafted a shiny dazzling Budget promising prosperity, while hiding the economic catastrophe beneath. This Budget might shimmer, but it is hollow as a treasure chest filled with air. It is flash promises of tax cut, economic growth, infrastructure hype to distract the common man, but beneath this illusion lies a brutal reality-- hidden indirect taxes, soaring inflation, slashed public spendings, and last but not least, corporate giveaways. Just as Maa Sita was misled, the common people are being pulled away from financial stability straight into fiscal wrecking ball.

This Government proudly proclaims 'no income tax for income upto Rs.12 lakh'. But behind the scenes, they silently ensure the lost revenue is recovered through rising fuel prices, inflated service charges, hidden taxes on daily essentials, and middle class, much like Laxman warning Maa Sita, is sceptical, but BJP's propaganda and PR machinery is desperately working overtime to ensure that the common man and the people of this country still chase the 'golden deer' anyway. What is given by one hand is being swiftly taken by the other. Just as in the Ramayan, by the time people realize and recognize the deception, the economy has already been handed over to the Ravanas of crony capitalism while the common man is left struggling to afford groceries, fuel, travel, healthcare and even a simple movie night, all while being taxed for merely existing.

Madam, the Budget presented by the NDA Government is a masterclass in half-truths, half accountability, half delivery of schemes, and half-hearted governance. From half-built houses under PMAY to half-achieved farmer income targets, the Government continues to sell dreams while delivering only

fragments of reality. Infrastructure projects remain half-finished, welfare schemes reach half the beneficiaries and their failed economic policies cater to half the population, leaving the rest in uncertainty. This is not a vision for a developed India; it is a half-baked agenda wrapped in propaganda. Make no mistake; much like demonetization, GST and the draconian farm laws, the full extent of devastation will only be visible when the smoke clears.

I will start with the half-truths. The NDA Government in Maharashtra launched the Ladki Bahin DBT scheme for women in Maharashtra just before the Assembly elections last year to use it as a political bait. Now with the elections over, they have conveniently started scrutinizing beneficiaries, thus removing 60 lakh women from the scheme. This is just another *jumla* running deep in your veins and people see through this betrayal and they are watching. Another betrayal is there. Before the elections, the Government promised a legal guarantee for MSP. After the elections, the promise has disappeared without a trace. Madam, the Finance Minister is here and I am glad she is present in the House. She began her speech with a flourish on agricultural growth, but when it came to MSP, the one demand that every farmer of this country has raised, there was only silence, no legal guarantee, no relief from the crippling debt. Instead of waiving farm loans, the Government has increased the Kisan Credit Card loan limit which essentially means handing farmers more debt. Whatever data I am quoting in the House, if the Chair wants, I would lay it on the Table of the House before tonight.

(1335/SRG/KN)

Madam, since 2014, in the last ten years, there have been one lakh farmer suicides, that is one suicide every hour. These are not just numbers. They are a grim reminder of a system that abandons those who feed the nation, while they conveniently feed lies to the entire country. They boasted of digital India, but conveniently ignored the dire state of our schools. While flashy slogans flood social media, the harsh reality is PM POSHAN remains stagnant, leaving millions of children without nutritious food. More than 50 per cent of the children under the age of five suffer from chronic malnutrition with 17 per cent underweight, 36 per cent stunted, and 6 per cent wasted, a crisis screaming for attention, and yet the budget for PM POSHAN remains dejectedly inadequate,

proving once again that the Union Government is interested more in headlines than hungry children.

Another half-truth is this. Before the elections, the NDA Government or the ruling Party, BJP, promised LPG cylinders for all. But in reality, 1.2 crore households, I repeat the figure, 1.2 crore households could not afford even a single refill in 2022-23 because of their exorbitant price hikes. This is not upliftment, this is abandonment. When people have to choose between a meal and a refill, their promise is nothing but a cruel joke.

In 2019, the Cabinet approved Rs. 8,574 crore for the Census. Yet in 2025, today even after five years, only Rs. 570 crore have been allocated in this year's Budget. Five years later, and still counting, and this is not happening this year either. But why does this matter? Why am I talking about the Census? It is because without a Census, every policy, every income tax slab revision and every economic projection is simply and just a blind projection and a blind gamble. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, Women's Reservation Bill, which was passed by calling a special Session 18 months back in 2023, could not be implemented as its rollout depends on the completion of the next Census. The Women's Reservation Act and subsequent delimitation, both are both are yet to be scheduled. The Government seems to prefer running the country on guesstimates and propaganda, rather than real data because facts expose their failures, and they would rather keep the nation in the dark.

As we look at the economic policies of the NDA Government, one cannot help but see a pattern, and what is the pattern? The pattern is, if I am to say, it resembles the tale of a `Reverse Robin Hood'. What is a `Reverse Robin Hood'? We know the story of Robin Hood, taking from the rich and giving to the poor. BJP has mastered the art of taking from the poor and giving it to the wealthy elite. So, I am saying `Reverse Robin Hood'. I will give you an example, for instance, the waiving of corporate loans worth rupees thousands of crores, using taxpayers' money, while poor farmers struggling with small debts are left to suffer. The Government claims to have no money to increase subsidies on essential commodities. Yet, it slashes corporate tax rates, giving billionaires an even bigger slice of the pie. This is not economic justice. This is economic favouritism at its worst.

Then I talk about or rather I will come to half-federalism. You know, all the Members sitting in this House have never heard of this phrase. This is a phrase that I have coined — `half-federalism'. Why I say half-federalism? I will give you another example just to understand it better. In Bihar, BJP's ally, Janata Dal United or JD(U) has 12 seats. And in Bengal, BJP has 12 MPs. BJP is in power in Bihar, and BJP is not in power in Bengal. So, Bihar gets bonanza, Bengal gets blockade. This is half-federalism. Madam, not a single meaningful financial allocation has been made for the State of Bengal. This is a Bangla-*virodhi* budget. An amount of Rs. 1.7 lakh crore is still due to the State of West Bengal under various heads.

(1340/RCP/VB)

This is a deliberate financial blockade, a calculated move to stifle Bengal's growth, prosperity and development. West Bengal's spending due on MGNREGA to the tune of Rs.7,000 crore still remains unpaid depriving 59 lakh poor workers. The State has launched Karmashree scheme for providing employment opportunities to job card holders paying 51 lakh workers from its own funds. The Central Government has not cleared Rs.8,140 crore in housing dues for rural Bengal under Pradhan Mantri Awas Yojana depriving 12 lakh beneficiaries. The State Government launched the Banglar Bari project last year in the month of December providing housing to 12 lakh beneficiaries entirely from the State's own funds. Why am I giving you these facts? This is because all of you, especially the Members sitting in the Treasury Benches must know that even though you have deprived West Bengal, the State continues to stand tall as a true testament and an example of '*atmanirbharata'* where the mind is without fear, where the head is held high – *Chitto Jetha Bhayshunyo, Uchcho Jetha Shir.* While the Centre withholds funds and plays politics with the people of Bengal and their livelihoods, Bengal refuses to beg. We build, we provide, we progress, we grow with or without their support.

Bengal has more than doubled its export in the last 10 years. Madam, 57 lakh new MSMEs have been added employing over one crore people. Bengal's handloom industry employs over five lakh workers, which is the

second highest in the country. The State's Broadband Policy formulated in 2020 resulted in an investment of Rs.7500 crore in the telecom sector alone. Almost three lakh direct employments have been generated in IT companies. Bengal has over 88 lakh MSMEs, which is the second highest in the country. One out of five MSMEs are owned by women, which is the highest in the country. Madam, 36 per cent of workers in these enterprises are females, which is the third highest in the country.

Now, I will come to health. India remains one of the lowest health care spenders globally investing a mere three per cent of its GDP, far behind China's five per cent and United State of America's 16 per cent. For a country of 140 crore people, this level of investment is not just inadequate, it is an outright betrayal of public health. The Government has opened floodgates for 100 per cent FDI in insurance happily inviting foreign profits. But it refuses to remove the 18 per cent GST on health insurance. So, while the corporates enjoy feeding, the common man is taxed while they are fighting for their own lives. This is not a reform. This is a rigged game where the poor, the downtrodden and the common people of the county are deliberately made to lose. Instead of strengthening Government hospitals, this Government prioritises private insurance. Models like PMJAY, whose allocations shot up by 29 per cent, essentially funnel public money into corporate pockets. Strengthening public health care could have benefited millions. But instead, the Government chose to privatise health care under the guise of welfare. If the Government truly cared about public health, why has funding for mental health programmes like the National Tele Mental Health Programme been slashed by 16 per cent? Why is NIMHANS, which is the country's top health mental institute, facing budget cuts? The answer is simple. The Government just does not care. If health care were a priority, this Budget would be investing in real solutions, not just mere illusions. Under BJP rule, all of them combined excel in crafting headlines. But when it comes to hospitals, medicines, genuine public health investment, the reality is nothing short of an empty set.

Now, I come to half-Minister. I spoke about half-truths. I spoke about half-federalism. Now, let us talk about half-Minister. This is because our part-time Railway Minister is also juggling between two other Ministries. One is Electronics and Information Technology and the other one is Information and Broadcasting. Running the Indian Railways, which is considered as a lifeline for millions is not a side gig. But under BJP, governance has become a multi-tasking circus delivering half-baked results everywhere.

(1345/PS/PC)

Why I say this is because from the time this Government came in, they have discontinued the Railway Budget. What have they done for safety? How many kilometres have been covered under KAVACH? Between 2015 and 2024, there have been 678 consequential railway accidents, where more than 784 people have lost their lives, leaving more than 2000 injured. No wonder, tracks are crumbling. The tech sector is struggling. And the media is drowning in propaganda.

Then, Madam Chairperson, I come to half-baked answers. I can ask fifty questions or hundred questions to the Government. But let me ask only five. Why did you promise the people of this country a five trillion-dollar economy by 2025? We are in 2025 today in the month of February. And looking at the rate India is growing, that goal will not even be achieved by 2037, forget about 2025. Why did you slash funds for LPG connections to poor households by 30 per cent over Revised Estimates? Why have you slashed funds for crop insurance scheme by 25 per cent over Revised Estimates? Why has the Data Protection Board of India been given only Rs. 5 crore when the cost of running the Parliament for a single day is more than Rs. 9 crore? Why has the budget allocation for the Minority Affairs has been slashed by 57 per cent, decreasing significantly from Rs. 1,575 crore in 2024-25 to Rs. 678 crore in 2025-26? These are the hard facts. These are data.

Madam, now, I come to half-accountability. After half-truths, after half-federalism, after half-Minister, after half-baked answers, I come to half-

accountability. A Government is expected to be hundred per cent accountable. But this coalition Government believes in half-accountability. You all must be wondering where is the other 50 per cent. Well, that is conveniently covered by the ... (*Expunged as ordered by the Chair*) media because -- if you ask them, if you ask the media -- according to them, this Government is working 200 per cent and is functioning at 200 per cent efficiency, and in their world, in the media's world, there are no failures; failures are invisible and questions are forbidden. The only policy is propaganda.

Madam, let me make just two quick points to prove their half-accountability. Food inflation, in 2024, averaged at 8 per cent. In October, food inflation was at 14 months' high. The bottom five per cent spends Rs. 66 a day, while the cost of two vegetarian *thalis* exceeds Rs. 150. Household savings have dipped to a fifty-year low. In the case of unemployment, youth unemployment is at a staggering 45 per cent. Three out of ten graduates today are unemployed. Under PMKVY, only 18 per cent of the trained candidates were placed. Over 90 per cent of the workforce employed in the informal sector, lacked job security and benefits.

Madam, now, I come to half-delivery. Now, let me present before you a few examples of half-delivered services. Time and again, this Government has misled the people making tall claims but has failed to deliver when it truly matters. I start with '*Beti Bachao, Beti Padhao*'. Launched with much hype and fanfare to promote girl child education and welfare, yet, over 80 per cent of the scheme's budget was spent on publicity rather than spending it on actual benefits for girls.

Then, I come to Jan Dhan Yojana -- bank accounts without bank services. Under the Jan Dhan Yojana, 54.66 crore that means 54 crore and 66 lakh accounts were opened. But 11 crore and 58 lakh accounts remain inoperative. And out of this 54 crore accounts, 33 crore and 67 lakh accounts have balance less than Rs. 1000. This is the perfect example of 'financial inclusion' in paper but 'financial struggle' in reality.

Madam, they spoke about doubling farmers' income, a forgotten promise. They have promised to double the farmers' income by 2022. We are in 2025.

(1350/SMN/CS)

But today, farmers are downing in debt, facing stagnant crop prices, rising input costs and no legal MSP guarantee. Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana benefits insurance companies more than the farmers.

Smart Cities Mission has more hype than reality. They promised over 100 smart cities. But most projects remain on paper or are rather incomplete. Basic infrastructure in many towns is crumbling while funds remain under-utilized or diverted to beautification projects. They spoke about 'Make in India'. They spoke about revolutionizing the manufacturing industry but what is the reality and truth of 'Make in India' - more imports, less manufacturing. Local industry today struggles under the rising imports from China, inconsistent policies and low capital investment. Instead of boosting domestic production, India's trade deficit with China has sky-rocketed over the years.

There is unemployment. They promised about two crore jobs every year. But in reality, unemployment remains at 45 years high. They promised houses for all by 2022, yet another broken promise. In 2015, a promise was made to provide every household a home by 2022. Three years later, in 2025, as the deadline passed, millions still await promised homes highlighting delays and unmet expectations.

If you look at the pattern, it is big announcement and half execution or rather zero execution. From infrastructure to education, from health to employment, BJP's governance is a pattern of half delivery. Grand promises, incomplete execution, and shifting blame when failures are exposed. I was here when Madam Finance Minister presented the Budget but later, I went through the Budget document.

Madam, all I realize is this Budget is like those promises where you promise free meals, but charge exorbitantly for giving a chair to sit, for water

and for service. So, this Budget is like a buffet that promises free meal but charges exorbitantly for water, service and cutlery.

While tax payers find momentary relief in minor reduction in income tax slabs, the Government swiftly offsets these benefits through indirect taxes on fuel, essential commodities, rising road tolls, and higher consumer good prices driven by the increased GST rates. It is evident that this relief is nothing more than a mere illusion, much like Jio's once free data plan attracting millions of users at a time and then, they raise the tariff sharply which now comes monthly at a hefty price tag. The Government claims to provide relief but the reality for the middle class tells a different story.

Let me give you another small example. These are real examples. The Government claims an Rs. 80,000 tax benefit for an individual whose income is Rs. 12 lakhs annually. But it is nothing but a misleading farce. They thump their chest about relief while simultaneously bleeding the common taxpayer, strike through GST and unchecked inflation. A taxpayer in this income bracket, that means, someone who is earning Rs. 12 lakh annually spends on essential categories like food, housing, education, healthcare, railway travel, air travel, transport, recreation and each of these are subjected to steep GST rates under NDA's failed economic policies. The result, if you do a quick calculation, you will see that someone earning Rs. 12 lakh ends up inadvertently paying Rs. 98,000 in GST. So, the illusion of Rs. 80,000 tax benefit that BJP is desperately trying to sell, in reality, it snatched away through GST alone. That means, someone earning Rs. 12 lakh has to pay advertently Rs. 98,000 on account of GST alone. Then, you have surcharges, you have cess, you have toll tax and many other taxes. You have STT, securities tax. Why am I talking about GST? It is because whatever one requires to exist, from medicines to tea, from toiletries to tooth paste, from hair oil to cooking oil, from fuel to oxygen cylinders, from rice to sugar, from butter to ghee, from under garments to footwear, from biscuits to even pop corn at the movies, everything is taxed.

(1355/SM/IND)

In fact, more is lost to GST than they claim to give back. To make matters worse, there are several other taxes as I mentioned. There is toll tax; there is security transaction tax; there are cesses; there are surcharges; and then there is inflation also, which continues to erode whatever little remains. With an average 6 per cent annual inflation, if someone is earning Rs.12 lakh today, it will shrink down to Rs.10 lakh in three years. The only thing that is not taxed, or rather untouched, is BJP's list of misleading promises and their sheer incompetence. That is only untaxed.

The Budget remains completely a failure and the budget also reminds me from a scene from a popular movie, 3 Idiots. All of us have seen the movie. It went very popular, and irrespective of caste, creed, and religion, everyone loved the movie. Madam, the Budget reminds me of the movie 3 Idiots where Shri Aamir Khan's character, 'Rancho', exposes the education system's obsession with rote learning over genuine understanding.

Similarly, today's Government reminds me of the deceptive college director, 'Virus' of that movie and the role of Virus was played by Shri Boman Irani. I am not talking about the viruses present here. I am talking about the college director 'Virus'. So, what the college director, 'Virus' used to do? He used to offer flashy numbers, grand schemes that prioritised ranking over real progress. Much like Virus, the focus seems to be on the surface level, over real achievements, presenting a polished image rather than addressing the true needs of the people.

If we take a page from the history, the British, during the colonial rule, promised reforms while continuing to exploit India's resources. BJP's Budget follows the same playbook, advertising tax relief while ensuring the burden is transferred through hidden economic policies that favour big corporations and the elite, leaving small businesses and working class struggling.

Madam, the Budgets presented over the last one decade perfectly sum up India and the BJP's version of *Achhe Din*, reflecting not just their grand narrative but also the harsh reality of common people's struggle under the NDA's rule and regime. If I am a citizen of India, I have to pay tax on the money I earn. If I am a citizen of India, I have to pay tax on the money I spend. If I am a citizen of India, I have to pay tax on the things I buy and I have to pay tax on the things I sell. Moreover, I have pay tax on things that are already taxed which I bought with the money which is also taxed.

Just imagine, you earn, you pay tax; you spend, you pay tax; you buy, you pay tax; you sell, you pay tax; and then you pay tax on things that are already taxed from the money which is already taxed. This sums up the Budget completely.

The people of India have woken up and they will no longer be misled by these empty promises and false claims. The Government must pay attention to the aspirations of 140 crore citizens. If they do not, they should brace themselves. What started as a teaser in June, 2024 will soon become a full-blown blockbuster. After all the saying goes, never underestimate the power of the common man. Every Indian who is watching this, who has seen the Budget, who has voted in 2024 and is going to vote again, exercise their franchise, they are far better scriptwriters than the BJP Members of this House. India now sees the truth clearly. BJP stands for Bhashan, Jumla and Propaganda, where speeches replace real action and NDA stands for, well, no prize for guessing, Not Delivering Anything.

Thank you, Madam. Jai Hind.

(ends)

(1400/RP/RV)

1400 hours

SHRI DAGGUMALLA PRASADA RAO (CHITTOOR): Hon. Chairperson, I am deeply grateful for the opportunity to address this transformative and growth-oriented Budget. I extend my heartfelt thanks to the hon. Finance Minister for presenting the Viksit Bharat Budget. With India projected to contribute 15 per cent to global economic growth between 2024 and 2029, this Budget embodies the vision of a self-reliant, prosperous nation.

Under the dynamic leadership of Nara Chandrababu Naidu Garu and the NDA Government, Andhra Pradesh has seen crucial developments, such as the revival of the Visakhapatnam Steel Plant with an allocation of Rs. 11,440 crore and the timely establishment of the South Coast Railway Zone. Moreover, Rs. 15,000 crore allocation for Amaravati's development and the ongoing progress of the Polavaram Project further highlight the Government's commitment to regional growth. This is due to the synchronised governance of the NDA Government under the leadership of the hon. Prime Minister.

This Viksit Bharat Budget is designed to create a robust foundation for growth through three key strategies. One is that the income limit is set at Rs. 12 lakh. As the hon. Finance Minister was saying, the Government is set to lose an amount of Rs. 1 lakh crore. It will be given to the people. If only 20 per cent of the amount will be saved and 80 per cent spent in the market, then around Rs. 80,000 crore will be spent into the market. If this spending will take place, the business will improve. As a result, the employment opportunities will increase. Take for example the online purchasing. The companies like Zomato and Swiggy will employ more people to cater to the needs of the people. Other tax proposals also include reduction in TDS limits.

Secondly, the Government has focused on credit creation by providing facilities across all sectors. For agriculture, the Kisan Credit Cards offer short-term loans to 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. For micro enterprises, customized Credit Cards with a Rs. 5 lakh limit are available *via* the Udyam portal. The 'Grameen Credit Score framework for rural areas and self-help groups further encourages credit creation, leading to a higher money multiplier effect, increased investment contributing to the vision of a Viksit Bharat.

Thirdly, the reduction in basic customs duties on several products, such as drugs and leather, aims to reduce import dependency. The Government has taken the decision to reduce the import dependency in fertilisers, particularly, urea. One example of reducing import dependency is the revival of urea plants in Assam. In 2022-23, India imported 7.58 million tonnes of urea. The revival of three urea plants in Assam will help reduce this import dependency, boost domestic manufacturing, and foster self-reliance, strengthening the economy and moving us towards a Viksit Bharat.

Therefore, boosting consumption, increasing credit, and incentivizing domestic manufacturing are key methods to create wealth. This Viksit Bharat Budget strikes a perfect balance between wealth creation and welfare measures, ensuring that economic growth benefits all sections of society.

The Budget places a strong emphasis on empowering marginalized and vulnerable communities, particularly focusing on women, children, and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. To foster entrepreneurship and innovation within these communities, a new scheme has been introduced to support first-time entrepreneurs from Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and women. Under this initiative, term loans of up to Rs. 2 crore will be provided over the next five years for building on the successful framework of the Stand-Up India scheme. This step will empower individuals from disadvantaged communities to start their own businesses, creating economic opportunities and contributing to their socio-economic upliftment.

The Budget for the Department of Social Justice for the financial year 2025 has seen a remarkable increase of 35.76 per cent compared to the revised estimates, underlining the NDA Government's unwavering commitment to improving the socio-economic conditions of marginalized communities.
(1405/NKL/GG)

These increased allocations will play a crucial role in ensuring inclusive growth and providing equitable opportunities to all.

For women, the Budget introduces several measures to promote their welfare. The key highlight is the Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 programme which provides nutritional support to more than eight crore children, one crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls.

The Budget also recognizes the importance of children's welfare, with increased allocations aimed at enhancing educational opportunities. Programmes like Samagra Shiksha and PM-SHRI have seen significant hikes, ensuring better access to quality education. The allocation for Samagra Shiksha is set to rise from Rs. 37,499 crore in 2024-25 to 41,249 crore in 2025-26. Similarly, PM-SHRI's budget increases from Rs. 6,050 crore to Rs. 7,500 crore. These increases will facilitate better infrastructure, resources, and quality education, setting a strong foundation for the future of our children and enabling them to contribute meaningfully to the nation's growth.

The National Rural Livelihood Mission Budget will rise from Rs. 15,047 crore to Rs. 19,005 crore, which will directly benefit rural communities by enhancing livelihood opportunities and supporting sustainable development. This allocation will enable marginalized groups to access vital resources, education, and opportunities, promoting economic and social inclusion.

In conclusion, the Viksit Bharat Budget is a remarkable testament to the perfect harmony between wealth creation and welfare, paving the way for inclusive and sustainable growth. For Andhra Pradesh, the future shines brightly as the State's strategic developments, boosted by this visionary Budget, will undoubtedly position it as a vibrant engine driving India's rise. As we work together towards a Viksit Bharat, Andhra Pradesh will stand tall as a shining example of progress and prosperity.

In addition to this, I would like to give a few suggestions. I would request the hon. Finance Minister to keep an eye on fiscal deficit and interest payments which are increasing. The benefits of the Government schemes for the downtrodden sections like SCs, STs and BCs are not reaching the targeted people. One such example is that the allocation for food supply in the Budget is major but this is being merged with the PDS. This is a kind of a thing which is allocated in addition to the regular Budget but it has been merged into this. So, I would like the hon. Finance Minister to consider this.

With this, I once again thank you for giving me the opportunity.

(ends)

1408 बजे

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, मैं वर्ष 2025-26 के आम बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वित्तीय वर्ष 50,65,345 करोड़ रुपये का कुल खर्च का बजट प्रस्तुत किया है। जिमसें उनका आंकलन है कि आय से 34,96,409 करोड़ रुपये होंगे एवं बाकी धन अन्य स्रोतों से प्राप्त होगा। यह सरकार का काफी उदार बजट है, जिसकी काफी सराहना हो रही है। मध्य वर्ग को आय की सीमा में 12 लाख रुपये तक की छूट से मध्य वर्ग एवं वेतनभोगी वर्ग काफी खुश है। साथ ही, टीडीएस में छूट भी आम नागरिकों को टैक्स में राहत देने का काम करेगी। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज पर वर्तमान टीडीएस 50 हज़ार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करना, इसी प्रकार किराये की आमदनी पर टीडीएस की वर्तमान सीमा दो लाख 40 हज़ार रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये कर देने से आम जनता को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार टैक्स प्रणाली में उदारता और सरलीकरण का लाभ कर दाताओं को मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय वित्तमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ।

माननीय वित्तमंत्री जी ने बजट प्रस्तुति के क्रम में कहा कि बिहार में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी, जिसमें करीब 50 हज़ार हैक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इसी तरह पूर्वी कोसी नहर के लिए भी सहायता दी जाय।

(1410/CP/VR)

यह परियोजना पूर्णरूपेण केन्द्रीय परियोजना के रूप में चलनी चाहिए। अगर राज्य को इस परियोजना में भागीदारी दी गई, तो वैसे ही बिहार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव परियोजना को विलम्ब की ओर ले जाएगा। अत: केन्द्र सरकार कोसी नहर परियोजना को केन्द्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृति दे। यह मेरी मांग है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने पटना और बिहटा के एयरपोर्ट के विस्तार के अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव किया है। यह काफी सराहनीय कदम है। इससे उस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार सरकार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने क्षेत्रीय उड़ान योजना के अंतर्गत सहरसा एवं वीरपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दिया है। इसका प्री-फीजिबिलिटी सर्वेक्षण भी हो चुका है। इसकी शीघ्र मंजूरी देकर उसे प्लेन चलाने लायक बनाया जाए, जिससे वहां के लोगों को भी विमान की सुविधा मिल सके। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आशा है कि यह बोर्ड जल्द ही स्थापित होगा, जिससे मखाना किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा।

सभापति जी, मैं बिहार राज्य के कोसी क्षेत्र से आता हूं, जहां बाढ़ विशेष रूप से प्रतिवर्ष जनमानस के लिए कठिनाइयों को लेकर आती ही रहती है। पूरा कोसी क्षेत्र एवं उत्तरी बिहार प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक केन्द्र एवं राज्य सरकार बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए अथक प्रयास करती रही हैं, किन्तु सारे

प्रयास एवं परियोजनाएं असफल ही साबित हुईं। एक ठोस एवं कारगर नीति अभी तक नहीं बनी। वहां आम जनता को भारी जान-माल की क्षति हाती है और उनकी पूरी की पूरी कमाई बाढ़ में बह जाती है।

सभापति जी, मैं कोसी क्षेत्र में बाढ़ की विनाशलीला को पिछले सात दशकों से देखता आ रहा हूं। अनुभव के आधार पर मैं पुन: केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार नेपाल सरकार से बात करके नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी, जो प्रत्येक साल बिहार को तबाह करती है, वहां वह बराह क्षेत्र में हाईडैम बनाए। पानी को बरसात के समय वहीं पर नियंत्रित करने से बिहार में बाढ़ की समस्या से निदान मिल सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार को भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञों की राय राज्य सरकार के पास है। कोसी नदी में प्रत्येक साल अत्यधिक गाद, मिट्टी आने से नदी का सतह ऊंचा होने से पानी अनियंत्रित हो जाता है और नदी तबाही मचाती है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि एक योजना बनाकर कोसी नदी से गाद निकाली जाए।

सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने रेलवे के लिए बिहार को 10 हजार 66 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। यह अपर्याप्त है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं सहरसा से नई दिल्ली के लिए एक जोड़ी वन्दे भारत स्लीपर ट्रेन एवं पटना-पूर्णिया अमृत भारत ट्रेन के परिचालन की मांग करता हूं। वैसे तो मैं रेल मंत्री जी को अपने क्षेत्र की रेल संबंधी समस्याओं से समय-समय पर पत्रों के द्वारा और सदन के माध्यम से संज्ञान में लाने का काम करता हूं, किन्तु अभी भी बहुत सारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। सहरसा-मानसी रेलखंड का दोहरीकरण और सहरसा-लहरिया सराय रेल लाईन निर्माण की स्वीकृति दी जाए।

यह मेरे लिए और देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्थ जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। सरकार का पूरा फोकस इस दिशा में काम कर रहा है। इससे देश जल्द ही विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढेगा। सभी प्रयासों के बावजूद चीनी सामान एवं वस्तुओं का अभी भी सस्ता और आकर्षक होना एक प्रश्न है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

मैं अंत में गरीब, मध्यम वर्ग, युवाओं, किसानों एवं अन्नदाताओं को ध्यान में रखकर उनके विश्वास को बढ़ावा देने वाले बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं एवं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इति)

(1415/NK/SNT)

1415 बजे

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : सभापति महोदय, आपकी इजाज़त से बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और न ही यह मेरा विषय रहा है, मैं एक साधारण विद्यार्थी रहा हूं। एक आम नागरिक होने की हैसियत से आम लोगों की जो भावनाएं हैं, मैं उसको आपके सामने और सदन के सामने रखने की इजाज़त चाहता हूं।

हर वर्ष की तरह इस बार भी आंकड़ों के जाल में सरकार द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, वह बहुत ही अफसोसनाक और चिंताजनक है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के उत्तर में जिस प्रकार से गलत बयानी से काम लिया गया, वह आश्चर्जनक है। शायद देश के मशहूर शायर ने इसी अवसर के लिए यह पंक्ति लिखी थी:

"वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीक़े से, मैं ऐतबार न करता तो और क्या करता"

यही हालत इस देश की सरकार की हो गई है। मोदी सरकार ने वर्ष 2024 लोक सभा चुनाव से कोई सबक सीखने की कोशिश नहीं की, जो परिणाम आए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और सरकार को इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि आने वाले समय में ऐसा बजट देना है, ऐसा कदम उठाना है, ऐसा रोडमैप बनाना है, जिससे देश की मुख्य समस्याओं को दूर किया जा सके, उसका रास्ता निकाला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने सोचा था कि आने वाला बजट एक ऐसा दस्तावेज होगा, उस दस्तावेज में गरीबी कम करने, बेरोजगारी दूर करने और कुछ ऐसे उपाय बताए जाएंगे, जिससे महंगाई से आम लोगों को निजात मिल सके। लेकिन मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में कोई भी कारगर उपाय नहीं सुझाये गये।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने वक्तव्य पर दावा किया कि पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। मैं सरकार से कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गरीबों की संख्या घटी है तो उपभोग दर में कमी क्यों नहीं आई। अगर सिर्फ 15 करोड़ लोग गरीब बचे हैं तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर वाकई में गरीबी घटी है तो नीति आयोग के इस दावे को विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। गरीबी मापने के मानक क्यों बदले गए? नरेन्द्र मोदी की सरकार रुपये की लगातार गिरती कीमत को रोकने में असफल है। पहली बार रुपये 87 के पार पहुंच गया है। इस असफलता की कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस की सरकारों ने गरीबी हटाने के लिए ठोस कदम उठाये, अक्सर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम गरीबी हटाने का सिर्फ नारा नहीं देते हैं बल्कि हम उसके लिए काम करते हैं, उसके उपाय ढूंढ रहे हैं।

(1420/KDS/AK)

मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में गरीबी को दूर करने का मात्र नारा नहीं दिया था। हमारे लिए गरीबी हटाओ केवल एक नारा नहीं था। इंदिरा जी की सरकार से लेकर

उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने गरीबी हटाने हेतु वास्तविक योजनाएं बनाईं और उनको लागू किया। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसी नीतियों ने देश के गरीबों की मदद करने की कोशिश की। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राजाओं का प्रिवीपर्स खत्म किया गया। लैंड रिफॉर्म हुआ। ऐसे कई प्रगतिशील कदम उठाए गए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स जैसी तमाम योजनाओं को हमने शामिल किया और उसे आगे बढ़ाने का काम किया, ताकि उसका लाभ आम लोगों, खासकर गरीबों को पहुंचे।

महोदया, इस बजट में बिहार का जिक्र है, अत: उस पर दो शब्द कहना चाहता हूं। बिहार को केवल भाषण मिले हैं। इस बजट में बिहार का जितना जिक्र हुआ, उतना किसी और राज्य का नहीं हुआ। लोगों को यह गलतफहमी हुई कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। वित्त मंत्री जी की मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी की चर्चा तो हो रही है, लेकिन बिहार के विकास की नहीं। हमें बजट भाषण नहीं, वास्तविक आवंटन चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो वायदा किया गया था, उस पर अमल नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि बिहार और झारखंड बंटने के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। आज हमारे पास उद्योग, खनिज, कल-कारखाने नहीं हैं। हम पूरी तरह से केवल कृषि पर निर्भर हैं। ऐसी हालत में बिहार को विशेष राहत या विशेष पैकेज देने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वह सही ढंग से नहीं हुई है। केवल गोल-गोल घुमाने का काम हुआ है। मखाना बोर्ड का जिक्र तो हुआ, लेकिन उससे कितनी वित्तीय मदद मिलेगी, इसकी कोई जानकारी इस बजट भाषण में नहीं है। देश को बजट से काफी उम्मीद थी।

महोदया, पिछले बजट से इस बजट के बीच 2.5 लाख करोड़ का अंतर आया है, लेकिन इसमें से मात्र 4 हजार करोड़ रुपये, खेती-किसानी में और एक हजार करोड़ रुपये ग्रामीण विकास में दिए गए हैं। आखिर यह पैसा जा कहां रहा है, हम जानना चाहते हैं। यह एक सवाल है। ग्रामीण विकास का बजट घटा दिया गया। शिक्षा के लिए आवंटित राशि में कमी कर दी गई। खाद और फूड सब्सिडी में कटौती कर दी गई। मनरेगा का बजट नहीं बढ़ाया गया। किसानों को आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी का इंतजार है। जब सरकार को-ऑपरेटिव्स का 16 लाख करोड़ रुपये कर्ज माफ कर सकती है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का खर्च, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपये आएगा, वह उठा सकती है, तो क्यों नहीं किसानों के लिए 26 लाख करोड़ रुपये खर्च करके हम एमएसपी सुनिश्चित कर सकते हैं? एमएसपी के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा।

महोदया, देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आय घट रही है। महंगाई चरम पर है। इसका सीधा असर आम जनता की बचत पर पड़ा है। घरेलू बचत 50 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। लोग अपने गहने गिरवी रखने को मजबूर हो रहे हैं। यह संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है। ऋण चुकाने में असमर्थतता के कारण डिफॉल्ट के मामले 30 प्रतिशत बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, पिछले बजट में प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा हुई थी, जिसमें 5 साल में एक करोड़ युवकों को टॉप 5 सौ कंपनियों में इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया था।

(1425-1435/SRG/SPS)

हकीकत यह है कि एक साल में मात्र 28,141 उम्मीदवारों को इंटर्नशिप मिली है। यानी लक्ष्य का केवल 0.28 परसेंट ही पूरा हुआ है।

महोदया, जीडीपी ग्रोथ दर गिर रही है। सरकार भले ही प्रचार-प्रसार कर रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। इस वर्ष जीडीपी ग्रोथ दर मात्र 6.4 परसेंट रहने वाली है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है। मोदी सरकार चाहकर भी यह नहीं छुपा सकती है कि यूपीए के दस वर्षों में जीडीपी ग्रोथ औसत 7.5 परसेंट थी, जबकि मोदी सरकार के दस वर्षों में यह मात्र 6.5 परसेंट रह गई है। एफएमसीजी कंपनियों की रिपोर्ट बताती है कि छोटे पैकेजों की मांग बढ़ रही है, यानी लोग जरूरी सामान भी कम मात्रा में खरीद रहे हैं।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ केवल 5.3 परसेंट रह गई है और माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ 7.1 परसेंट से घटकर 2.9 परसेंट हो गई है। निवेश क्यों नहीं हो रहा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में भी हम माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहेंगे। भारतीय उद्योगपति प्रधानमंत्री जी की तारीफ तो करते हैं, लेकिन निवेश करने से बचते हैं। इसकी क्या वजह है?

सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग, बदले की राजनीति, अत्यधिक टैक्स और कठोर नीतियों से सरकार आम आदमी से जीएसटी के नाम पर अत्यधिक कर वसूल कर रही है। आटा, दही, दवा, शिक्षा, पॉपकॉर्न और यहां तक कि पुरानी कारों पर भी भारी टैक्स लगाया जा रहा है। इन्कम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा वसूली अब आम आदमी से की जा रही है।

ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना अधूरा है। सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा किया था। अब वर्ष 2025 भी आ गया है, लेकिन यह लक्ष्य आज भी दूर की कौड़ी है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें हर साल 10 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ चाहिए, जो इस सरकार के बस की बात नहीं है।

महोदया, निष्कर्ष यह है कि यह सरकार केवल प्रचार और दावों में विश्वास करती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही बयां कर रही है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह प्रचार से हटकर देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, युवकों और गरीबों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे। धन्यवाद।

(इति)

1429 hours

*SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH *ALIAS* PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon'ble Madam Chairperson, thank you, I rise to discuss the Union Budget for the year 2025-26. At the outset, before I start my speech, I would like to draw the Central Government's attention towards an important issue. As you are aware, today the farmers are compelled to sell soyabean at the rate of Rs. 3800-3900 per quintal but, earlier the rate was Rs. 11000 per quintal. The Union Government had started guaranteed agricultural procurement centers.

Since 10th December, 2024, around 44013 farmers registered themselves on agricultural procurement portal. Out of it, 15749 farmers successfully sold their produces during last 2 months. Yesterday, it was last day and still around 2800 farmers are waiting for their turns. So, it is my earnest request to Union Government to honour their struggle for livelihood, and the last date for procurement of soyabean should be extended. I personally met Hon'ble Agriculture Minister in this connection and drew his attention towards this issue.

While discussing this Union Budget, I would like to draw your attention towards the declaration made by Hon'ble Prime Minister in the year 2016 about doubling the farmers' income till 2022. Hon'ble Chairperson, that did not happen but the production cost has been doubled since then. You know, the farmers who earn their bread and butter through farming activities also have to take care of their families.

But now a days farming has become loss making profession. Whenever the procurement price touches Rs. 11,000 mark, Union Government immediately intervenes. You reduce the import duty on Palm oil. You also start importing soyabean cakes too. Due to this unnecessary intervention of Union Government, the farmers are now bound to sell soyabean at Rs. 3800 per quintal.

---

* Original in Marathi

Madam Chairperson, whenever the rates of onion go up, the Union Government intervenes timely to ban export of onions. Any industrialist who produces cement or steel, allowed to fix his profit margin, then why is it not permitted to farmers? A farmer works very hard in his farm relentlessly, so he must get respectable income in return and that should be ensured by Central Government.

The problem which is there with soyabean and onions, the same is applicable in case of milk too. In my Lok Sabha Constituency, at places like Bhum, Paranda, Vashi and its surroundings, 'khowa' or milk solids industry is booming. Kunthalgiri Pedha is very famous. Unfortunately, a cheap quality adulterated khowa is being supplied at the rate of Rs. 70-80 per kg from Gujarat State. That is why the local farmers are now compelled to sell their khowa at the rate of Rs. 120 per kg. The Union Government should ban this adulterated khowa immediately to stop health losses of common man.

Madam, Shri Pashabhai Patel , Chairman, Maharashtra State Agricultural Price Commission, has requested the Union Government to fix MSP of Rs. 7000 per quintal for soyabean after adding only 15% profit. But, the Government fixed Rs 4892 per quintal as an MSP for soyabean. In this way, the Government did not allow the farmers to earn minimum 15% profit on soyabean.

Madam, we keep on passing many legislations on different issues and subjects. Now, it is time to bring a legislation for farmers to fix their income and profit on the basis of production cost. When the UnionGovernment would come forward to make farming a profitable business? Kindly do something in this connection.

In this budget, it is declared that there would be no tax up to the income of Rs. 12 lakh. But, due to the Government's policies, the farmers in my area are committing suicides. And when a farmer dies,

the Government provides Rs. 1 lakh as compensation. Can any farmer ever get benefited through your this tax exemption scheme?

In this budget, you talked about crop insurance scheme too. But I would like to show you the reality of this scheme. You must know that around Rs. 42,000 crore have been paid to insurance companies comprising State and Central Government shares as a premium. In return, the claimed amount is around Rs. 36,300 crore. It means, around Rs 5700 crore have been earned by these insurance companies as a profit in my Maharashtra State only.

I want to bring it to your notice that Rs. 17000-18000 per hectare are being paid to insurance companies as a premium. But, unfortunately these insurance companies never pay the compensation matching the premium amount. So, the Union Government should review this scheme. Earlier only Government insurance companies were allowed to participate in this scheme but, now the private companies like Reliance General Insurance, HDFC Argo, Bajaj Allianz, Bharti Axa, ICICI Lombard are engaged in crop insurance scheme. These companies are solely concentrating on profiteering. Instead of paying Rs. 18000 to these companies, the Government should directly pay this amount to the farmers.

The infrastructure for the farming is also very important. Availability of water and electricity is also important. During Atal Behari Regime, very ambitious river interlinking project was declared. The flood and excess water should be diverted towards the drought-affected areas and that was the core idea. But today nobody is ready to talk about it. Government of the day should take initiative in this direction.

I would like to draw your attention towards an important rail-line project. In the year 2014, it was decided to connect Tuljapur with railway line. But the administrative approval was given only in 2019. The initial

project cost was Rs. 904 crore then. Since 2019, around Rs. 1026 crore have been allocated for this project. But today, due to cost escalation, around Rs 3000 crore are needed to complete this project and you have made a provision of only Rs. 225 crore in this budget. In future, due to cost escalation, you would have to make provision of Rs. 6000-7000 crore to complete this project, if you fail to complete this project within stipulated time.

Now, I would like to speak on PM Jan Aarogya Yojana. If a patient needs a surgery, he is referred to a particular hospital under this scheme. But the doctor says this disease is not in the list, our hospital is not entitled for the treatment. The total cost of treatment is not payable under this scheme. In this case he has to sell a piece of land to bear the cost of treatment. We can help only 3 patients per month. There are lacs of people waiting for treatment, so how can we manage? The Union Government must think about it. An all-inclusive scheme, which will cover all kinds of diseases, should be brought by the Government so that no poor patients would be deprived of the health and medical benefits of such a scheme.

(ends)

(1440/MM/RCP)

1442 बजे

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से देश की माननीय वित्त मंत्री जी, जिन्होंने आठवां भारत का स्वर्णिम बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं मोदी जी के लिए कहना चाहता हूं – मैं सितारा नहीं हूं सूरज हूं, गहरा रिश्ता है मेरा मिट्टी से। ऐसे माटी पुत्र, यशस्वी प्रधान मंत्री, युगद्रष्टा माननीय नरेन्द्र मोदी जी के संकल्पों के स्वर्णिम भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बने, ऐसा सर्वप्रिय बजट प्रस्तुत करने पर बहुत-बहुत बधाइयां।

इस अवसर पर माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के श्रेष्ठ मंत्री श्री जेटली जी को भी उन्हीं के शब्दों में स्मरण करना चाहूंगा, जो उन्होंने वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में कहे थे-

कश्ती चलाने वालों ने जब हारकर दी पतवार हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मझधार हमें।
फिर भी दिखाया है हमने और फिर यह दिखा देंगे सबको
कि इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें।

बजट का मजमून क्या है, उसकी कल्पना क्या है, बजट का इशारा क्या है? बजट का इशारा है, मोदी जी के संकल्प, शक्तिशाली भारत, आदर्श भारत, गरीब कल्याण को समर्पित भारत, जहां सभी को न्याय मिले और जहां सभी प्रसन्न हों। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस दृढ़ विचार के साथ वर्ष 2047 का विकसित भारत बने, जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गयी। उसी आधार को मजबूत करने वाला यह बजट आज देश और दुनिया में भारत की ख्याति बढ़ा रहा है। वर्ष 2012-13 में बजट के केन्द्रीय सेक्टर में व्यय 13 लाख 14 हजार 242 करोड़ रुपये था और आज का बजट जो देश की यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह है- 50 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का विशाल बजट। यह बजट बताता है कि दुनिया के ज्ञात इतिहासों में कोई देश, कोई इकोनॉमी अपने बजट का आकार चार गुणा कर ले तो वह सिर्फ मोदी जी के भारत का बजट ही हो सकता है।

(1445/YSH/PS)

"मेहनत कर मंजिल भी मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा,
इज्जत भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा,
साधनों की कमी के कारण होना मत उदास कभी,
इरादे अगर नेक हों तो आशीर्वाद रूपी लक्ष्मी जरूर होगी साथ,
जिंदगी में ऐसी भी नौबत आई, था आगे कुआं तो पीछे खाई,
तलाशा मोदी जी ने सकारात्मक दृष्टिकोण, कुएं से जानलेवा प्यास बुझाई,
और समझ खाई को बहुसागर सार आकांक्षा में डुबकी लगाई।"

हम देखते हैं कि बजट में सर्वप्रथम अन्नदाता कृषकों के जीवन की बेहतरी हेतु विचार किया गया। यह विचार धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा से हुआ। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आकांक्षी जिलों की श्रीवृद्धि से देश प्रसन्न था और आज हम देख रहे हैं कि कम फसल बुवाई वाले 100 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चयनित किया गया है, जिसने 1 करोड़ 70 लाख कृषकों के जीवन में नया उजाला भर दिया है। उन्होंने दलहन में आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया, बल्कि इतना ही नहीं तूर, उड़द, मसूर पर विशेष फोकस किया और यह संकल्प लिया कि जितना उत्पादन लाओगे, उन सभी को खरीदा जाएगा। सब्जियों, फलों और श्री अन्न पर कभी सरकारों ने ध्यान दिया था? क्या प्रसंस्करण पर कभी सोचा गया था? किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों की भागीदारी कभी सुनिश्चित की गई थी? मखाना बोर्ड बनेगा। अभी तारिक भाई कह रहे थे कि मखाना बोर्ड बनेगा, लेकिन इसमें बजट नहीं है। शायद आजकल कांग्रेस के लोगों ने बजट पढ़ना ही बंद कर दिया है। उसमें 100 करोड़ रुपये का प्रोविजन पहले से ही किया गया है।

बीज मिशन भी आएगा। कपास उत्पादक मिशन, विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोगों का वाहक बनेगा और केसीसी 7 करोड़ 70 लाख कृषकों के जीवन का आधार बनेगा। यूरिया उत्पादन की तरफ भी फोकस किया गया है और साथ ही 1 लाख 50 हजार ग्रामीण डाकघरों को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार दिया गया है। ग्रामीण भारत में स्वामित्व का आधार देकर सम्पत्ति कृषकों के नाम कर दी गई। मैं समझता हूँ कि इस पावन धरा का यह सबसे कठिन व महान कार्य मोदी सरकार द्वारा हुआ है। निश्चित ही यह माइलस्टोन है। यह यादगार है।

एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी के लिए 1 लाख 71 हजार 437 करोड़ रुपये की विशाल राशि दी गई है। जब तारिक भाई और राहुल गांधी जी कृषकों के लिए कह रहे थे तो मैं देख रहा था कि कांग्रेस का फोकस इन चीजों पर है ही नहीं। इसलिए मैं बजट के पन्ने उठाकर लाया हूँ। मैं बजट में प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय के बारे में बताना चाहता हूँ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड रुपये दिए गए हैं। कृषोन्नति योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। एनएफएस के अंतर्गत खाद्यान्नों को राज्य के भीतर लाने व ले जाने के लिए 7 हजार 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण के लिए 12 हजार 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 2 हजार 464 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पशुपालन और डेयरी के लिए 1 हजार 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई के लिए 8 हजार 260 रुपये दिए गए हैं। नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 8 हजार 336 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इंटरलिंकिंग रिवर, अद्भुत जल जीवन मिशन के लिए 67 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए ये कह रहे थे कि बजट ही नहीं है तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 86 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन यहां स्पष्ट दिख रहा है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन, खैर ये कभी जिएं हों तो पता चलेगा, उसके लिए 19 हजार करोड़

रुपये दिए गए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए 54 हजार 832 करोड रुपये दिए गए हैं। वाटर शेड विकास योजनाओं के लिए 2 हजार 505 करोड़ रुपये दिए गए हैं। महलों में रहने से वाटर शेड क्या होता है, यह पता नहीं चलता है। अंत्योदय ग्रामीण जीविका मिशन क्या है, इसे वे समझते नहीं हैं। सक्षम आंगनवाड़ियों के लिए 21 हजार 960 करोड़ रुपये दिए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए अभी हमारे अपोजिशन के लोग कह रहे थे कि कोई राशि नहीं दी गई है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए 12 हजार 242 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, पीएम आशा के लिए 6 हजार 941 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के लिए क्या आपने कभी पूछा कि किसानों के पॉकेट में कितना पैसा जाता है। उसी के लिए 63 हजार 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(1450/RAJ/SMN)

कपास तकनीकी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए, दलहन मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए, सब्जी-फल मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए, हाइब्रिड बीज मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए, मखाना बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए है। भाई, पढ़कर आया करो। खाद्य सब्सिडी के लिए 1,18,900 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 2,03,000 करोड़ रुपए, मिशन मौसम के लिए 1,329 करोड़ रुपए, पशुधन के स्वास्थ्य के लिए 1,980 करोड़ रुपए का प्रावधान है कभी पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम में गए हो, तो पता पड़ेगा ना! डेयरी विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए, खादी ग्रामोद्योग विकास के लिए 1066 करोड़ रुपए, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 51,000 करोड़ रुपए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना के लिए 2,600 करोड़ रुपए और पीएम मुफ्त घर सूर्य बिजली योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एलपीजी के लिए 1500 करोड़ रुपए, गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस के लिए 9100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मैं पूरा बजट नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैंने सिर्फ किसानों के लिए जो किया गया है, वही आपको बताया है। सबको आवास, सबको जल, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको राशन, सबको बिजली मिलना अभूतपूर्व है। सही मायने में यही राम राज है।

“दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।
सब नर करहिं परस्पर प्रीती, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।”

अर्थात राम राज में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप किसी को नहीं व्याप्ते हैं, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं। भारत में राम राज की स्थापना हुई है। जब राम राज की बात होती है तो कांग्रेस या विरोधी पक्षीय समझते हैं कि हिंदू राज की स्थापना होगी। वे राम राज की स्थापना हर तरह के सुख व समृद्धि, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जीने का अधिकार, सुरक्षा, न्याय का अधिकार सभी को मदद मिले, मगर कुछ लोग तो राम राज का माखौल उड़ाते हैं। लोकतंत्र की रक्षा, देश की मर्यादा राम राज में सुरक्षित है और राम राज तो भारत का भी राज था। भागवत और जैन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। राजा हरिश्चंद्र, राजा सुदास, भगवान राम, राजा युधिष्ठिर चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त तृतीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजा भोज, ये सब राम राज की

कल्पनाओं के राज्य हैं, जिसको कभी कांग्रेस ने नहीं देखा। मगर महात्मा गांधी के सपनों के राम राज की बात तो पढ़ ली होती कि राम राज की विधि के बारे गांधी जी क्या कहते हैं? राम राज की विधि या धर्म संवत मर्यादा की अवधारणा केवल राजा या शासक के कर्तव्यों का विचार नहीं है, अपितु एक ऐसी समग्र राज्य व्यवस्था की निर्मिति है जिसमें सामाजिक जीवन का प्रत्येक कोना धर्म के चार चरणों सत्य, शौर्य, दया और दान पर अवलंबित है। यह एक ऐसी चतुष्पद व्यवस्था है, जो राज्य और समाज के सभी आधारभूत घटकों को सच्ची श्रद्धा से ओतप्रोत करती है। वे सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, एक ऐसा ईश्वरीय राज है, जहां कोई दुखी और दरिद्र नहीं होगा। सभी शिक्षित और बहुत संपन्न होंगे एवं सभी प्रकार की सुविधा से युक्त होंगे। यह कैसी सामूहिक कल्पना है। नर और नारी अहंकार एवं दंभ से मुक्त होंगे। छल कपट से मुक्त जीवन जीने वाला समाज होगा और महात्मा गांधी इस राम राज के इस स्वप्न को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, रामायण का प्राचीन आदर्श राम राज निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है। मेरे सपनों का राम राज और निर्धन दोनों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करता है।

मैं जिस राम राज का वर्णन करता हूं, वह नैतिक अधिकारों पर आधारित लोगों की संप्रभुता है। राम राज का लक्ष्य पाने के लिए महात्मा ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज की कल्पना करते हुए राजा के लिए कुछ गुणों का उल्लेख किया। यथा लोक वेद द्वारा विहित नीति पर चलना, धर्मशील होना प्रजापालक होना, सज्जन एवं उदार होना और स्वभाव का दृढ़ होना। हम देखते हैं कि आज देश के प्रधान में ये सारे गुण मौजूद हैं। श्री राम में आदर्श राजा के सभी गुण विद्यमान हैं। उन्हें प्रजा प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्रियजन, पूर्वजन, गुरुजन, सबके प्रति राम का व्यवहार आदर्श एवं धर्म अनुकूल है। तभी तो हम देखते हैं कि आज देश में प्रजा को प्राणों से अधिक प्यार किया जाता है, चाहे वह कोरोना काल हो या चाहे विपदाकाल हो। महात्मा गांधी ने जी राम राज की कल्पना की, उसका मूल आधार तुलसीदास की राम राज परिकल्पना है। निश्चित ही यह आदर्श शासन व्यवस्था जिसका मूल आधार लोकहित एवं मान्यतावाद है। राम उत्तर से दक्षिण जोड़ते हैं और इस लिए हम देखते हैं कि आज देश की सरकार काशी से तमिल को जोड़ने का प्रयास, उत्तर से दक्षिण जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है है।

(1455/SK/SM)

यह राम तो है जो अपने राज्य में केवट से अनुनय करते हैं कि नाव पर बिठाओ, उस पार ले जाओ। वह समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति को अपने हृदय से लगाते हैं और जब हम मोदी जी को देखते हैं तो वह भी समाज में अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति के पांव पखारने का काम करते हैं। कोदंडधारी राम, असुर निकंदन राम, अहिंसा और करुणा का प्रतीक राम, गिलहरी और खर-दूषण, मारीच और शूर्पणखा तक को न्याय देने वाले राम हैं, जो भारत के जन-मन में बसे हैं।

आज भारत नई करवट ले रहा है। सबको साथ लेकर चलता हुआ भारत, सर्वत्र बढ़ता हुआ भारत, राम राज्य की नई कथा लिखने की दिशा में बढ़ चला है। राम राज्य पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द है लोक कल्याण, लोगों के लिए समर्पित शासन से राम राज्य प्रारंभ होता है, जो सगुण सकारात्मकता और नैतिक भावना से पूर्णता को प्राप्त करता है। यह एक ऐसी आदर्श स्थिति है. जिसमें कोई उपेक्षित, वंचित और तिरस्कृत नहीं होता है। जिसमें अंतिम व्यक्ति की आवाज शीर्ष तक बिना किसी व्यवधान के पहुंचती है और सुनी जाती है। मेगास्थनीज की इंडिका, फाह्यान का हर्षवर्धन के राज्यकाल में वृतांत, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासन की पौराणिक आख्यान, ललिता दीदी के महान शासक की राजतरंगिणी की आख्यान,

छत्रपति शिवाजी के हिंदू पद पादशाही के सुशासन स्वराज, स्वभव स्वराज सुराज्य की व्यवस्था को भी स्मरण करना होगा।

हम एक बात बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं और हम जानते भी हैं कि आज देश किन स्थितियों में है। मैं 29.04,1914 के मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचार पढ़ रहा हूं –

> "एक दूसरे से हमारे संबंध अत्यंत प्रगाढ़ हैं, जो बिंदु समुद्र से अलग हो जाता है वह सूख जाता है। उसी प्रकार जो जीव अपनों को दूसरे से भिन्न मानता है वह नष्ट हो जाता है। मैं तो यूरोप की आधुनिक सभ्यता का शत्रु हूं और हिंद स्वराज में मैंने अपने इस विचार को निरूपित किया है और यह बताया कि भारत की दुर्दशा के लिए अंग्रेज नहीं बल्कि हम ही लोग दोषी हैं, जिन्होंने आधुनिक सभ्यता स्वीकार कर ली है। इस सभ्यता को छोड़कर हम सच्ची धर्म नीति से युक्त अपनी प्राचीन सभ्यता पुनः अपना लें तो भारत आज ही मुक्त हो सकता है। हिंदू स्वराज को समझने की कुंजी इस बात में है कि मैं दुनियावी प्रवृत्ति से निवृत होकर धार्मिक जीवन ग्रहण करना और ऐसे जीवन में काले या गोरे किसी भी मनुष्य के प्रति हिंसक व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है।"

आज हम विचार करके देखें कि किस तरीके से धर्मवीर गांधी जी कह रहे थे, ऐसा लगता है कि हम रुग्ण समाज में रह रहे हैं। उन्हें क्यों लग रहा है कि रुग्ण समाज में रह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की जिस परिवारवादी रुग्णता में फंस गए हैं गांधी जी, उसमें से उन्हें कुछ दिखता नहीं है। धर्मवीर गांधी भाई, तुम तो अलग गांधी हो, महात्मा गांधी अलग गांधी है, और ये तीनों गांधी अलग गांधी हैं। तुम कौन सी रुग्णता की बात करते हो? मुझे नहीं पता। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से रेखांकित करके जानते हैं कि आज देश में आजादी के बाद जिन हालातो में आपने देश को पहुंचाया है, उस पर आज मंथन करने की आवश्यकता है।

अगर हम देश के आर्थिक विकास को खंगालें तो वर्ष 1951 से 1956 का एक आदर्श वाक्य था - कृषि का विकास। यह भी विदेश से उठाया गया था, हैरोड डोमर मॉडल। भांखड़ा नांगल, हीराकुंड, चंबल, दामोदर वैली यह देश के सामने आई थीं। मैंने इस पर अध्ययन किया, चंबल वाली से मेरा नाता-रिश्ता है। वर्ष 1930 में ब्रिटिश इंडिया ने इंजीनियरिंग कार्य किया था, डिजाइनिंग की थी, स्थल का चयन किया था, टोपोग्राफी बनाई थी और बजट की कल्पना भी आजादी के पहले बना कर रख दी थी। नेहरू मॉडल की जो तुम बात करते हो, वह तुमने उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, यह हम सब जानते हैं।

इन्होंने वर्ष 1956 से 1961 तक औद्योगिक प्रोडक्शन और तेजी से औद्योगीकरण की बात की। हम सब जानते हैं कि देश के प्रथम उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इतिहास गवाही देता है, चितरंजन का लोकोमोटिव कारखाना, सिंदरी का उर्वरक निगम और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स जैसे संस्थान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश को देकर गए थे। धर्मवीर भाई ने टाटा इंस्टीट्यूशन की बात कही है। आजादी के बाद वर्ष 1956 से 1961 टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च ने शोध संस्थान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तब भारत सरकार के नगण्य कार्य थे। आप उदारवादी अर्थशास्त्री बी.आर, शेनॉय को पढ़ें। उन्होंने नोट किया कि घाटे के वित्त पोषण पर निर्भरता परेशानी का नुस्खा होगा। शेनॉय का तर्क था कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण एक युवा लोकतंत्र को कमजोर करेगा। वर्ष 1957 में ही भारत भारी भुगतान के संकट में फंस गया और यह तर्क इसकी पुष्टि करता है।

(1500/KN/RP)

माननीय सभापति जी, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं कि वर्ष 1961-1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना– वर्ष 1966 में रुपये के मूल्य पर पहली बार अवमूल्यन आया और पहली बार उधारी के लिए आईएमएफ का सहारा लिया। वर्ष 1966-1969 रिकॉर्ड पर है, दयनीय विफलता के कारण योजनावकाश घोषित कर दिया गया। वर्ष 1969-1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना – बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। विकास की दर का लक्ष्य 5.7 रखा, मगर वास्तविक स्थिति 3.3 पर थी। वर्ष 1974-1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, रोजगार देंगे के नारे दिए। मगर मोरारजी देसाई आएं, जिन्होंने प्रणाली को बदला। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली और पर्यटन प्रणाली का विकास वहां से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1980-1985 में राशन की दुकानें बंद कर दीं और यहां का नेहरूवादी समाजवाद का स्वयं कांग्रेस ने अंत कर दिया। जिस नेहरूवादी समाजवाद के मॉडल की बात करते हो, वह तो यहां अंत कर दिया गया। वर्ष 1985-1990 में राजीव गांधी जी सातवीं योजना लेकर आए थे और सामाजिक न्याय, गरीबी दूर करना, आश्रय की आपूर्ति, एक बत्ती कनेक्शन का लक्ष्य रखा। वर्ष 2000 तक लक्ष्य को पूर्ण करना लिखा, लेकिन हमें आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1992 से 1997 तक देश में विदेशी मुद्रा का भंडार का संकट था, एक अरब अमरीकी डॉलर शेष रह गए थे। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? कोई बताता है कि लगभग-लगभग दिवालिया राष्ट्र पीवी नरसिम्हा राव जी को सौंपा था। मुक्त बाजार की बात करने वाले ये लोग इस दिवालिया राष्ट्र की कैसी हालत वर्ष 1992-1997 तक करके छोड़ कर गए थे? नौंवी योजना में आर्थिक, सामाजिक विकास, ग्रामीण क्षेत्र की जनता का जुड़ाव, शहरी क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, कृषि, सूचना प्रोद्योगिकी, स्वास्थ्य, सर्वशिक्षा अभियान और योजना व्यय में 48 परसेंट की अभूतपूर्व वृद्धि, समाज में व्याप्त ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने का अगर प्रारंभिक कार्य हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासकाल में हुआ है।

माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से 2025 का भारत – ये स्वर्णिम भारत है। या यूं कहें... (व्यवधान) मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपका विशेष अनुग्रह चाहूंगा। या यूं कहें कि मोदी का भारत यानी भारत का स्वर्णिम काल है, गोल्डन ऐरा है।

“वक्त भारत का है, सपने भी भारत के हैं।
पूरे भी भारत को करने हैं, माना डगर थोड़ी मुश्किल है,
मगर नामुमकिन नहीं। करना यहीं है, समय यही है।
चाहे तो सोना बना दो या चाहे तो अपोजिशन जैसा सोने में समय बिता दो।”

मोदी जी जाग रहे हैं, तभी तो 50 लाख 65 हजार करोड़ का विशाल बजट देख रहे हैं। आज देश देख रहा है कि 8 लाख 76 हजार किलो सोना, 876 टन सोना भारत के बैंकों में रिजर्व है। देश देख रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार, जो एक अरब डॉलर न रहा था, आज 645 अरब डॉलर हमारे पास फोरेक्स से विदेशी मुद्रा का भंडार है। देश को खबर है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा पार कर गए हैं। उजाले की ओर आए हैं, देश को जानकारी है, आज 700 से अधिक मेडिकल कॉलेजेज कार्यरत हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र नीमच, मंदसौर, रतलाम में 3-3 मेडिकल कॉलेज, 3-3 नर्सिंग कॉलेज, तीनों ही निर्मला सीतारमण जी के बजट से, नरेन्द्र मोदी जी के आशीर्वाद से, जेपी नड्डा जी, डॉ. हर्षवर्धन जी, मांडविया जी के स्नेह से बने हैं। आज का बजट बता रहा है कि 75 हजार एमबीबीएस की सीटें पांच वर्षों में और बढ़ेंगी। मेरा संसदीय क्षेत्र भी सीटें बढ़ने का और इंतजार करेगा।

माननीय सभापति जी, विगत वर्षों में भाजपा सरकारों द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने, वर्तमान मुख्य मंत्री मोहन यादव जी ने सिंचाई क्षेत्रफल के विस्तार पर फोकस किया है, जो केन्द्र सरकार के प्रमुख माननीय नरेन्द्र मोदी जी के बिना असम्भव था। प्रधान मंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना या चम्बल नदी पर बनाई गई नहरों द्वारा वर्तमान में शिवना उद्ववहन सिंचाई योजना के कारण मेरा संसदीय क्षेत्र देश का पहला ऐसा संसदीय क्षेत्र बनने जा रहा है, जो उक्त प्रोजेक्टों के पूर्ण होने पर देश का पहला नदी और नहरों से पूर्ण सिंचित क्षेत्र बेनगा। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि मध्य प्रदेश के साथ-साथ मंदसौर संसदीय क्षेत्र पर विशेष कृपा आपकी बनी रहे।

वर्ष 1952 से जनसंघ, भाजपा के मजबूत गढ़ के रूप में कृषक परिवारों ने साथ दिया है। मैं आपके माध्यम से इस आशा-अपेक्षा के साथ देश की वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा, प्रधान मंत्री जी को भी बधाई दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि अपोजिशन बार-बार, बार-बार आरोप लगा रहा है। मैंने तारीक अनवर जी की सारी बातें लिखी हैं, ये कह रहे हैं कि आंकड़ों के जाल में भ्रमित करने का प्रयास है। अरे, एक आध गरीब हटाओ का आंकड़ा भी तो रख देते। एक आध सामाजिक न्याय का आंकड़ा भी अपने शासन काल का रख देते। आप बड़े सलीके से भली बात कर रहे हैं। खेती-किसानी के क्षेत्र में मैंने आपको सारा का सारा गिनवा दिया। आपने कहा कि आठवां वेतन आयोग का खर्चा सरकार उठा सकती है तो अन्य खर्चे क्यों नहीं?

(1505/VB/NKL)

यह भी एक तकलीफ है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कैसे हो गया? आप लोगों के गहने गिरवी रखने की बात कर रहे हैं। देश में किन लोगों के गहने गिरवी रखे हैं? अगर आज आयुष्मान कार्ड न होता, तो हमारे देश में लोगों के पास गहने बचते ही नहीं, इलाज के अभाव में ही लोग तड़प-तड़पकर अपनी जान दे दिये होते। मैं तो देश की वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि जिन्होंने मजदूरों से लेकर किसानों तक, विद्यार्थियों से लेकर गरीबों तक हरेक के कल्याण पर फोकस किया है। हरेक के कल्याण पर फोकस करने के कारण आज राष्ट्रीय राजमार्गों का ऐतिहासिक विकास हुआ है। आज मेडिकल कॉलेजों की लम्बी श्रृंखला है, आज आईआईएम और आईआईटीज हैं, आज देश में लगातार एम्स का विकास हो रहा है और यह विकास का क्रम गरीबों के घर तक पहुँचा है। हमने उजाला देखा है, हमने जीवन में इन राहों को बढ़ते हुए देखा है, जो माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से हुआ है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी आई हैं, तो जेटली जी की उसी बात को, जो वर्ष 2016-17 में कही गई थी, मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ।

“कश्ती चलाने वालों ने हार के दी पतवार हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मझधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर यह दिखा देंगे सबको
कि इन हालतों में आता है, दरिया पार करना हमें।”

मैं देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने यह आठवाँ और ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो माइलस्टोन है। हम दुनिया के सामने तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपके सधे हुए कदम, आपका सधा हुआ बजट, आपका सधा हुआ एक अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, आज दुनिया के सामने देश को बदलते हुए देख रहा है।

बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

(इति)

1507 बजे

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : माननीय सभापति महोदया, वर्ष 2025-26 के बजट पर हो रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपनी पार्टी शिव सेना और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे और गट नेता डॉ. श्रीकांत शिंदे से माननीय पंत प्रधान श्री नरेन्द्र मोदी जी को और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, देश के लिए यह बजट लाया है। हमारे नेता श्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उनके लिए सीएम का मतलब कॉमन मैन है और डीसीएम का मतलब डेडिकेटेड टू कॉमन मैन है। यह हमारी महायुति की विचारधारा है कि इस प्रकार से कॉमन मैन के लिए काम करें और उसे लाभ दें। एक तरफ हमारे लिए कॉमन मैन है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में एक कॉन मैन है, यानी धोखाधड़ी करके, झूठ बोलकर, जनता के साथ छल करने वाला यह कॉन मैन है, जो कभी अभय मुद्रा में चले जाते हैं, कभी आलू डालकर सोना देते हैं, कभी अपने भाषण में हलवा को मलाई कहते हैं। हम उनसे और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये विपक्ष वाले महिलाओं का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।

महाराष्ट्र वाली सांसद, वर्षा ताई को भाषण देने का कभी मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि उनका वसीला नहीं है। वर्षा ताई, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप एनडीए में आओ। मैं बाकी लोगों को कहता हूँ कि जिन्होंने हमें रोकने की साज़िश रची, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, जिन्होंने हमें रोकने की साज़िश रची, वही आज हारकर अँधेरे में बैठे हैं। सुनो, महाराष्ट्र के कांग्रेस वालों, महाराष्ट्र की जनता ने फैसला सुना दिया, विरोधियों का मुँह काला कर दिया। आपका मुँह महाराष्ट्र की जनता ने काला किया है, इसलिए आप चुपचाप बैठो।

(1510/PC/VR)

राष्ट्रपति जी का पद इस देश का सर्वोच्च पद है। हमें गर्व है कि आज उस पर द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हैं। अपनी मेहनत और त्याग से वे यहां तक पहुंची हैं, लेकिन कांग्रेस वालों ने आदिवासी वर्ग से आने वाली महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। … (व्यवधान) पहले, सोनिया जी ने अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए और इन्होंने ऐसी ही अपमानजनक बातें हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी के लिए और हमारे नरेन्द्र मोदी जी के लिए भी इन वाक्यों का प्रयोग किया। … (व्यवधान) यह सिर्फ इसलिए, क्योंकि देखा नहीं जाता कि इस देश का नेतृत्व एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला और एक सामान्य परिवार से आना वाला व्यक्ति इस देश का पंत प्रधान बने। … (व्यवधान) इसीलिए, ये इस तरह की बातें करते हैं। … (व्यवधान)

मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष का नेता कुछ जिम्मेदारी से अपनी बात रखे, लेकिन विपक्ष के नेता को पहले पांच मिनट सुनकर मुझे लगा कि शायद अभय मुद्रा में रहने से उनके ज्ञान के दरवाजे खुल गए होंगे, क्योंकि वे प्रधान मंत्री जी की तारीफ कर रहे थे। … (व्यवधान) अडानी और अंबानी जी की भी तारीफ कर रहे थे। … (व्यवधान) वे शायद अपनी मन की बात कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनके मुंह से गलती से सच निकल गया, फिर उन्होंने यू-टर्न लिया और कांग्रेस पार्टी की

मन की बात कहने लगे। … (व्यवधान) इंडी-एलायंस की जो हालत है, उस पर मुझे एक शायरी याद आती है –

"बदले-बदले मेरे सरकार नजर आते हैं,
इंडी-एलायंस की बर्बादी के पूरे आसार नजर आते हैं।"

इस बजट के बारे में यहां के हमारे यूबीटी के नेता बोले कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात लेकर जा रहे हैं। इनकी सरकार की आदत है, जो बिजनेसमैन हैं, उनके घर के नीचे अगर बम लगाएंगे, तो महाराष्ट्र में बिजनेस कैसे आएंगे? … (व्यवधान) इनका गृह मंत्री खंडनी लेने में गिरफ्तार हुआ, ऐसा इनका इतिहास है। … (व्यवधान) हमारी सरकार का वर्ष 2014 से सपना था कि हर नागरिक का अपना घर हो, इसलिए, सरकार ने पंत प्रधान आवास योजना शुरू की थी। … (व्यवधान) मुझे खुशी है कि पंत प्रधान जी द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों के लिए नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5 लाख 36 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है, जिससे न सिर्फ पूरा देश, बल्कि मेरा महाराष्ट्र और मेरी ठाणे लोक सभा के नागरिकों को भी अपने लिए घर मिलेगा, जो उनका अधिकार है।

हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल था? यह हम सबको पता था। महंगा उपचार परिवार को गरीबी में धकेल देता था, लेकिन हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाकर इस समस्या का निवारण किया है। आज 12 करोड़ परिवार और 55 करोड़ नागरिक इस योजना की वजह से अपना इलाज बिना किसी आर्थिक असुविधा के करवा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के छ: करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। अब इस वर्ग को भी हर वर्ष पांच लाख रुपए का हैल्थ कवर मिलेगा। … (व्यवधान) सुन रहे हो या नहीं? सुनो जरा। … (व्यवधान)

बजट की बात करें, तो निर्मला सीतारमण जी ने बजट में देश के हर वर्ग के विकास के लिए प्रावधान किया है। … (व्यवधान) महाराष्ट्र के लिए भी बहुत किया है। … (व्यवधान) अगर मुझे टाइम मिला, तो उसके बारे में भी आपको बता सकता हूं। यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। भारत को 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक मजबूती, कर-सुधार, कृषि विकास, स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा, रोजगार सृजन और टैक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता इस बजट के मुख्य स्तंभ हैं।

(1515/CS/SNT)

इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिससे हर मध्यमवर्गीय परिवार को फायदा मिलेगा, वह है 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर इंकम टैक्स की छूट। मैं देख रहा था कि जैसे ही वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की, उसी वक्त विपक्ष के साथियों का मूड बदल गया, क्योंकि वे स्क्रिप्ट रेडी करके आये थे कि बाहर निकलते ही मीड़िया से बोलेंगे कि यह बजट सिर्फ अमीरों का है, इसमें मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस घोषणा से जनता के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे खपत और बचत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। किसी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार का होता है और उसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल

एक्सपेंडिचर राज्यों को मिलेगा, जिससे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश होगा। यह चीज भी महाराष्ट्र के लिए है। यह बजट गरीबों को सशक्त बनाता है, युवाओं को रोजगार के अवसर देता है। यह बजट किसानों को आर्थिक मजबूती देता है। यह बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। यह बजट भारत को टेक्नोलॉजी और स्टॉर्टअप के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट देश को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और इस सरकार के ऐतिहासिक प्रयास को भी बधाई देता हूँ।

अंत में, एक शायरी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। हमने तो समंदर के रूख बदले हैं, मोदी जी ने सोचने के सलीके बदले हैं, आप कहते थे कि कुछ नहीं होगा, हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले हैं।

धन्यवाद।

(इति)

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

6th Report

1517 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Madam, I rise to present the Sixth Report of the Business Advisory Committee.

केन्द्रीय बजट – सामान्य चर्चा – जारी

माननीय सभापति : श्री अरुण गोविल जी।

1518 बजे

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : जय श्री राम।

आदरणीय सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने की दिशा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को वर्ष 2025-2026 के लिए केन्द्र सरकार का बजट बनाने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

इस कल्पनाशील बजट से जहाँ एक तरफ पूरे देश के मध्यम वर्ग, व्यापारी, किसानों, महिलाओं, वेतनभोगी, श्रमिकों और युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं विरोधी दलों के लिए यह बजट एक भूकम्प की तरह रहा है। इस बार वे विरोध करने की जगह अपने आँसू पोंछते हुए सिर्फ यही कह पाये कि यह बजट दिल्ली के चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। विपक्ष की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे तृणमूल के सांसद आये और एक बहुत ही धमाकेदार स्पीच उन्होंने दी, फुल ऑफ ड्रामाटिक्स। उन्होंने रामायण की बात की कि यह बजट एक सोने के हिरण जैसा है। रामायण से मेरा बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक रहा है, इसलिए कह पा रहा हूँ कि यह बजट सोने का हिरण नहीं है, यह बजट वह तीर है, जो उस सोने के हिरण को मारेगा, जिन्हें हम अपने देश की समस्याएं कह सकते हैं या हम अपने देश की परेशानियाँ कह सकते हैं, यह उसे मारेगा।

(1520/IND/AK)

उन्होंने एक फिल्म 'थ्री इडियट्स' की बात की। मुझे समझ नहीं आया कि वे उस समय क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी स्पीच फुल आफ ड्रामाटिक्स थी। मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि यह जगह ड्रामाटिक्स के लिए नहीं है। यह सीरियस बिजनेस है, क्योंकि हम देश के विकास की बात यहां करते हैं, देश की समस्याओं की बात यहां करते हैं। हमें केवल इसी बात पर ही स्ट्रिक्ट रहने की आवश्यकता है। इस बजट में टैक्स में छूट की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी है। देश की जनता ने और हम में से भी किसी ने यह बात सोची नहीं थी। इस छूट से जनता के हाथ में जो अतिरिक्त पैसा आएगा, वह देश में व्यापार और उद्योग की तरक्की की रफ्तार बढ़ाएगा। हमारे एक साथी ने बताया कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, यह बात सही है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। विपक्ष के जितने भी सदस्यों ने अपनी बात रखी, उन्होंने बिलकुल भी आंकड़ों की बात नहीं की है, जबकि बजट सिर्फ आंकड़ों पर बेस्ड होता है। अब मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करूंगा। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये करना बहुत बड़ा

कदम है। इससे देश में खेती की रफ्तार बढ़ेगी और किसान खेती में ज्यादा धन का निवेश कर सकेंगे। खेती को भारी-भरकम 1.37 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया। देश में अन्न संकट नहीं है, लेकिन दलहन के मामले में हाथ थोड़ा कम है। ऐसे में अरहड़, उड़द और मसूर की खेती पर विशेष ध्यान देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये से छह वर्ष के अंदर दलहन में आत्मनिर्भता मिशन की शुरूआत एक सराहनीय कदम है।

ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी केंद्रीय बजट में 1.88 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए 86 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। डिफेंस में भारत को मजबूत बनाने का सपना देखने वाले प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये करना देश की सुरक्षा के लिए हमें आश्वस्त करता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल और यू-टयूबर भारत के इस रक्षा बजट से खौफ खाए हुए हैं। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारी विकास हुआ। पिछले दस सालों में एमबीबीएस की सीट्स 50 हजार से अधिक बढ़ाई गई तथा प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का अगले पांच वर्ष में 75 हजार मेडिकल सीट्स बढ़ाने का इरादा है। सरकार ने पिछले 10 सालों में आईआईटीज में भी 70 हजार नई सीटें जोड़ी हैं तथा आईआईटीज में 6500 नई सीटें जोड़ने की घोषण भारत को टेक्नीकल फील्ड में बहुत बड़ा जम्प देगी। आदरणीय प्रधान मंत्री जी द्वारा शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति के अनुरूप मेरा अनुरोध है कि मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सेंटर आफ एक्सीलेंस बन सके। छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब से इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। दक्षता निर्माण के लिए 5 नेशनल सेंटर्सअ ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाना भी अत्यंत सराहनीय कदम है। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बहुत अच्छा कदम है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मेरठ से लखनऊ वंदे भारत ट्रेन देने और बनारस तक विस्तार करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरठ से पानीपत रेल लाइन बिछाने के लिए 2200 करोड़ रुपये धन आबंटित करने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरठ से बिजनौर के लिए भी रेलवे लाइन बिछाने की हमारी मांग को भी यदि स्वीकृत कर दें, तो इस क्षेत्र के लिए यह बहुत अच्छा कदम होगा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उड़ान योजना का विस्तार करते हुए अगले पांच वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या 250 करने के लिए कहा है। मेरठ में भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी को फुल एयरपोर्ट में अपग्रेड करने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। मेरठ में हवाई अड्डे की स्थापना से पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यापार की गति तेज होगी। देश की आधी आबादी अर्थात् महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने पूरा-पूरा ध्यान दिया है। पांच लाख महिलाओं और अनुसूचति जाति, जनजाति श्रेणी के उद्यमियों को पांच साल

की अवधि के लिए टर्म लोन मिलेगा। इसके अंतर्गत उद्यमी को दो करोड़ रुपये तक का क्रमिक लोन दिया जाएगा। पहली बार कारोबार की दुनिया में कदम रखने वाली महिलाओं को अगले पांच साल के लिए

सहायता देना बहुत अच्छा कदम है। यह बजट वास्तव में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस बजट में स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेटेजिक इनवेस्टमेंट तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की समावेशी नीतियों पर जोर दिया गया है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करके अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का इरादा है। प्रस्तावित दूसरी परिसम्पत्ति मुद्रीकरण योजना नई परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के मूल्यों को अनलॉक करेगी, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी।
(1525/RV/UB)

स्टार्ट-अप के लिए 'फंड ऑफ फंड्स' का विस्तार, खिलौना क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड के विस्तार और स्टैण्ड-अप इंडिया योजना के तहत सावधि ऋण में बढ़ोतरी से ऑन्त्रप्रेन्योरशिप तथा रोजगार निर्माण को और भी बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदया, मैं, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित, सम्पन्न देश बनाने की दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, उनका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन और बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

जय श्री राम।

(इति)

1525 hours

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, Budget is a collective imagination of the nation. It is not just a compilation of facts and figures and a set of numbers. It is a shared dream that the country views together. It is one vision that the country should capitalise and share the future of the communities. It is a collective aspiration of the nation. It shall be a vision statement enriched by the input and ideas of the hon. Members. We, as a nation, shall imagine our future paths, give care and attention to all segments of the society, and chart our own path to progress. It shall not be a political rhetoric or an election game. We, as a nation, shall put our soul into emerging as a stronger nation and address the popular concerns. Political favouritism and biases shall not defeat the dreams of the great nation. But the Budget of 2025-26 fails to address the pressing challenges our country is facing today, such as, unemployment, inflation, depreciation of rupee against major currencies, farm sector crisis, MSME struggles, climate change, and the emerging geopolitical tensions caused by the new US administration.

In what appears to be an unprecedented move, the Ruling Party has openly framed the Budget to benefit only a small segment of society. This is nothing short of bribery, using public funds to secure votes in upcoming elections. We can conclude that this Budget is not for Bihar and Delhi.

Sir, the Government claims that the agriculture sector is the growth engine of our economy but the Budget fails to offer a meaningful support to improve the agriculture produce which would help the farmers earn more. While research and development are vital for progress in agriculture, the Government only marginally increased funding of it by Rs. 21 crore.

India's overall spending in research and development remains insufficient. We are spending only 0.6 per cent of the GDP. India's research and development expenditure is the lowest among the world's five economies. By contrast, China allocates 2.41 per cent of the GDP and the European Union allocates 5-6 per cent of the GDP. China now leads in patent applications and has achieved the second highest labour productivity

growth. China also boasts of its largest number of Ph.D. awards annually and innovation in AI. A report from the Ministry of Human Resources Development reveals that only 15.8 per cent of papers by Indian researchers appear in the world's top 10 journals, whereas the figure stands at 27 per cent for China, 33 per cent for Germany, and 36.2 per cent for the United States. We are entering the era of AI, so we have to give more importance to research and development.

1526 hours (Kumari Selja *in the Chair*)

The existing commodity boards, crucial in the agriculture sector, especially for Kerala, are left underfunded. For instance, the allocation for the Coffee Board remains unchanged between 2024-25, and the Rubber Board gets Rs. 40 crore increase, and the Spices Board sees only Rs. 24 crore more.

(1530/GM/GG)

In an alarming move, the allocation for the Coconut Development Board has actually been reduced from Rs.39 crore to Rs.35 crore. The Budget also falls short of addressing our weakening currency which is poised to wreak havoc on the economy. The Finance Minister offers no concrete measures to counter this. Agriculture has been projected as the growth engine. But in terms of total allocation for agriculture, there has been a marginal reduction in the current Budget as compared to the Revised Estimate of the previous year. What is totally unacceptable and not understandable is the neglected plantation agriculture. Plantation is no more the business of large business owners. Today, it is dominated by small holders. There is predominance of human labour and more importantly, about 72 per cent of the plantation workers are from the backward community. What is more, plantation is done in the least developed locations in our country.

Sir, as compared to the Revised Estimate of 2024-25, the total Budget size of the year 2025-26 got a little over 10 per cent increase in real terms. After considering inflation, the increase will be less than five per cent according to my knowledge. The *Economic Survey* rightly noted that

corporate profitability reached a 15-year peak in 2023-24 whereas employment growth has been sluggish. No wonder our educated young generation remains unemployed and is migrating from this country. The Budget, therefore, is disappointing for the younger generation. The big-ticket concession is by way of tax concession for the middle class. By exempting income of upto Rs.12 lakh from Income-tax, it is estimated that the Finance Minister has foregone Rs.1,00,000 crore. If the Finance Minister had decided to put at least Rs.25,000 crore in the hands of the lowest income group by way of increase in the welfare pension or by way of increase in the wages of MGNREGA workers, there would have been a much higher boost in domestic demand. But sorry Sir, the allocation to the MGNREGA scheme is the same as in the last Budget.

The emphasis on manufacturing is also welcome but we must not forget the fact that after the introduction of the Make in India programme, they say that the share of manufacturing output in India's GDP has not been increasing. As usual, Kerala continues to be neglected in the Union Budget. Despite facing one of the worst recent disasters, Wayanad has not been granted a special package.

As a new AIIMS has been announced for Kerala, the tourism sector in the God's Own Country has been ignored. Even though Kerala has achieved 100 per cent literacy, the education sector continues to be neglected. In the railway sector, Kerala still does not receive adequate consideration. The State's dream project, the Angamaly-Sabari rail line has not been included in the Budget. After completing the ongoing projects, for which funds have been allocated, Kerala will receive only Rs.330 crore in the Railway Budget. Sir, the Vizhinjam Port Project has been in a sorry situation.

Sir, I have a request before the hon. Finance Minister. One of the biggest reliefs could be for the MPs in MPLADS fund. Our allocation of Rs.5 crore was fixed years ago. In many States, the funds allocated to MLAs are bigger than this. Considering the increased developmental needs or timely

expansion of the project, I request the hon. Union Minister to increase the MPLADS fund to at least Rs.20 crore.

The Central Government has constituted a new Pay Commission. I welcome that, Sir. In this context, I also urge the hon. Union Minister to consider increasing the allowances of the Members of Parliament.

The present Government claims that it is building a new India. But facts and figures since 1947 show that it is nothing but a balanced line. The present India has been built by the previous Government led by Congress. Take the growth of the Budget size in the first year of free India.

(1535/SRG/CP)

The size of the first Union Budget was a mere Rs. 171.15 crore. In 2013-14, when the Congress Government presented its last full Budget, the size had jumped to Rs. 16.65 lakh crore, an incredible growth of 9,73,757 percent or a 9737-fold increase from the first Budget. If the interim Budget presented by the Congress Government is taken into account, the Budget size scales another new peak. It presented an interim budget of Rs. 17.63 lakh crore. Compared with the first budget, this represented a growth of 1,01,303 percent or more than a 1,00,000-fold increase. Barring a few years, the period was largely dominated by Congress Governments. On the other hand, the size of the first NDA Government's budget in 2014-15 was Rs. 17.94 lakh crore, and the current NDA Government's Budget is near about Rs. 50 lakh crore. This shows a 168 percent growth in the budget size or just a 1.6-fold growth during the NDA period. This comparison indicates that while India grew 9,737 times from 1947 to 2014 under the Congress rule, it has only achieved a 1.6-fold growth under the NDA government.

The growth of the country's banking sector is equally remarkable. At the time of Independence, total deposits in banks were Rs. 1,261 crore, while loans amounted to Rs. 475 crore; and by 2013-14, total deposits had risen to Rs. 79.55 lakh crore, with outstanding credit to Rs. 62.82 lakh crore, and the CD ratio stood at 79 per cent. This incredible growth was achieved through the nationalization of banks, introduction of the Lead Bank Scheme,

the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, NABARD and other things.

Somebody criticized Indira Gandhi's Scheme. The former speaker, Shri Sunil Gupta from Maharashtra criticized Indira Gandhi's tenure. What happened? Shrimati Indira Gandhi Ji translated her promise of `Garibi Hatao' into action, the country saw a 500 percent increase in food production, and India became a food-surplus nation. India produced just 50.82 million tonnes of grain in 1950, and now that figure has risen to a record 314 million tonnes.

Before nationalization, private banks in India were inaccessible to the common people while offering a red-carpet welcome to industrialists. In 1967, only 2.2 per cent of the total loans were allocated to the agricultural sector. In rural areas, there were only 1,247 bank branches. Indian farmers struggled without access to loans for agricultural investment. After the nationalization of banks, this situation changed significantly. In 1969, there were only 1,247 rural bank branches across the country. By 1984, this number had increased to 25,541 branches. In the 1970-71 period, agricultural loans amounted to Rs. 744 crore. By 1990-91, this had increased to Rs. 10,000 crore, reflecting a 7.5-fold growth. Despite facing major crises like the Bangladesh War, the influx of refugees, two famines, and the oil crisis, India's food production increased by 35 per cent. … (*Interruptions*)

Madam, I am just concluding with one sentence. If India shines today, it is not because of the NDA Government. If India shines today, it is due to the firm foundation laid by our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru Ji. The present Government is merely enjoying a piggyback ride on that foundation while claiming to be creating a "new India." In the future, they will become the laughingstock of history.

With these words, I conclude.

(ends)

1539 बजे

श्री राजीव राय (घोसी) : मैडम, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बजट भाषण की शुरुआत इस आक्रोश और नाराजगी के साथ करना चाहूंगा कि एक बार फिर आपने उत्तर प्रदेश को ठगने का काम किया है।

(1540/NK/RCP)

खासतौर से आप पूर्वांचल लगातार की अनदेखी करने का काम कर रहे हैं। मैं अपने लोक सभा के बारे में क्या कहूं, हमारे बड़े भाई और कपड़ा मंत्री जी यहां बैठे हैं। हमारे यहां एक कताई मिल है, केन्द्र सरकार की जमीन है, जिसे कल्पनाथ राय जी ने शुरू किया था। आज से सात-आठ साल पहले कपड़ा मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे थे कि उस कताई मिल को शुरू करेंगे। इस सरकार ने पिछले दस सालों में घोसी के लिए कुछ नहीं किया, एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया है। अगर आप इसी तरह से अन्याय करते रहेंगे, आजादी के बाद गलती से एक बार 2014 में चुनाव जीत लिया था। मैंने रेल मंत्री जी को ट्रेन चलाने के लिए एक लिस्ट दी थी, दोहरी घाट से नहीं चल सकती, मुंबई के लिए नहीं चल सकती, दिल्ली के लिए नहीं चल सकती, कोलकाता के लिए नहीं चल सकती, आप यहां कुर्सी पर बैठे हैं तो किसी पंडित ने बताया था कि नहीं चल सकती। उसका जवाब यह है कि चुनाव आने वाला है, चुनाव में आपको वोट नहीं मिलेगा, घोसी लोक सभा की तरफ से प्रधानी में वोट नहीं मिलेगा, ब्लॉक प्रमुख में वोट नहीं मिलेगा, जिला पंचायत में वोट नहीं मिलेगा, विधायकी में वोट नहीं मिलेगा, लोक सभा में वोट नहीं मिलेगा।

मैं आपसे खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं, कपड़ा उद्योग आपका है। बुनकरों में केवल माइनोरिटीज के लोग नहीं आते हैं। जब कपड़ा बिकता है, ट्रांसपोर्ट वाले भी होते हैं, धागे वाले भी होते हैं, अर्थव्यवस्था सुधरती है तो सारे धर्मों के लोग होते हैं। मैं वित्त मंत्री जी अनुरोध करता हूं कि पीछे बैठे मंत्री जी के लिए भी कुछ और पैसा दे दीजिए कि मेरे लोक सभा का भी उद्धार हो जाए। वसीम बरेलवी जी का एक शेयर है:

"वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीक़े से, मैं ऐतबार न करता तो और क्या करता"

बड़े जोर से 12 लाख रुपये पर इनकम टैक्स छूट का दावा किया गया। मीडिया को अब लोग ... (*Expunged as ordered by the Chair*) मीडिया भी कहते हैं, जोर-शोर से कहा गया कि 45 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया। 35 परसेंट लोग मिडल क्लास में आते हैं। मिडल क्लास की परिभाषा नहीं पता है, … (व्यवधान) किसानों का कर्ज माफ कर दीजिए, मैं आपका स्वागत करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। कर्ज क्यों बढ़ा रहे हैं?

इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट की सच्चाई यह है कि केवल 7.4 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जिसमें से 5.2 करोड़ लोग निल इनकम टैक्स भरते हैं, जो 70 प्रतिशत के बराबर है, 2 करोड़ लोग ओल्ड आयकर व्यवस्था के अंतर्गत हैं, अब डेढ़ करोड़ लोग बच गए, डेढ़ करोड़ में से मुश्किल से कुछ ही इनकम टैक्स पेइंग होंगे, जो 7 लाख से 12 लाख रुपये के ब्रेकैट में आते होंगे।

सात लाख रुपये पाने वाले से तो पहले ही आप कुछ नहीं लेते थे। सच सुन लीजिए, मुश्किल से 20-30 लाख लोगों को इनकम टैक्स में राहत दे रहे हैं, बारह लाख रुपये से बारह लाख दस हजार हो जाए तो आप 65, 500 रुपये वसूल लेंगे, बीस से तीस लाख लोगों को राहत दे रहे हैं।

मैं दो बातें कहूंगा, आपने बीस से तीस लाख लोगों को बारह लाख रुपये में राहत दीं, हाउसिंग लोन पर रिबेट मिलता था, बच्चों की फीस पर मिलता था, हेल्थ इन्श्योरेंस पर मिलता था, आपने सब छीन लिया, सबको आपने वापस कर दिया।

सरकार की हमेशा से नीति रही है कि देश को जुमलों और अच्छी-अच्छी बातों में बहका दो। चंद महीने बाद आठवां पे कमीशन शुरू होगा। आप सात से बारह लाख रूपये पर छूट देने की बात कह रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप जवाब देने के लिए खड़ी हों तो घोषणा करें कि आठवां पे कमीशन लागू होने पर छूट को प्रपॉशनेटली बढ़ा दिया जाएगा। अभी आप छूट देने की बात कह रही हैं। सभी लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। … (व्यवधान) मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं देश के किसानों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। पूरे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ को रिकार्ड किया गया। यह 3.3 प्रतिशत था जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 2.5 प्रतिशत है। यह कहानी तस्वीर खासतौर से उत्तर प्रदेश का बयां कर रही है।

(1545/KDS/PS)

जो अच्छी-अच्छी बातें ये लोग करते हैं। यूपी में 69 हजार किसान कर्ज में डूबे हैं। देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। आमदनी दोगुना करने वाले लोग देखें कि today, 18.7 crore farmers are under agricultural loan obligations. इन्होंने दोगुना दाम देने का वायदा किया था। ये किसान भी हैं। 16 लाख करोड़ रुपये आपने अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप पीठ ठोंककर कहते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी।

मैडम, हम पूर्वांचल से आते हैं। हमारे पूर्वांचल के किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों की तरह नहीं हैं। हमारे किसान एक बीघा, डेढ़-दो बीघा वाले होते हैं। उनको आप कर्ज के जाल में फंसाना चाहते हैं ताकि वे आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएं। हमारे यहां कोई उद्योग-धंधा नहीं है। हमारे यहां छोटे-छोटे किसान हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं … (व्यवधान) उनको छूट है, बोलने दीजिए। पिछले 5 सालों में इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। मैं किसानों के कर्जमाफी की बात कर रहा हूं। आप किसानों का कर्ज माफ करें।

मैडम, मैं शिक्षा पर आता हूं। समय के हिसाब से थोड़ा कट-शॉर्ट कर रहा हूं। ये वाट्स अप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं। मैं शिक्षा कमेटी में मेंबर हूं। प्राइमरी स्कूलों में 10 लाख टीचरों की वैकेंसीज़ खाली हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि टीचरों को अपॉइंट कर दें। प्राइमरी स्कूलों में जहां आप टीचर अपॉइंट नहीं कर सकते, तो फिर देश की शिक्षा-व्यवस्था बनाने की बात आप कैसे कर सकते हैं? उन स्कूलों की हालत क्या है? मैं 30 से 35 प्रतिशत केंद्रीय विद्यालयों की बात कर रहा हूं। संविदा पर वे नौकरी कर रहे हैं। वे खुद ही सुरक्षित नहीं हैं। उनको खुद नहीं पता कि वे कांटीन्यू करेंगे या नहीं? यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 9वीं क्लास में गणित का एक टीचर जाता है, जो रेग्युलर है

और एक लाख, सवा लाख सैलरी पाता है, जबकि संविदा वाले टीचर को आप 40 हजार सैलरी देते हैं। यदि आप टीचरों, जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, उनके साथ भेदभाव करेंगे, तो फिर देश को आगे बढ़ाने की आप क्या बात कर रहे हैं? प्रधान मंत्री जी आते हैं और एमबीबीएस की सीटें 1 लाख बढ़ा दीं। 10 हजार सीटों का प्रस्ताव पारित कर दिया कि 10 हजार सीटें बढ़ाएंगे। … (व्यवधान)

मैडम, अभी तो केवल 5 मिनट हुए, 8 मिनट का टाइम दिया गया था। आप डेटा मांग लीजिए। हर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पीजी फैकल्टी की जरूरत होती है। देश में पीजी फैकल्टी नहीं है, लेकिन एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दीं, तो क्या उन विद्यार्थियों को अधकचरे टीचरों से आप पढ़वाएंगे? आप जान से खेलेंगे? आप हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ में प्रधान मंत्री जी हवाई अड्डे का उद्घाटन करके आए थे। उस समय चुनाव था। आप पता कर लीजिए कि कितने हवाई अड्डे चल रहे हैं? हवाई जहाजों की हालत यह है कि यहां से लंदन जाओ तो 30 हजार रुपये, लेकिन प्रयागराज जाओ तो 50 हजार रुपये। यह आपकी सरकार है। बजट भाषण में आप जो बातें करते हैं और जनता पर अहसान करने का काम करते हैं, उसके लिए मैं दो लाइनें फिर दोहराना चाहता हूं और उन्हें बार-बार दोहराऊंगा।

आप अवाम पर कुछ ऐसे अहसान करते हैं।
आंखें तो छीन लेते हैं और चश्मे दान करते हैं॥

मैडम, अंत में मैं एक अनुरोध करते हुए आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ है। भुखमरी की कगार पर है। हमारे यहां उद्योग नहीं हैं। हमारे यहां छोटे किसान हैं। हमारे यहां बाढ़ और सुखाड़ का क्षेत्र है। आप दिल पर हाथ रखकर सोचें कि यदि पूर्वांचल के लिए कुछ न दिया हो, तो पूर्वांचल पर उपकार कर दीजिएगा और मेरे घोसी लोकसभा में बंद पड़ी मिलों को चलवा दीजिए। उनसे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बोलना तो बहुत कुछ था। अंत में, मैं यही कहूंगा कि यह बजट किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, चिकित्सा विरोधी है और इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। धन्यवाद।

(इति)

(1550/MK/SMN)

1550 बजे

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : धन्यवाद सभापति महोदया। आज मैं आपको और अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। यह बजट, जिसको माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, यह विकसित भारत के मॉडल का बजट है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, घरेलू मनोभाव को उल्लास से भरना और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च क्षमता को और सहूलियत देना है। बजट में ऐसे लक्ष्यों को लेकर काम किया गया है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। मैं बधाई इसलिए भी देता हूं कि इस बजट में मध्यम वर्ग को बहुत राहत दी गई। चूंकि मैं एक किसान वर्ग से आता है, आज पूरे किसान वर्ग में हर्ष और उल्लास का वातावण है। कृषि हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसी कारण धन-धान्य कृषि योजना में 100 ऐसे जिलों को शामिल किया है, जो खेती में कमजोर हैं। इसमें एक करोड़ सात लाख किसानों को कवर करने का काम किया गया है। मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। किसानी और खेती करने वाले मजदूरों का पलायन न हो, उसके लिए खेती को और बढ़ावा देने का काम किया गया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं।

बिहार में मखाना बोर्ड गठित करके ऐसे किसानों को, जो वर्षों से वंचित थे, उनको लाभ देने का काम किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, इसको 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले गाँव का एक साहूकार पूरे गाँव को दबाकर रखता था। पहले बहुत बदतर हालत थी। पहले एक कहावत कही जाती थी – 'उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी,भीख निदान' । लेकिन अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब खेती में सम्मान निधि से किसानों का सम्मान लौटा है। हमारे विगत प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट योजना लेकर आए थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ था । इसको 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करके न केवल किसानों को राहत देने का काम किया गया बल्कि उनके जो अन्य रास्ते हैं, चाहे वे उद्योग के लिए हों या किसी और चीज के लिए, उनको भी खोलने का काम किया है। दलहनों के लिए 'आत्मनिर्भर मिशन' की घोषणा की गई है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे विश्व ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व को 'श्री अन्न योजना' सहित कई योजनाओं के लिए सराहा है और पालन करने का प्रयास किया है, चाहे वह योग दिवस हो या अन्न योजना हो। दलहन और श्री अन्न के मामले में, चूंकि आज हर घर में रोग पैदा हो रहे हैं और हमारी जो पुश्तैनी खेती थी, पुरातन खेती थी उसको दूर करने का काम कांग्रेस के राज में हुआ था। इन्होंने उद्योग को ही सर्वोपरि रखा था। उसमें भी ये तथाकथति व्यक्तियों के लिए रखते थे। 'आत्मनिर्भर भारत', जो गांव के रास्ते से होकर निकलता है, जो गरीब के रास्ते से होकर निकलता है, उसको माननीय मोदी जी ने लागू किया है।

दालों में, चाहे वह अरहर हो, उड़द हो या मसूर हो, उसमें आत्मनिर्भरता के लिए बजट में माननीय वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं।

आज नए सेक्टर, एमएसएमई में, जो सर्वांगिण विकास सुनिश्चित करता है, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने क्रेडिट गारंटी कवर दिया है। उसको सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। इससे डेढ़ लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध हो सकेगा। मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वह जूते का हो या चमड़े का हो, एक जमाने में चमड़े के उद्योग को हीन दृष्टि से देखा जाता था, अब उसको भी 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार, जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपये तक निर्यात होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

खिलौना विनिर्माण, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता और भारत की जितनी भी सनातनता है, उसको देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें खिलौने का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माननीय मोदी जी ने भारत में खिलौने के लिए टिकाऊ और वैश्विक केंद्र बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जो सूक्ष्म उद्योग के उद्यमों के लिए है, उसको 5 लाख रुपये की सीमा से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का काम किया गया है।

(1555/SJN/SM)

माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले ही वर्ष 10 लाख कार्ड्स जारी करने का काम किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, जिसमें निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर क्रमशः ढाई और दो गुना करने का काम किया गया है, जिससे आम और गरीब व्यक्ति के जीवन में अमूल-चूल परिवर्तन होगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बेहतर कल के लिए 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' को शुरू किया है। अगर कोई आठ करोड़ बच्चों, एक करोड़ माताओं और 20 लाख किशोरियों के लिए पोषण सहायता देने का काम करेगा, तो वह हमारी सरकार करेगी, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं धन्यवाद देता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं में वर्ष 2025-26 में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीट्स और 200 कैंसर केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। कैंसर जैसी गंभारियों का इलाज कराने में काफी दिक्कतें आती हैं। मैंने तो अपनी मां को कैंसर की वजह से खोया है। मैंने उसका बहुत अध्ययन किया है। मैं जानता हूं कि हर घर में सस्ते इलाज की जरूरत है। मैं इसलिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जिस रसायन और खाद्यान्न के कारण कैंसर जैसी बीमारी बढ़ रही है, इस बजट में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस प्रकार की स्वस्थ खेती और स्वस्थ मानव की कल्पना की गई है। इसलिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है। मैं सभी गरीब लोगों की ओर से वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। विपक्ष कहने के लिए कुछ भी कहता रहे-

मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं,
जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि 'पीएम जन आरोग्य योजना' के तहत लगभग एक करोड़ वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सेवा कल्याण सुनिश्चित करेगी, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बैंकों का

बढ़ा हुआ ऋण, 30,000 रुपये की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के माध्यम से उनके कल्याण को आगे बढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की शुरुआत, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र तथा 6,500 अतिरिक्त छात्रों को समायोजित करने के लिए आईआईटी का विस्तार किया जा रहा है। अभी-अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सात संभागीय समिति हुई हैं, जिसमें एक-एक जिले में 30 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। यह मोदी के मार्गदर्शन में विकसित भारत का रास्ता खुला है।

तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से किसी का बिगड़ा मुकद्दर नहीं सुधरता,
दुनिया में जीतने का हौसला रखो,
क्योंकि एक हार में कोई फकीर और एक जीत में कोई सिकंदर नहीं बनता।

माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निजी भागीदारी और पीपीपी मॉडल बनाने का काम किया गया है। उसमें बुनियादी ढांचों को तीन वर्षीय परियोजनाओं को पाइपलाइन में आगे बढ़ाने का काम किया गया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। राज्यों में 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि नई परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ों का जो सपना देखा था, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में उसकी शुरुआत हो गई है। चाहे वह केन-बेतवा नदी परियोजना हो या चाहे पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना हो। हजारों-करोड़ रुपये की योजनाएं हैं। पहले हमारा किसान एक समय में एक फसल पैदा नहीं कर पाता था। यह मोदी जी का वर्ष 2025 का भारत है। मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 18वीं और 19वीं सदी ब्रिटेन और इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की है, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। यह मोदी जी का भारत है, जो पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। अर्थव्यवस्था में अनेकों नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।…(व्यवधान)

(इति)

(1600/SPS/RP)

1600 बजे

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी (बीरभूम) : मैडम, थैंक्यू। लास्ट 16 साल से हाउस में बैठकर जितनी बार बजट सुनती हूं, तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा बजट है। ओहो, इसमें कितना कुछ मिल गया है। जब मैं घर जाकर पढ़ती हूं तो लगता है कि एक्चुअली क्या मिला है और क्या मिलना चाहिए। जैसा मैडम ने बोला है कि पॉवर्टी जीरो परसेंट तक, तो मुझे लगता है कि मिनिस्टर ने गांव में कभी जाकर … (व्यवधान)

माननीय सभापति (कुमारी सैलजा) : मंत्री जी, आपने क्या बोला है?

श्री गिरिराज सिंह : मैंने आग्रह किया है कि यदि कोई सदस्य इस समय बोल रहे हैं, तो वह सवाल-जवाब तो नहीं है। यह उचित नहीं लगता है। मैंने यह प्रार्थना आपसे की है। … (व्यवधान)

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : मैडम, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : शताब्दी जी।

… (व्यवधान)

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : मैडम, मुझे केवल एक मिनट दे दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : सॉरी। अब दोबारा नहीं, क्योंकि उनका भाषण शुरू हो चुका है।

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी (बीरभूम) : मैडम, थैंक्यू। मैं फिर से बोल रही हूं कि लास्ट 16 साल से जब बजट हाउस में सुनती हूं तो लगता है कि बहुत कुछ मिला है, लेकिन जब घर जाकर पढ़ती हूं तो लगता है कि कितना मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या मिला है। मैडम ने पॉवर्टी की बात की है। मुझे लगता है कि मैडम को गांवों में जाना चाहिए, तब पता चलेगा कि पॉवर्टी किसे बोलते हैं। उनकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की वजह से शायद सिग्नल में कभी उनकी गाड़ी खड़ी नहीं हुई है। वहां पता चलता है कि बच्चे गाड़ी को आकर धोने लगते हैं, कैसे धूप बेचते हैं, कैसे जिम्नास्टिक दिखाते हैं। अगर वह वहां रहेंगी तो पता चलेगा कि देश में पॉवर्टी का क्या हाल है। What we all need to accept is that childhood malnutrition in India is a direct result of both poverty and systematic inequalities. The record indicates that India has the highest child wasting rate in the world, which is 18.7 per cent, and 35.5 per cent of children under five are medically listed as having their growth stunted.

The Budget of Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 saw hardly an increase of 3.58 per cent. Despite allocation to a few concerns during the Finance Minister's address, the Budget remains silent on Anganwadi workers and Mid-day Meal scheme.

The Budget for the National Health Mission, which contributes towards strengthening the public health system, especially, at the primary care level, has been allocated with a mere rise of 3.4 per cent in real terms. Therefore, there is a decline in its allocation.

अभी इस बजट को फिल्मी लैंग्वेज में बोलें तो 12 लाख रुपये से हिट है। मुझे जानना है कि कितने लोगों की महीने में एक लाख रुपये की इनकम है और उसकी परसेंटेज क्या है? मैं रिक्वेस्ट करूं कि मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी बीरभूम में 12 हजार ऐसी नौकरी दे दें तो मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी में उन लोगों को इनकम टैक्स फ्री नहीं चाहिए। वे दो लाख तक इनकम टैक्स भर देंगे, लेकिन उनको नौकरी चाहिए।

In 1990, six per cent employment was there in the organised sector. In 2025, the same rate of six per cent of employment is there in the organised sector. That means, there is no employment growth in the organised sector. The MSME houses approximately 62 per cent of employment to the women. The micro units have the employment strength of 10.20 crore. The Government has increased the loan gratuity scheme. The Government needs to note that the micro and small units cannot further carry the burden of complicated GST and other imposed obligations.

According to a Report of NITI Aayog, as of 2021, there were approximately 7.7 million gig workers in India. The gig workforce is expected to expand to 23.5 million workers by 2029-30. Why is the Government not introducing a dedicated law for these gig workers and give them the legal status? Does this Budget try to address internal problem of the economy? Perhaps, it is not. What we have seen on a regular basis is, there is an allocation but there is no actual spending.

As far as Swachh Bharat Mission is concerned, Rs. 2392 crore was spent in 2021-22. The allocation under this Misson in 2022-23, under the urban component, was Rs. 5000 crore whereas the spending was only Rs. 2,159 crore. Now, the allocation under the urban component has received Rs. 5,000 crore.

(1605/NKL/MM)

In respect of Jal Jeevan Mission, the allocation was Rs. 70,000 crore in 2023-24 but only Rs. 23,000 crore were spent. This time, Rs. 67,000 crore has been allocated for this.

मैडम ने मखाना के बारे में बोला था। मैंने सोचा कि कोई अलग से स्कीम होगा, लेकिन बाद में पता चला कि खाने वाला मखाना होता है। मुझे लगता है कि मखाना लकी है, उसका अचीवमेंट है कि वह पार्लियामेंट में बजट तक पहुंच गया। यह गवर्नमेंट का कोई अचीवमेंट नहीं है। इसमें बढ़ा-चढ़ाकर बोलने की कोई बात नहीं है कि मखाना के लिए हमने इतना किया। इंडिया में ऑलरेडी काफी काम है। मैं एक बात और बताना चाहती हूं कि इस सरकार और पार्टी का हमेशा इलेक्शन का बजट होता है, ऐसा क्यों? डेवलपमेंट नीडिड के लिए होता है। देश में कहां डेवलपमेंट की जरूरत है। बी फोर बीजेपी, बी फोर बिहार और बी फोर बंगाल। बंगाल ने इनको वोट नहीं दिया, इसलिए क्या यह इलेक्शन पर डेवलपमेंट डिपेंड करेगा? लेकिन बिहार में इलेक्शन है, शायद वह लोग बहुत वोट देंगे, यह सोचकर उसका एलोकेशन हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि हम हमेशा इस पर ध्यान दें कि डेवलपमेंट किसलिए चाहिए, कितना चाहिए और कहां तक चाहिए। मुझे पता है कि टाइम कम है और मुझे बहुत कुछ बोलना था। मेरी एक रिक्वैस्ट और सजेशन है कि अगर जितने माइक्रोफोन्स हैं, उनके साथ एक लाइडिटेक्टर लगा दें तो पता चलेगा कि कौन कितना झूठ बोल रहा है और कहां तक झूठ बोल रहा है और कितना झूठ हाउस में बोलते हैं? इसमें यह भी पता चलेगा कि मिनिस्टर के पीछे बैठकर थपथपाकर साउंड देते हैं, वह साउंड ज्यादा है या लाइडिटेक्टर का साउंड ज्यादा है। देश को यह भी जानना चाहिए कि झूठ कहां है, सच कहां है और मुझे लगता है कि यह सिस्टम बनने से सच ज्यादा बोला जाएगा और झूठ कम होता जाएगा।

(इति)

माननीय सभापति (कुमारी सैलजा) : आपने समय में अपना भाषण खत्म किया, थैंक यू।

1607 hours

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAGAON): Thank you, Madam, for giving me this opportunity.

Exactly about a fortnight before the hon. Finance Minister presented the Budget, the C-Voter carried out a survey asking respondents about what would be the anticipation of the Budget and beyond the Budget. You would be surprised to know that when the figures were given to the public, about 37 per cent of the people responded by saying that irrespective of the goodies that probably would be forthcoming in the Budget, the life of common people would only be getting harder for another one year and after that.

Madam, you would be surprised to know that two-thirds of the respondents say that the prices have only been skyrocketing since 2014. About 50 per cent of the respondents have said that inflation has directly hit their lives and it is becoming worse. This is the highest level of pessimism probably registered over a decade. These are not the cold statistics. These are the real fears. These are the real apprehensions, real struggles and real agonies. So, I hope that the Finance Minister and the Government would try to understand the fear of common people.

Madam, in 1991, when the former Finance Minister, Late Prime Minister Dr. Manmohan Singh, presented his Budget, he quoted Victor Hugo. He said:

“No force on Earth can stop a good idea whose time has come.”

Indeed, he presented an epoch-making Budget which really did a course correction and set a new paradigm of development for the country. And today, after more than two decades, we are still basking on the path that was set out by Dr. Manmohan Singh in 1991. But for more than two decades, our Finance Minister has been presenting the Budget. Frankly speaking, I do not see any new idea that has been translated or which has added a new dimension to the people of India for enhancing their quality of lives.

(1610/VR/YSH)

Madam, yes, there is much hullabaloo of this income tax rebate up to Rs.12 lakh. I would like to point out that by raising the bar of relaxation of the income tax up to Rs.12 lakh, you are going to benefit only two per cent of the total population. But what about the rest 98 per cent of our population who have been left in the lurch?

Today, I would like to cite examples of four persons, the common people, whom I met recently, and I hope that the hon. Finance Minister would take note of the aspirations of these people, whose cases I am going to cite.

When our leader, Rahul Gandhiji spoke during the Motion of Thanks on the President's Address, he did stand up here and instead of criticising the Government, he gave a new narrative. He set a new narrative before the people of India through this Parliament. Similarly, we are not here just to criticise the Budget. I would like to give a new alternative, a new paradigm and, if necessary, the hon. Finance Minister can take note of this. I would like to provide alternative proposals against these four examples that I want to give.

Just a fortnight before this Budget was placed in the House, I met Saponti Hazarika, a daily wage earner in my constituency. He told me that despite getting five-kilogram rice under the Garib Kalyan Yojana, his family is going through a dire state in spite of cutting all the expenses. In Assamese he said: *"sokolu faltu khoros bondho kori disu".* It means that he cut all the frills of his life.

On the one hand, the monthly expenses of his family have doubled, but on the other hand, the wages that he earns are remaining stagnant. That is why he asked me, how much longer we can survive like this. This is an area where I would say that the Government has failed. The prices of all commodities are rising and there is no meaningful relief from your side. There is no major intervention by the Government to curb inflation beyond some vague fiscal targets. The income disparity is widening due to corporate tax breaks, but there is no direct support for the struggling families.

Madam, here is the alternative proposal from us – a) expand and strengthen food security, increase allocation of PDS, and universalise free ration distribution for next two years; b) increase MGNREGA wages and expand minimum work days, raise daily wages to match inflation and ensure 150 guaranteed work days instead of 100 days; c) provide direct income support, expand cash transfers for low income families, model the global best practices in terms of inflation relief, and reduce GST on essentials like food, medicines, medical insurance and household staples.

Then, I would like to give another example. About a month ago, in a railway compartment, I met one young graduate, Dipankar Mahapatra from Odisha. He is just 25 years old. During conversation he told me that he has been applying for jobs for the last three years. He told me that a degree means nothing because there are no jobs. Talking to him, I was wondering, how I would instil hope in his mind because he is in a hopeless situation.
(1615/SNT/RAJ)

Madam, where did the Government fail? The hon. Finance Minister has been presenting the annual Budget. This is the 8th time. But where has this Government failed? Unemployment is at a decade high level despite of a perceptibly high GDP growth. Skilling programmes, with changing times, have failed to translate into job placements. Both the MSME and the unorganized sector, India's largest job creators, are struggling due to poor credit access and centralising of economic activities.

Madam, here is the prescription from our side. There should be expansion of economic activities. Put more money in the pockets of the lowest income groups so that demand for consumption increases. One does not have to be an economist to know this. It is common sense that if you put more money in the pockets of the common people, who live in the lower strata of economic pyramid, actually our economy expands and the canvas of economic activities also proliferates. That is how demand for consumption and demand for jobs are created. But this Government is doing nothing. For public sector hiring, push should be given. Fill up two million plus existing Government jobs, vacancies within the next year. Demand-driven skilling

programmes and MSME revival fund are utmost necessary. At the same time, like MGNREGS, Urban Employment Guarantee Scheme should be initiated. The National Employment Guarantee Programme for cities, modelled on MGNREGS, should also be initiated in this country.

Madam, I want to give a third example. This is regarding Nidhiram Bordoloi, another farmer from my constituency. He has been a farmer, but due to vagaries of nature and untimely floods, all his crops are destroyed. He does not have a future. What he told me is: “Our land and waters have become unreliable. Yet this Budget does nothing to protect us.” Your failure is that there is no dedicated climate resilience fund, despite extreme weather losses; lack of disaster insurance for small farmers and unorganized workers; and weak urban climate planning leading to flooding and heat waves.

Madam, these are the few examples that I wanted to give, and these actually reflect the aspirations of the people. I want to say just a few words before I conclude. It is not a stupid idea that an elected representative like me stand up and say something. What I would like to say is that life continues, but we have to try to make life more meaningful. That is why I am saying that in your Budget, you may have tried to solve a popularity problem of your Government, but it has not solved the problems of our people. It has not given new ideas, new dimensions, or it has not addressed the feeling of hopelessness that is all-pervading in our country.

Thank you.

(ends)

1619 बजे

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यूनियन बजट 2025-26 पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ-साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देगा। पिछले साल बजट पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्तीय घाटे को 4. 5 प्रतिशत से नीचे रखने की बात की थी। वर्ष 2026 के लिए इस घाटे का लक्ष्य 4.4 प्रतिशत रख कर उन्होंने इस घाटे को कम किया है।

महोदया, जनवरी, 2025 में आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने साल 2025 में वैश्विक ग्रंथ के अनुमान के साथ-साथ वर्ष 2026 के अनुमान में कटौती की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वर्ष 2026 में यह ग्रोथ 3.3 प्रतिशत रह सकती है।

महोदया, वर्ल्ड बैंक के अनुसार सामान और सेवाओं के निर्यात का वर्ष 2023 में भारत के जीडीपी में करीब 22 प्रतिशत का योगदान था।

(1620/SK/AK)

इस बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स का प्रावधान है, यह एक सराहनीय पहल है। इससे लोगों के हाथ में खर्च करने लायक पैसा बढ़ेगा और खपत में भी तेजी आएगी। वेतन भोगी कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट, 87ए के तहत 75000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। यह बजट वर्ष 2025-26 में मजदूरों, गरीबों, महिलाओं, किसानों, युवाओं, व्यापारियों और कृषि मध्यवर्गीय परिवारों की आर्थिक मजबूती समेत सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण के लिए दिशा प्रदान करेगा।

मैं विशेष कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बजट 2025- 26 में बिहार को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना की खेती को बढ़ावा मिलेगा। बिहार मखाने के कारण देशों और विदेशों में जाना जाता है। बजट में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से बिहार की 50,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। इसके कारण मिथिला क्षेत्र में विकास को दुगनी गति मिलेगी।

इस बजट में आईआईटी, पटना की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग संस्थाओं की स्थापना भी की जाएगी, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। आईएमएफ के डाटा - 2014 के अनुसार देश की पर कैपिटा इनकम 2,697 डॉलर है जबकि हाई इनकम कम्युनिटी कंट्री के लिए बेंचमार्क 23,380 डॉलर है। जुलाई, 2023 के रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की रिसर्च के अनुसार अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो 7.6 परसेंट प्रति वर्ष की दर से ग्रोथ करनी होगी। यह बजट इसी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है।

इस बजट में आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व के स्थानों के विकास के साथ भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों की डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दिया गया है। पिछले साल 3260.93 करोड़ रुपये दिए गए थे जिसे इस साल बढ़ाकर 3307.96 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बजट में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटीज़ में इनोवेशन पर खास फोकस किया गया है। ग्रेजुएशन लैवल पर एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाई गई हैं और आईआईटीज़ में 6,500 सीटों के इजाफे के साथ एडीशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की भी व्यवस्था की गई है। सरकारी स्कूलों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स का लक्ष्य रखा गया है, यह एक उचित पहल है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह बजट शिशुओं से लेकर युवाओं तक विकसित भारत बनाने की ओर पहल है।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पटना एवं बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार के अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है, यह एक सराहनीय कदम है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव पर गोपालगंज, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, में सबेया एयरफील्ड को उड़ान योजना में शामिल किया गया है। 473 एकड़ की परिधि में बाउंड्री पिल्लरिंग का काम चल रहा है। मेरा निवेदन है कि बिडिंग करके प्लेन चलाने की शीघ्र मंजूरी दी जाए क्योंकि इससे गोपालगंज की विभिन्न जरूरतें पूरी होंगी। यहां डेढ़ से दो लाख लोग खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं, इस कारण यहां विदेशी मुद्रा का आगमन भी सर्वाधिक है।

बिहार को रेलवे के लिए 10,086 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जो कि पर्याप्त नहीं हैं, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। गोपालगंज-थावे से दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए कोई ट्रेन नहीं है। हमने समय-समय पर पत्र द्वारा, सदन के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस विषय को संज्ञान में लाने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक समस्या का निदान नहीं हो सका है। मेरा निवेदन है कि गोपालगंज-थावे से दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए ट्रेन के परिचालन की समस्या का निदान किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

(1625/KN/UB)

1625 बजे

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : माननीय सभापति महोदया, आपने आम बजट वर्ष 2025-26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं।

मैडम, कोई भी बजट चाहे किसी सामान्य घर का हो, किसी जिले का हो, प्रदेश का हो या देश का हो, यह बजट उस संस्था के, उस इलाके की ग्रोथ का परिचायक होता है। प्रत्येक नागरिक इस बजट में अपने भविष्य को देखने का काम करता है। वर्ष 2025-26 का आम बजट 60 पन्नों का है। मैं देश की काबिल वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं। देश के विकास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, इस विजनरी बजट के लिए मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल तथा अपने नेता जयंत चौधरी जी की तरफ से समर्थन करता हूं।

हमें समझना होगा कि जहां विश्व 3 प्रतिशत की विकास दर से वृद्धि कर रहा है, जहां हमारा पड़ोसी प्रतिद्वंद्वी देश चाइना 5 प्रतिशत की विकास दर से वृद्धि कर रहा है, वहीं आज इन वैश्विक परिस्थितियों के दौरान भी भारत देश लगभग साढ़े 6 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है।

विकसित भारत वर्ष 2047 के संकल्प के लिए एक अनुमान लगाया गया है, जहां आज प्रति व्यक्ति आय लगभग सवा दो लाख रुपये है, इसे वर्ष 2047 तक 6 गुना अधिक बढ़ानी होगी, तब जाकर विकसित भारत का संकल्प जो आम आदमी देखता है, वह कहीं जाकर पूर्ण होने का काम करेगा। जलवायु परिवर्तन, तनावपूर्ण विश्व परिस्थितियां, एआई, अनेक प्राकृतिक आपदाओं, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेज को देखते हुए यह बजट बनाया गया है। प्रधान मंत्री जी ने जहां मेक इन इंडिया का लक्ष्य दिया, पिछले दिनों भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था, वहीं राष्ट्रपति जी के मेक फॉर वर्ल्ड के विजन को आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आगे बढ़ाते हुए इस बजट में फ्रेम करने का कहीं न कहीं काम किया है। हमारा यह सदन ऐतिहासिक सदन है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि विश्व में जितने भारतीय हमारे भाई-बहन हैं, अगले 20 साल भारत के हैं, जहां वर्ष 2047 तक हमें ग्रो करना है। मैं सब को कहता हूं कि जो लाइफ स्टाइल और बेहतर व्यवस्थाएं हिन्दुस्तान में मिल सकती हैं, शायद ही विश्व में कहीं और मिलेंगी।

पूरे देश के किसानों की शान स्व. चौधरी अजीत सिंह जी की 86वीं जयंती इसी सप्ताह 12 फरवरी को है। चौधरी साहब ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए और उन फैसलों ने हमेशा खेती करने वालों के जीवन में भरोसा लाने का काम किया, बदलाव लाने का काम किया। किसान बिरादरी, किसान समाज कभी भी अपने दिलों से उन्हें निकाल नहीं सकता

है। वे आज भी हमारे दिलों की धड़कन में बसते हैं। उसी विचारधारा को बढ़ाते हुए प्रधान मंत्री धन-धान्य योजना के अंतर्गत 100 ऐसे जिले, जो कहीं न कहीं फसलों के प्रोडक्शन में पीछे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन जिलों को शॉर्ट लिस्ट करना, उनको बजट के अंदर, योजनाओं के अंदर पांच तरीकों से उस क्षेत्र के किसानों को सशक्त करना, चाहे क्रॉप सेलेक्शन से लेकर क्रॉप रोटेशन हो, भंडारण की उचित व्यवस्था करनी हो, सिंचाई की नई व्यवस्थाएं करनी हों, ऋण का माध्यम हो, उच्च उपज वाले जीन मोडिफाइड बीजों का प्रत्यारोपण हो, ऐसी योजनाओं से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।

मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने दलहन के बारे में बताया है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन लाया गया। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए मंसूर, उड़द और तुअर की दालों के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना हो। राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन के अंतर्गत रोध प्रतिरोधक उत्पादन के लिए बीज को उपलब्ध करवाने की बात हो।
(1630-1640/RCP/CS)

हमारे किसानों को उर्वरकों की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए असम में नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह काम भी कहीं न कहीं किसानों के हित में है।

जीन बैंक की स्थापना, पशुपालन और डेयरी के लिए 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना, समृद्ध विकसित भारत की पहचान मजबूत खेती और मजबूत किसान इस बजट का परिचायक है।

वर्ष 2024-25 के अनुपात में, वर्ष 2025-26 में, बजट में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, इसके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, विश्व की सभी परिस्थितियों को देखते हुए, आज आम बजट में, डिफेन्स के क्षेत्र में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं दोनों पक्षों के लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं खुद एक युवा सांसद हूँ। हमारे देश का नौज़वान हमेशा मोदी जी की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री जी की तरफ देखता है, प्रदेश की सरकारों की तरफ देखता है। आज प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने देश के युवाओं का जो भविष्य है, उनको सही रोज़गार के अवसर प्रदान करने का, फुटवेयर या टॉय मेकिंग या अन्य सामानों के प्रोडक्शन का काम हो, नौज़वान ही हैं, चाइना जैसे देश और आसपास के अन्य देश, जो इनके प्रोडक्शन में आगे है, हमारे देश के नौज़वानों की ही यह ऊर्जा है, जो उनका सामना करके भारत को विश्व के पटल पर आगे रखने का काम करेंगे।

मेक फॉर वर्ल्ड के सिद्धांत पर आधारित स्किल इंडिया, कौशल विकास आदरणीय जयंत चौधरी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है।

वहीं पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्ट केन्द्र (नैशनल सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग) की स्थापना की जाएगी। युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। आईआईटीज में 6500 से अधिक सीटें बढ़ाये जाने के लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो या मेडिकल कॉलेजेज में 75,000 से अधिक सीटें बढ़ाने की बात हो, एआई में भारत को आगे ले जाने के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश हो या हेल्थ सेक्टर हो, कैंसर से लड़ने के लिए 200 डे-केयर सेन्टर बनाने की बात हो, मैं आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर और आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर से अनुरोध करूँगा कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर में ये स्थापित होंगे, तो निश्चित रूप से एम्स पर जो लोड पड़ता है, वह कम होगा। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आई हैं।

कैंसर मेडिसीन्स को टैक्स फ्री करना, बुजुर्गों के लिए मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराना आदि सारी बातें बहुत ही हितकारी हैं। चाहे पीएम स्वनिधि योजना हो, जल-जीवन मिशन, न्युक्लियर एनर्जी, टूरिज्म और 12 लाख रुपए तक की आय वाले कर दाताओं को राहत पहुंचाने की बात हो। मेरे पास कई पन्नों में लिखी हुई ऐसी कई बातें हैं, जिनके लिए हम धन्यवाद करते हैं और इस आम बजट का समर्थन करते हैं।

मैं अपने देश के नौज़वानों से इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई हथियार दिखाने वाले को, कोई गलत बात सिखाने वाले को हम अपना रोल मॉडल नहीं बना सकते हैं। अगर हमें अपना रोल मॉडल बनाना है, हमें देश की तरक्की को आगे ले जाना है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की तरह विज़न हो। एनडीए सरकार की देश को आगे बढ़ाने की जो ज़बरदस्त नीतियाँ हैं, उनके समर्थन के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

(इति)

1634 hours

*SHRI GOPAL JEE THAKUR (DARBHANGA): The budget 2025-26 presented by Shrimati Nirmala Sitharamanji under the leadership of the Vishwakarma of new India, and most popularly applauded Prime Minister Shri Narendra Modiji is dedicated to aspersion and welfare of the common-man in the country. This budget is likely to be proved a new chapter, if progress and growth is taken into account. The have-nots, peasants, women-folk, youth, middle-class, old-aged-people, almost all the category of citizen have been kept in mind while preparing this budget. Road-connectivity, healthcare, education, the Railways, defence-sector, games and sports, rural development along with employment-generation have also been given prominence in this budget.

Hon. Chairperson, all the inhabitations of Mithila region are glad and proud that hon. Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman put on the Saari embroidered with Mithila Painting drawn by Padmashree Dulaaree Devi while presenting the budget. Madam, I belong to Mithila region of the State named Bihar; and special attention has been paid to Mithila and this budget, and for this I again express my gratitude to the Hon'ble PM Shri Narendra Bhai Modiji and the Finance Minister.

Madam, budgetary provision to set- up a Makhana (lotus-seeds) Board and economic package for revival of Koshi Canal Project would certainly be a boon for Mithila region. Ninety percent of the total production of Makhana in India takes place in Mithila region. Late Hon'ble Atalji had established a national Makhana Research Centre in Darbhanga. During the tenure of Congress Government in 2005 its status of national institute was withdrawn. After a lapse of 18 years, Shri Narendra Bhai Modi accredited Makhana to be a cultural identification of Mithila region and accorded nationalistic status to the institution for

* Original in Maithili

promoting the cult. The district-magistrate of Darbhanga has also been awarded by Hon'ble Prime Minister under with 'ONE DISTRICT, ONE PRODUCT.' And the lotus-seeds produced in Mithila was categorically honoured with GI-tag in 2022. The only research centre for taking up research work on Makhana and other agri-products cultivated in water-bodies has also been established in Darbhanga. EMFME Scheme launched under '*Atamanirbhar Bharat'* campaign, the entrepreneurs engaged in processing of Makhana and other food products are provided 35% of subsidy if a loan up to Rupees 10 lacs is sanctioned to them. Simultaneously pisciculture is also being promoted under PM *Matsya Sampada* scheme. The cultivation of lotus-seeds has been expanded from 15 thousand hectares to 40 thousand hectares on account of the positive decisions taken by the Government of India in last five years. Lacs of farmers and entrepreneurs are engaged in cultivation of Makhana and it's processing. To this effect I wish to demand from the Government of India that headquarter of the proposed Makhana Board be established in Darbhanga and a training centre of international accreditation and a Farmers Hostel be constructed within national Makhana Research Centre, Darbhanga and financial aid be provided to both with according it the status of an autonomous body. The sanctioned post of research-fellows be increased and separate post of a director be created for the institution and be posted there. We are sure that the promises made by Modiji has always been fulfilled and the vogue will continue in the future.

Madam, the Members from the opposition benches were meandering on different point of views with regard to this budget. In 1951, the first president of the country had sanctioned setting of a Mithila Sanskrit Post-graduation Research Centre in the Mithila region I belong to, and the foundation-stone was also laid there. And the same plan and project is being executed by the Hon'ble Prime Minister and Hon'ble CM Shri Nitish Kumar and the state government of Bihar has sanctioned 48

crore Rupees for this project. The Mithila which was divided into 2 parts has been unified by our applauded Prime Minister Shri Narendra Modiji with sanction of Rs. 516 crore and construction of a great railway bridge on Koshi river. I congratulate the Finance Minister that decisions made with consecutive budget allocation and has resulted into construction of the biggest bridge on Koshi river after 88 years. Even the long pending issue of Sankree-Hasanpur railway line has been resorted after 46 years. Hon. Prime Minister has accorded construction of 88 airports in the country under UDAN Scheme and a few of them are located also in Bihar. Constructed with a cost of Rs. 1300 crore, the international airport Darbhanga is likely to be completed and now-a-days the facility is availed by 25 thousand crore passengers across the country.

Madam Chairperson, a planetarium has been constructed in Darbhanga Bihar, super specialty hospital has been inaugurated by Hon'ble Health Minister Shri J.P Nadda in Darbhanga, Bhagalpur, Gaya and Muzafarpur. Almost in all the big cities of the state survey for metro rail is being carried out. On 13 of November widely applauded Prime Minister visited the state for inauguration of laying of underground gas pipeline amounting to Rs. 3600 crore in Darbhanga, Supaul, Madhubani, Sitamarhi, Sheohar and the people in all this area are full of zeal. Broadcasting from many FM radio stations. Has also been taken up in the state. The construction- work for AIIMS Darbhanga is being expedited with cost of Rs. 1200 crore under leadership of hon. Prime Minister and the Health Minister Shri Gadkariji. Shrimati Nirmala Sitharamanji has presented the eighth consecutive budget and the budgetary allocations are being widely praised.

Dozens of bridges have been constructed on the river Ganges. Six- lane railway bridge on Rajendra-setu, six-lane bridge on Gandhi-setu, six-lane bridge in Deegha-ghat is a fruition of such budgetary allocations. The fertilizer in Barauni has also been revitalized by Hon'ble Prime Minister. He has also sanctioned in amount of Rs. 11,000 crore

for solving the perennial problem of devastating flood in the state. All of us belong to Mithila region and Hon'ble Prime Minister has released of the Constitution of India in the language spoken by Mother Janki 7000 years ego in the Treta era. He has also honoured late Jananayak Karpoori Thakurji with Bharat Ratna. Whether it be expansion of Patna airport or construction of green field airport or renovation of IIT Patna or promoting tourism sector with development of the historical sites deleted to Lord Buddha all these items has been included in budget this year. Providing reservation to the EBC category and declaring it constitutionally valid has also fructified during the tenure of this government. Providing honour to the physically-handicapped, passage of Naari Sakti Vandan act has been another feather of governance. Now India is advancing to become the third largest economy of world and the government is working on that line. PM Vishwkarma scheme, PM Suryaghar Yojna, providing LPG connection, PM Swasthya Yojna, Jan-dhan Yojna, distributing free ration to 80 crore people, crop insurance scheme, has been implemented. Thank you.

(ends)

(1645-1650/SMN/RV))

1645 hours

*SHRI BALWANT BASWANT WANKHEDE (AMRAVATI): Hon. Chairperson, thank you. I am too surprised like my other colleagues here that the budget presented by Finance Minister is a Union budget or a particular state's budget. It is necessary to talk on the future of the nation on the backdrop of 2025-26 budget. Government has announced a lot of schemes but it differs from the reality. The budget should consist of the issues related to Social justice, Education, Unemployment, Health, Agriculture, industrial growth etc. but it lacks everything. Hence, I oppose the bill. Hon'ble Chairperson, we are dreaming of becoming 3rd largest economy in the world, but we will not fulfill this dream. Indian economy belongs to the rural India. Farmers, Workers, and Youth are important stakeholders in this system. In this budget, this main component has been ignored. Our Prime Minister had said in 2014 that, we would double the income of farmers, but never told us how he would double the income. I am presenting the real picture here. In 2014, I had an yield of 18 quintal cotton in 1 acre, but this year only 8 quintal cotton I could yield. Our budget talks about 5 years program of cotton development, but fails to explain how it is going to increase. There is no announcement for KG to PG education. There are many issues pending like Anganwadi Sevika's salary hike, teacher recruitment, lack of classrooms for education, absence of basic facilities in the schools. We are dreaming of tomorrow's developed nation. On backdrop of this, how we can think of tomorrow's developed nation? As of today, we are providing free food grains to 80 crore Indians. We should not take pride in it. How we are going to make tomorrow a developed nation? Prime Minister said in his speech that he uplifted 25 crore people above the poverty line but didn't provide any logic or concrete analysis. He talked

* Original in Marathi

about uplifting of 25 crore people above the poverty line, but still providing free food grains to 80 cores people. If you calculate this, it is around 105 crore people. What about the actual condition of the rest of 35 crore Indians? Prime Minister didn't tell the exact situation of these 35 crore people. Hon. Chairperson, in my constituency at Melghat, one youth committed suicide for not getting wage payment under the MGNREGA scheme. We can imagine the economic picture of the nation through this incident. The numbers given by Prime Minister in President's Address were hard to believe, I don't know which agency provided this data. Prime Minister said 4 core people got their houses. Earlier, he had said he'll give houses to all Indians, but in last 11 years, only manages to provide only 4 crore houses. At the same time, did not provide information about how many houses left for construction. Later, he said 12 crores toilets have been constructed in our county, but no data provided. In her speech, the government said that it has provided water through taps to 12 crore people without data. Later he claimed that the government identified more than 10 lakh people who are false beneficiaries of various schemes which may cost 3 lakh crore rupees. I'm going to seek all this information through RTI. Adding to this, he said under Swachh Bharat Mission, 2 lakh 300 crore got to treasury without any analysis. Under the Aayushman Bharat Scheme, 1 lakh 20 crore have been saved which is money of the citizens of this country. He claimed it, but how? Around Rs. 30 crore have been saved due to Jan Aushadhi centers. But, how? Don't know. By cleaning their own houses, 70 crore people saved money. But, how? Nobody knows. What is this calculation? Adding to this, by doing soil testing, Rs. 30000 saved every acre, and it is claimed by the government.

Maharashtra government started Ulhas scheme. We don't know, who's brain working behind this scheme, but Maharashtra government doing pathetic work through this scheme. Under this scheme, government searching for people aged 35 to 70 who are illiterate and

working for gaining literacy. But on the contrary, the children and all the younger students, are having less number of teachers in the school. But the government is trying to literate people who are aged and between 35 to 70. They say our Prime Minister is about to become Vishwa Guru but looking at the pathetic condition of this scheme, our PM cannot be Vishwa Guru.

I want to speak on distribution of social welfare fund under Union budget 2025-26. This budget deprives of funds for SC and ST community. Dr. B. R. Ambedkar said, “Democracy is a medium to bring the social and economic change in individual life. Political democracy should convert into social democracy. Otherwise, there would be a threat to democracy.” As a part of constitutional duty, Part 4, article 36 to 51 in the Constitution of India, state should follow policy directives. Article 46 underlines educational, social and economic justice. In this budget, there is nothing for the deprived class, minorities, bahujans etc. If we have the agenda i.e. Samvidhan Pe Baat, Vikas Ke Saath, then we must stick to the Constitutional values. There should be honest efforts for it. If the efforts are honest, we will give justice to deprived classes, minorities, bahujans etc.

We are unable to see our share of education, health, livelihood, employment and dignified life in this budget. I want to highlight the issues related to my constituency through this budget speech. There is a narrow-gauge train runs between Murtijapur to Achalpur, needs to be converted into broad-gauge. For this project, Maharashtra Government made some provision. Kindly approve this project and start it immediately. Nalganga Vainganga river linking project should also start as early as possible. I would request Civil Aviation minister, to look into Amravati Airport project issue and start the functioning of the airport as early as possible. The region has good cotton and oranges production, so kindly start a processing industry for it. There is cotton mill issue, which is pending. Many youth have committed suicide due to this

pending issue. Salaries are not getting on time, growing unemployment is also an important issue. Due to the oppressive conditions of forest department, in the region of Melghat, many projects related to drinking water, electricity and other services have been cancelled. Marathi language has been accorded the classical language status by the government. This year, Marathi Bhasha Sahitya Sammelan is being organised here at Delhi. When this sammelan was organised at Ghuman, Punjab, the then railway minister arranged two trains free of cost to reach the venue. This government has given classical language status to Marathi, but charged triple fare for the Delhi journey with applicable waiting charges. Mahatma Jyotiba Phule once said, 'society is like a plant and we are fruits of this plant'. We should work to uplift society. The budget should be based on these values. In this budget, allocation for social welfare fund is not up to the mark. NDA is completing 11 years now, but still keep on asking what Congress has done during last 70 years. This Government is not going beyond, 'Hindu Khatre main Hai,' Emergency, Batenge Katenge, Ek hai toh safe hai etc. They always debate on emergency but. I am mentioning here with full confidence that, emergency was supported by RSS.

Lastly, I oppose this bill and conclude.

(ends)

(1655/GG/SM)

1657 बजे

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं भोजपुर जिले की महान जनता का भी आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे जिता इस सदन में भेजा है।

महोदया, वर्ष 2025-26 के लिए 50,65,345 करोड़ रुपये का केन्द्रीय बजट कॉर्पोरेटों को राहत देकर आम जरूरतमंदों का बोझ बढ़ाने वाला बजट है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस सरकार का पहला आम बजट खाद्य वस्तुओं की बढ़ती मंहगाई, रुके हुए आर्थिक विकास, घटते रोजगार, गिरता रुपया, आम जन की घटती क्रय शक्ति, किसानों के आन्दोलन और विकासमान अर्थव्यस्थाओं पर ट्रम्प के अमेरिकी प्रशासन की धमकियों के बीच पेश किया है, जिसका ताजा उदाहरण अमेरिका द्वारा भारतीयों को घुसपैठिया कहकर, हाथ में हथकड़ी और कमर में जंजीर डालकर खूंखार अपराधियों की तरह अपमानजनक तरीके से भारत भेजने की घटना है।

महोदय, जनता एक ऐसा राहत देने वाला बजट चाहती थी जिसमें बढ़ रही आर्थिक विषमता कम हो और आम जनता की क्रय शक्ति बढ़े, लेकिन भाजपा सरकार ने पिछली गलतियां सुधारने के बजाय इस बार भी अमीर परस्त बजट ही पेश किया है।

मध्यम वर्ग को आयकर में कुछ राहत मिली है, लेकिन मजदूरों, किसानों और आम मेहनतकश जनता को मुश्किल हालातों में ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जो चिन्ताजनक है। उन्हें राहत देने के लिए आवश्यक उपभोक्ता सामग्री पर जीएसटी में कमी करने और जनकल्याणकारी योजनाओं में खर्च बढ़ाने की जरूरत को अनदेखा किया गया है। कॉरपोरेटों और अमीरों पर टैक्स बढ़ाने के लिए सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी साफ तौर पर उजागर हो रही है। निजी क्षेत्र के लगातार बढ़ रहे मुनाफे के बावजूद सरकार की प्राथमिकता अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की जगह जनकल्याण, सामाजिक, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च कम करने की है। यह बिल्कुल जनविरोधी दिशा है। केन्द्रीय योजनाओं पर सरकार ने पिछले साल बजट में घोषित मद से 93,978 करोड़ कम खर्च किये।

(1700/CP/RP)

प्रधान मंत्री आवास योजना और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन पर पिछले साल घोषित राशि का मात्र 50 प्रतिशत से भी कम खर्च किया गया। यही नहीं मनरेगा, ग्राम सड़क योजना अनुसूचित जाति के लिए स्कॉलरशिप आदि में भी की गई घोषणा से कम राशि खर्च की गई। महिला स्वास्थ्य और बाल विकास पर पूरी आबंटित राशि खर्च नहीं की गई और उल्टे इनके बजट में भी कटौती कर दी गई है। इस साल के बजट में कृषि और कल्याण विभाग का आबंटन घटा दिया गया है। खाद्य और जन-वितरण विभाग के बजट में भी कमी की गई है।

स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रिन्योरशिप के नाम पर पिछले बजट में काफी कुछ कहा गया, लेकिन इस मद में दिए गए 1,435 करोड़ में से सरकार ने मात्र 669 करोड़ रुपये ही खर्च किए। स्वास्थ्य पर भी वास्तविक खर्च पिछले साल की गई घोषणा से कम रहा। आशा, आंगनबाड़ी, मिड-डे-मील व अन्य स्कीम वर्कर्स को नियमित करने और कम से कम न्यूनतम मजदूरी देने की मांग को फिर से नकार दिया गया है, जबकि पिछले दिनों गुजरात हाई कोर्ट ने इन्हें स्थायी करने का फैसला दिया है। इसी तरह जग्गो बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में केंद्र सरकार से अस्थायी, आकस्मिक और अनुबन्ध के आधार पर श्रमिकों की भर्ती बंद करने और उचित व स्थिर रोजगार प्रदान करने के लिए कहा गया है। बजट में इस आदेश को लागू करने के लिए वित्तीय आबंटन तो दूर कोई चर्चा तक नहीं की गई है। स्थायी नौकरियों को लेकर कोई नीति घोषित नहीं की गई, जिससे बेरोजगारी की समस्या और गहराएगी।

सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जबकि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में आबंटन घटाया गया है। जाहिर है कि देश के किसान और आम जन को बड़े निजी कॉरपोरेशन्स की दया पर छोड़ा जा रहा है। सरकार ने पिछले साल पूंजीगत निवेश बढ़ाने की घोषणा कर खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है कि घोषणा से 1.84 लाख करोड़ रुपये कम खर्च किए गए हैं। इस बजट में जरूरी क्षेत्रों में खर्च न बढ़ाने से सरकार की गलत दिशा में जारी प्राथमिकताएं फिर से उजागर हुई हैं। आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि कुल बजट खर्च में दिख रही बढ़ोतरी का करीब 40 प्रतिशत तो लिए गए कर्ज का अतिरिक्त ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाएगा, जबकि जरूरतमंद आमजन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं जीएसटी व इन्कम टैक्स की हिस्सेदारी कॉरपोरेट टैक्स से ज्यादा हो रही है। वर्ष 2014-15 में कॉरपोरेट टैक्स से 4.49 लाख करोड़ रुपये व आम जनता से 2.66 लाख करोड़ रुपये टैक्स से प्राप्त हुए। ये वर्ष 2023-24 में क्रमश: 9.11 लाख करोड़ रुपये एवं 10.45 लाख करोड़ रुपये हो गए।

यह बजट मोदी सरकार की अपनी क्रोनी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट क्षेत्र के पक्ष में जारी आर्थिक अराजकता को पुन: स्थापित कर रहा है। मजदूरों की वास्तविक मजदूरी दर में आयी कमी और उनके नियमित रोजगार के कम हो रहे अवसर की सच्चाई को अनदेखा किया गया है, जबकि सरकार जानती है कि कॉरपोरेट टैक्स का मुनाफा चार गुना तक बढ़ गया है, फिर भी सरकार कॉरपोरेटों पर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती। ऐसे में यह बजट वर्तमान आर्थिक विषमता, घटती मजदूरी दर और घटते रोजगार के अवसरों पर हमला करते हुए कॉरपोरेटों के मुनाफे को और बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं में कटौती, किसानों के लिए कोई राहत नहीं और स्कीम व अन्य मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी करने वाला बजट है।

इससे आर्थिक असमानता और बढ़ेगी, बेरोजगारी व महंगाई की मार तेज होगी, जबकि कॉरपोरेट मुनाफे लगातार आसमान छूते रहेंगे।

सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने का दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ है, क्योंकि कृषि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बजटीय आबंटन पिछले साल की तुलना में घटा दिया गया है। एमएसपी पर भी बजट चुप है। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स नहीं बढ़ाया, जबकि अब उनका कुल कर भुगतान व्यक्ति आयकर से भी कम हो गया है। वास्तविक मजदूरी घटी, लेकिन कॉरपोरेट मुनाफा चार गुना बढ़ गया।

सरकार ने मिडिल क्लास को 12 लाख रुपये तक टैक्स में छूट देकर राहत दी है। गरीबों और मजदूर वर्ग का क्या? वे जीएसटी के रूप में सबसे अधिक कर का भुगतान करते हैं। इसमें कोई छूट नहीं है। आप गरीबों और श्रमिक वर्ग से बढ़ती कीमतों से लड़ने की उम्मीद कैसे करते हैं?

भारत एक युवा देश है, फिर भी बजट में सार्वजनिक वित्त पोषित कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं की गई है। नई शिक्षा नीति, 2020 आने के बाद लोगों को सरकारी संस्थानों में भी पढ़ने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है।

(1705/NK/NKL)

अब नई शिक्षा नीति में पब्लिक फंडेड मॉडल को अब लोन बेस्ड मॉडल में बदल दिया गया है। बीमा क्षेत्र में सौ प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देकर सरकार ने किसानों और आम लोगों को निजी कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया है।

देश जातीय जनगणना कराकर संख्या के आधार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में आरक्षण की सीमा बढ़ायी जाए। देश में भूमि सुधार लागू करने के लिए भूमि सुधार आयोग का गठन किया जाए। सभी भूमिहीनों को आवास, कृषि भूमि और पक्का मकान दिया जाए। देश में सिलिंग एक्ट कानून को सख्ती से लागू किया जाए। देश के खुदरा और थोक व्यावसाय की दशा सुधारने के लिए व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाए, खासकर फुटपाथ दुकानदारों, छोटे और मंझौले व्यावसायियों को पांच वर्ष के लिए दो-दो लाख रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। सोन नदी में प्रस्तावित इन्द्रपुरी जलाशय के निर्माण तथा नहरों के पक्कीकरण का कार्य शीघ्र किया जाए। बटाइदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाए।

(इति)

1706 बजे

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : सभापति महोदय, यह बजट देश की जनता के साथ बड़ा खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी धोखा देकर सत्ता में आयी और लाठी लेकर सत्ता में बैठी। इस बजट में कहीं भी आम आदमी के हित की कोई बात नहीं है। किसान, नौजवान, बहन-बेटी किसी का इसमें तरक्की का उल्लेख नहीं है। ये किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। किसान के इनपुट की कीमत बढ़ा दी गई है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, हम लोगों को आशा थी कि कृषि यंत्र ट्रैक्टर से जीएसटी हटायी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कीटनाशक और उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में आपके ही लोग फर्जी खाद बना रहे हैं, इभको और कृभको को फर्जी पोटाश सप्लाई कर रहे हैं। 27 रुपये क्विंटल राख खरीदकर पोटाश कहकर बेच रहे हैं। सब जानते हैं कि राख नेचुरल होता है, उसमें पोटाश होता ही है।

हमें उम्मीद थी कि सरकार किसानों की फसल खरीदने का काम करेगी, एमएसपी को लेकर आज भी किसान आंदोलनरत हैं। सरदार डल्लेवाल साहब कितने दिनों से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार को फुर्सत नहीं है, लेकिन इनको किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। आज किसान का गेहूं बीस से बाइस रुपये किलो बिकता है, जब वही आटा पीस कर आता है तो 47 रुपये किलो हो जाता है, वह ब्रांडेड हो जाता है। हमारे जनपद में जितने भी कारखाने हैं, उन पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया है। सरकार मजदूरों के हित की बात नहीं कर रही है, मनरेगा में मजदूरी 270 रुपये है, मजदूर साढ़े चार सौ रुपये में मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजदूरी 200 रुपये रखी है, ये सब फर्जी आंकड़े हैं। आज की तारीख में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है।

जहां तक नौजवानों के लिए रोजगार की बात है। बैंकों की स्कीम लाते हैं, बैंक में खुद उतना ही भ्रष्टाचार है, जितना सरकार में है। आज सच्चाई यह है कि सरकार में बैठे लोग धनाढय होते जा रहे हैं, तीन एकड़ के किसान तीन चार हजार करोड़ के आदमी हों गए, यह सरकार का ही कमाल है। छात्रों की शिक्षा की बात की गई। आजादी के मतवाले कहा करते थे, सिंचाई मुफ्त होगी, शिक्षा मुफ्त होगी, दवाई मुफ्त होगी, लेकिन आज शिक्षा को गरीब किसान के बच्चे के हाथ से किताब छीन ली गई है। मेडिकल शिक्षा हो, इंजीनियरिंग शिक्षा हो या अन्य प्रोफेशनल कोर्स की शिक्षा हो, आज ये शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। अब गरीब का बच्चा अम्बानी और अडानी का मजदूर बनेगा, ऐसी ही सरकार की नीति है। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैंसर से बहुत ज्यादा ग्रस्त है।

(1710/KDS/VR)

वह प्रदूषण के कारण ग्रस्त है। सरकार आंख मूंदे बैठी है। ऐसा कोई गांव नहीं है, जिसमें आठ से दस तक कैंसर के मरीज न हों। हम लोग मांग करते रहे कि आप कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फर नगर में एक कैंसर अस्पताल खोल दें। आज इन्होंने डिटेक्शन सेंटर की बात की है, लेकिन यह जमीन पर तब आएगा जब आधी आबादी कैंसर से मर चुकी होगी। आज कैंसर, हृदय रोग क्यों फैल रहा है, पक्षाघात क्यों हो रहा है? इसकी जांच कराने की ये बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां का जो मरीज एम्स आता है, वह बहुत किराया खर्च करके आता है। उसे एक साल से लेकर 2 साल तक का समय मिलता है और जब उसकी बीमारी का इलाज होने का समय आता है, तब तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।

महोदया, हमारा जनपद एनसीआर में है। जब से हमारा जनपद एनसीआर में आया, हमारा जीवन दूभर हो गया। विकास का कोई काम मुजफ्फरनगर या शामली में नहीं हुआ। अलबत्ता कितने प्रतिबंध लग गए। किसान 15 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकता। किसान कार नहीं चला सकता। हमारी मांग है कि इस एनसीआर से हमारा पल्ला छुड़ाइए। हमें महारोग लगता है, महा बीमारी लगती है। इसे एनसीआर से बाहर कर दें या इन प्रतिबंधों को हटा दें। उद्योगों पर भी प्रतिबंध है। इसके साथ-साथ एक रैपिड रेल चली। उसकी बड़ी चर्चा थी कि वह मुजफ्फरनगर तक जाएगी। हम मांग करते हैं कि मेरठ के स्थान पर उसे सहारनपुर तक चलाइए व बिजनौर भी भेजिए। रैपिड रेल चलाने की ये बात करते हैं। अब बच्चों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अयोध्या की बेटी के साथ क्या हुआ? बहन-बेटी सुरक्षित नहीं हैं। ये बार-बार कहते हैं, लेकिन उसका उल्टा करते हैं। हमने मांग की थी। हमें अपेक्षा थी कि गांव- गरीब की बेटी, किसान की बेटी शहर में आकर स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सके, इस हेतु आप छात्रावास की व्यवस्था करेंगे, लेकिन छात्रावास नहीं हैं। गांवों में उच्च शिक्षा संस्थान नहीं हैं। शहर में छात्रावास नहीं हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे, यह हमारी समझ से परे का मामला हो गया है।

मैडम, लड़कियां पढ़ने से रह जाती हैं। एक हजार बेडों का कैंसर का अस्पताल लखनऊ में बना हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है कि सरकार राजनीति के फेर में आकर अस्पताल में डॉक्टर नियुक्त नहीं कर रही, क्योंकि अस्पताल अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार ने बनाया था। यहां पंकज चौधरी जी बैठे हुए हैं। ये बड़े सीनियर मेंबर हैं। ये राज्य मंत्री बने हुए हैं। ये बहुत वरिष्ठ हैं और इनकी कनिष्ठ इनकी सीनियर हैं। ये कह रहे हैं कि किसान को 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये का कर्जा दे दिया। हम कहते हैं कि आप किसान को कर्ज से मुक्त करें। आपने किसान को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना गुलाम बना लिया है। आज कोई किसान ऐसा नहीं है, जिसकी जमीन के कागज बैंक में न रखे हुए हों। आदरणीय चौधरी जी, आप भी

किसान हैं। वैसे तो मसाले आदि का बहुत काम है, लेकिन आप किसान भी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बिल का जब रिन्यूअल कराता है, तो उसे अपना सारा पैसा जमा करना पड़ता है। उसके पास कौन-सा व्यापार है कि सारा सामान बेचकर वह पैसा ले आएगा? सब जानते हैं कि बैंकों के बाहर दलाल बैठे हैं। वे उसे 10 रुपये रोज पर देते हैं। जिस तरह दुकानदान की सीसी लिमिट रिन्यूअल होती है, इस पर तो कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा। किसान के क्रेडिट कार्ड का भी 3 साल के लिए आप उसी तरह से रिन्यूअल कर दें। आप ब्याज जमा करा दें, तो शायद अच्छा रहेगा। किसान को लूट से बचाने के लिए आपको कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा।

महोदया, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, 5 साल की गारंटी है। जो 3 साल पहले बनी थी, वह टूट गई और उसमें गड्ढे हो गए। कोई उसे नहीं देखता। एनएचएआई में काम हुआ, लेकिन में एक अनुरोध करना चाहता हूं कि एनएच58 जो दिल्ली से देहरादून मार्ग है, उस पर जब चलते हैं और मेरठ पार करते हैं तो एक्सिडेंट होने शुरू हो जाते हैं। जड़ौदा, संधावली, कुकड़ा, रोहिल्ला के पास फ्लाई ओवर ब्रिज बने बिना काम चलने वाला नहीं है, लेकिन कोई देखने-सुनने वाला नहीं है। सब ठेकेदार इनकी कृपा पर जाते हैं और लूट-खसोटकर चले आते हैं। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रोटी-बेटी का रिश्ता है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि करनाल से बिजनौर तक, वाया शामली मुजफ्फर नगर और पानीपत से मेरठ तक एक रेल रूट बनाया जाए, ताकि पश्चिम के लोग भी वहां रह सकें व जा सकें।

(1715/MK/SNT)

महोदया, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री जी जब उत्तर दें तो इन बातों का समावेश करें। इस बारे में वे कुछ कहें। वे मना करें या हाँ करें, वे कुछ तो कहें। बहरहाल वे बहकना छोड़ दे।

आप सरदार डल्लेवाल का पता लगाइए। मेरा यह भी अनुरोध है कि जिन लोगों ने किसान आंदोलन में हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर आंसू गैसे के गोले छोड़े थे, उनको चिह्नित करके उनके विरुद्ध मुकदमें दर्ज किए जाएं और उनमें शामिल सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1715 बजे

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : आदरणीय सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आम बजट 2025-26 पर बोलने का समय दिया।

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 का यह आम बजट प्रस्तुत हुआ है। यह काफी उदार और देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना साकार करने वाला बजट अगले 25 वर्षों की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा। गरीब, युवा, मध्यम वर्गों, अन्नदाता, किसानों, वंचितों और नारी शक्ति के भविष्य को ध्यान में रखकर बजट का प्रारूप आया है। इसके लिए मैं माननीया वित्त मंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन और दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रही हूं।

आदरणीय महोदया, मैं मिथिलांचल क्षेत्र शिवहर, बिहार से आती हूँ। यह पूर्णरूपेण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वहां के लोग गरीबी और फटेहाली की स्थिति में हैं। हमारे यहां एक ही फसल सही ढंग से हो पाती है, क्योंकि प्रतिवर्ष पूरा मिथिलांचल एवं उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। वहां के मखाना किसानों के कल्याण के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बिहार में 'मखाना बोर्ड' की स्थापना का प्रस्ताव काफी हर्ष की बात है। निःसंदेह यह बोर्ड मखाना किसानों के लिए वरदान साबित होगा। स्थानीय मखाना किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराने में बोर्ड मदद करेगा। मखाना का उत्पाद, प्रसंस्करण, विपणन एवं उचित मूल्य मखाना किसानों को मिलेगा। वहां समृद्धि होगी, उनकी आय बढ़ेगी, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देती हूं। इसी प्रकार मिथिलांचल में 'पश्चिमी कोसी नदी परियोजना' का प्रस्ताव भी क्षेत्र के लोगों के लिए विशेषकर किसानों के लिए काफी खुशी की बात है। सरकार 'पश्चिमी कोसी नहर परियोजना' के लिए वित्तीय सहायता देगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में करीब 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा और समुचित सिंचाई की सुविधा मिलेगी, साथ ही बाढ़ से भी राहत मिलेगी।

इसी क्रम में 'उड़ान योजना' के अंतर्गत हवाई अड्डों का विस्तार एवं विकास के लिए 'ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट' बिहार को देने का प्रस्ताव है। यह पटना और बिहटा के लिए चल रही विस्तार परियोजना के अतिरिक्त है।

मुझे आशा है कि बिहार को नया एयरपोर्ट जल्द मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होगा। वर्तमान में दरभंगा एयरपोर्ट कुछ ही वर्ष पहले आम यात्रियों के लिए आरंभ हुआ है। वहां अभी छोटा रनवे है और उसे विस्तार की आवश्यकता है। वहां रात में भी विमान लैंडिंग की सुविधा होनी चाहिए। टर्मिनल और यात्री सुविधा का भी विस्तार होना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करती हूं कि दरभंगा हवाई अड्डे के विकास की परियोजना को इसी बजट में मंजूरी देने की कृपा करें।

आदरणीय महोदया, बिहार अति पिछड़ा प्रदेश है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफी प्रयासरत हैं। केंद्र के द्वारा काफी वित्तीय सहायता मिल रही है, किंतु अभी तक यह विषय केंद्र के पास लंबित है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से वहां औद्योगिक विकास होगा।

मिथिलांचल में, विशेषकर शिवहर में इथेनॉल की फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और एक कागज की फैक्ट्री लगाने की अपार संभावनाएं हैं। इसे स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा केंद्र सरकार प्रदान करे, यह मेरी मांग है।

इस बजट में रेलवे को बिहार के लिए 10 हजार 66 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। 98 रेलवे स्टेशनों का अमृत स्टेशनों की परियोजना के तहत विकास कार्य जारी है। बिहार को 12 वंदे भारत ट्रेन्स मिली हैं। दरभंगा और आनंद विहार के बीच एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मंजूरी मिली है, किंतु यह बड़ी अफसोस की बात है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर अभी तक रेल सेवा से वंचित है।

(1720/SJN/AK)

मैं बार-बार इसकी मांग करती हूं। मैं फिर से आदरणीय रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे इस दिशा में तेजी से काम करने की मंजूरी दें।

आदरणीय महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने पटना, आईआईटी के विस्तार के लिए प्रस्ताव किया है। आने वाले पांच वर्षों में देश में 75,000 मेडिकल सीट्स को बढ़ाने की योजना प्रस्तावित है। इसी क्रम में देश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा के तहत मैं मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग करती हूं। वित्त मंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इन्कम टैक्स नहीं लगेगा, यह कदम बहुत ही सराहनीय है।

महोदया, मैं भगवान बुद्ध की जन्मस्थली तथा पर्यटन स्थल में विस्तार और सौंदर्यीकरण की सराहना करती हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि देश की आधी आबादी के लिए काफी कारगर होगा कि किसी भी देश की प्रगति का रास्ता महिलाओं के विकास पर ही निर्भर करता है। जिस देश की नारी शक्ति शिक्षित और आत्मनिर्भर होगी, वह देश उतनी ही तरक्की करेगा। जब बिहार मजबूत होगा, तो देश मजबूत होगा। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के बारे में चिंतित रहे हैं।

आप देखिए कि केन्द्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण और तीन तलाक कानून पास किया गया है, ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें। आज महिलाएं पुरुषों के साथ-साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के आर्थिक अभियान में सहयोग कर रही हैं। यह हर्ष की बात है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी पर गर्व करती हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बिहार में वृद्धावस्था पेंशन मात्र 400 रुपये है, उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की कृपा की जाए। बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये तथा नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, मैं इसकी भी मांग करती हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने मिथिला प्रिंट की साड़ी पहनकर बजट भाषण दिया था, इससे उन्होंने मिथिलावासियों का मान-सम्मान बढ़ाया है। उद्यमी महिलाओं का जो मान-सम्मान बढ़ा है, इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। मैं बजट 2025-26 का समर्थन करती हूं।

जय हिन्द, जय बिहार, जय शिवहर, जय मिथिलांचल।

(इति)

1722 बजे

श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान (रतलाम) : सभापति जी, आपने मुझे बजट 2025-26 के पक्ष में बोलने की अनुमति दी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

भारत की विकास यात्रा के अमृत काल को आज मोदी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। नीतियों एवं नियमों में गरीब, मध्यम, युवा, महिलाओं तथा किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण की सुविधा मिलती है। इस बजट में तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया जाएगा। किसान इस ऋण को लेकर कृषि संबंधित अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। यह किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बहुत ही राहत देने वाला कार्ड है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। जो शीशमहल में रहते हैं, जो लाल मिर्च पकाने की बात करते हैं, उन्हें क्या पता कि एक गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास क्या होता है। जिसको घर मिलता है, वह मोदी जी को धन्यवाद देता है, जिसका नंबर नहीं आता है, वह अपनी बारी का इंतजार करता है। गरीब सोचता है कि वह अपनी बेटी का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास में करा सके और अपनी बेटी के ससुराल वालों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिले उस गैस-चूल्हे पर चाय-नाश्ता बनाकर प्रधानमंत्री आवास में करवा सके। यह एक गरीब का सपना है। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने गरीब बहन-बेटियों की चिंता की है।

सभापति जी, जब महामहिम राष्ट्रपति जी अभिभाषण दे रही थीं, तब वह गरीब के हित और उसके उत्थान के लिए बोल रही थीं। देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित करते हुए एक ममत्व का भाव लिए मैं एक माता और बड़ी बहन के रूप में उन्हें देख पा रही थी, लेकिन विपक्ष के लोगों ने उनको … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कहकर … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) किया है। एक महिला होकर, महिला का उच्च पद उन्हें रास नहीं आ रहा है। एक आदिवासी महिला होने के नाते मैं विपक्ष के लोगों द्वारा बोल गए उन शब्दों की कड़ी निंदा करती हूं। मुझे गर्व है कि मेरे भारत देश की राष्ट्रपति एक गरीब आदिवासी महिला हैं।

(1725/SPS/UB)

विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि मोदी सरकार हर बार एक ही तरह के कार्य करती है। मोदी जी की सरकार अगर एक ही तरह के कार्य करती तो भारत पांचवी अर्थव्यवस्था नहीं बना होता और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने नहीं जा रहा होता। मेरी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के 97 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। किसान का बेटा-बेटी खेती को वैज्ञानिक तरीके से कर पाए, कम खेती में अधिक पैदावार कर सके, खेती की पढ़ाई कर सके, उसके लिए मेरे संसदीय क्षेत्र झाबुआ, अलिराजपुर में एक कृषि महाविद्यालय की मांग आपके माध्यम से करना चाहती हूं, ताकि आदिवासी भाई बहन भी आगे बढ़ सकें। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूं।

(इति)

1726 बजे

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया। किसी भी सरकार का बजट इस बात का द्योतक नहीं होना चाहिए कि रुपया कहां से आता है और कहां जाएगा। जब कोई बजट आने वाला होता है तो देश के करोड़ों लोगों की उससे आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं तथा वह उसमें परिलक्षित भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वित्त मंत्री जी के 2025-26 के बजट में इन सब बातों का अभाव है।

महोदया, सरकार ने इस बजट में कृषि को प्रगति का इंजन बताया है और दूसरी तरफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है, जो कृषि को बढ़ावा दे, कृषि को लाभकारी बनाए और किसानों की आय को बढ़ाएं। वर्ष 2014 में जब ये लोग सत्ता में आए थे तो कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्होंने रिपोर्ट को तो लागू नहीं किया, लेकिन तीन ऐसे कानून लेकर आए, जो न किसानों ने मांगे थे और न किसी ने मांग की थी। ये किसानों को तकलीफ देने वाले कानूनों को लेकर आए। किसानों ने संघर्ष किया और अगर यह सरकार पहली बार किसी के आगे झुकी तो किसानों के सामने झुकी। उसी बात का मलाल इस सरकार को है और किसानों से बदला लेने के लिए हर वह कार्रवाई कर रहे हैं, हर वह कदम उठा रहे हैं, जो किसानों के हित के नहीं हैं। सदन में चाहे खाद की बात आई, डीजल की बात आई, ट्रैक्टर पर जीएसटी की बात आई, लेकिन इस सरकार ने किसी भी चीज में किसानों को राहत नहीं दी। बहुत जोर-शोर से कहा गया कि हम तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन एक करोड रुपये का बजट रखा है। यह बहुत बड़ा देश है। इसमें एक हजार रुपये क्या मायने रखते हैं? इन्होंने न किसानों की कोई आय बढ़ाने का कोई काम किया, न किसानों की जमीन की हेल्थ सुधारने का कोई काम किया और किसानों को सच्चाई के लिए अच्छी तरह से पानी मिले, उसके लिए भी कोई काम नहीं किया।

सभापति महोदया, सबसे बड़ी बात यह है, जिसके लिए पूरे देश के किसान आंदोलनरत हैं तथा हरियाणा, पंजाब, यूपी के ज्यादा हैं। अन्य राज्यों और आपके निर्वाचन क्षेत्र के भी किसान आंदोलनरत हैं। सरकार ने एमएसपी की गारंटी देने की बात कही थी, लेकिन इस सरकार ने उसको इज्ज़त का सवाल बना रखा है और जो किसान दिल्ली आना चाहते हैं, उनको दिल्ली तक नहीं आने दे रहे हैं। कृषि के बारे में यह इनकी सोच है। इन्होंने कृषि का बजट लगभग उतना ही रखा है। जो बढ़ाया है और इन्फ्लेशन को जोड़ें तो इनका बजट नेगेटिव ही है। स्वास्थ्य के बारे में ये बहुत बढ़-चढ़कर बोल रहे हैं कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। यह योजना भी यूपीए सरकार ने शुरू की थी। जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और गुलाम नबी आजाद देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय यह योजना चालू की गई थी। मेरे स्टेट में भी सात मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए थे। आप मेडिकल कॉलेज खोलिए, यह अच्छी बात

है, लेकिन स्थिति है कि न वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, न मशीनें हैं, न फैकल्टी है और जब मान्यता देने के लिए चिकित्सा आयोग की जांच जाती है तो 50 साल पहले जो सरकारी क्षेत्र के कॉलेज कार्यरत हैं, उनकी फैकल्टी को वहां बुलाते हैं।

(1730/MM/GM)

अगर एक जिले में जाते हैं तो वहां बुलाते हैं, दूसरे जिले में जाते हैं तो वहां बुलाते हैं। अभी कुछ दिल पहले चर्चा हो रही थी कि अब स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ते हैं, जहां फैकल्टी नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे में कैसे अच्छे डॉक्टर तैयार होंगे, कैसे लोगों को हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे?

ये लोग हमारे नेताओं की बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की आलोचना करते हैं, इंदिरा जी की आलोचना करते हैं, राजीव जी की आलोचना करते हैं, मनमोहन सिंह जी की आलोचना करते हैं, यूपीए के प्रधान मंत्री हों या कांग्रेस के प्रधान मंत्री हों या कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार चली उसके प्रधान मंत्री हों, सबकी आलोचना करते हैं। 11 साल हो गए हैं लेकिन एक भी मेडिकल इंस्टिट्यूट ये दिल्ली के एम्स के लेवल का नहीं बना पाए हैं। डब्ल्यूएचओ का मानदंड है कि जीडीपी का पांच परसेंट हेल्थ केयर सेक्टर पर, हेल्थ सेवाओं पर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए। लेकिन, ये उसके कहीं भी नजदीक नहीं हैं। इनकी खुद की वर्ष 2017 की स्वास्थ्य नीति थी कि ढाई परसेंट खर्च करना है। उसके भी ये लोग कहीं नजदीक नहीं पहुंचे हैं। आज देश में उप-स्वास्थ्य केन्द्र देखें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखें, जिला अस्पताल देखें, जिले का मेडिकल कॉलेज देखें, कहीं वह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो विश्व स्तर का कहा जा सके। फिर भी वाह-वाही लूट रहे हैं कि हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। हम राजस्थान में 25 लाख रुपये एक व्यक्ति को इलाज के लिए बिना किसी शर्त के देते थे। पांच लाख रुपये की इनकी आयुष्मान भारत योजना को ये ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में जो सरकारी चिकित्सा संस्थान हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है और जो निजी क्षेत्र के चिकित्सालय हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बजट में भी उसी ओर ध्यान दिया गया है। आप शिक्षा को ले लीजिए जहां हजारों-लाखों पद प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में खाली पड़े हैं। हायर एजुकेशन की स्थिति यह है कि दुनिया के जो दो सौ इंस्टिट्यूट्स हैं, जो टॉप के हैं, उनमें एक भी भारत का सरकारी क्षेत्र का इंस्टिट्यूट नहीं है।

ये हमारे नेताओं की बहुत आलोचना करते हैं। इंदिरा जी ने दिल्ली में जेएनयू बनाया था। 11 साल में ये एक भी जेएनयू लेवल की सरकारी यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं कर पाए हैं। खाद्य क्षेत्र में आप देख लीजिए तो इंदिरा जी ने खाद्य में देश को अत्मनिर्भर बनाया। उसकी बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाद्य सामग्री दे रहे हैं। यह आप उस किसान के बलबूते पर दे रहे हैं, जो देश में अनाज पैदा करता है। इंदिरा जी की नीतियों के बलबूते पर

आप दे रहे हैं। इस बजट में पशुपालन पर एक शब्द भी नहीं कहा गया, जो कृषि का बहुत बड़ा कम्पोनेंट है, किसान की आय का बहुत बड़ा कम्पोनेंट है।

1734 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

आप इनकी कल्याणकारी योजनाओं की बात कर लीजिए। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी, उसको ये नेस्तनाबूद कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में आप देख लीजिए। आंगनवाड़ी को देख लीजिए। 80-90 हजार पद पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकताओं के खाली पड़े हैं। 70-75 हजार पद आशा सहयोगी बहनों के खाली पड़े हैं। बहुत सारे आंगनवाड़ी केन्द्र बिना भवन के चल रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में चाहे एससी-एसटी छात्रवृति को लें या ओबीसी छात्रवृति को लें या अल्पसंख्यक के कल्याण की योजनाओं की बात करें या हमारे एससी भाइयों के कल्याण की योजनाओं की बात करें, एसटी भाइयों और ओबीसी भाइयों के कल्याण की योजनाओं के लिए बजट एलोकेशन ये लोग घटाते चले जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि राज्यों पर ये बहुत बड़ा भार डाल रहे हैं।

केपिटल एक्सपेंडिचर की बात आयी। मेरे एक साथी बोल रहे थे। इस बजट में इन्होंने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि सरकार केपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी। हम इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे।

(1735/YSH/SRG)

युवाओं के लिए रोजगार की बात आई है। शुरूआत में प्रतिवर्ष दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, उस हिसाब से अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। इस बजट में ऐसी कोई बात नहीं की गई कि रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। खेती, जो 46 परसेंट लोगों को रोजगार देती है, उसके लिए कोई बात नहीं हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि बहुत बड़ी संख्या में रोजगार देता है, उसकी इस बजट में कोई बात नहीं हुई है। सर्विस सेक्टर बड़ी संख्या में रोजगार देता है, उसकी कोई बात नहीं की गई है। यहां कहा गया कि हम परमाणु संयंत्रों या परमाणु क्षेत्र में काम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी खोलेंगे।

अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि जब अमेरिका और भारत के बीच में परमाणु सहयोग के लिए संधि हुई तो यही लोग थे, जिन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश की थी, कठघरे में लाने की कोशिश की थी और आज ये उसी बात को मान रहे हैं कि वह समझौता अच्छा था।

माननीय अध्यक्ष : देश अब उसी से बदलेगा। ठीक है, धन्यवाद।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : अध्यक्ष जी, यहां पर 'उड़ान योजना' की बात आई है। मेरे राजस्थान के साथी यहां पर हैं। चूँकि आपके यहां पर अभी तक हवाई अड्डा ही नहीं बना है, लेकिन आप बहुत प्रयत्नशील हैं। बीकानेर से हमारे माननीय सदस्य आते हैं, जो सरकार के हिस्सा भी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि बीकानेर में उड़ान योजना की क्या स्थिति हुई? उड़ान उड़ी नहीं, उससे पहले ही नीचे उतर गई। उड़ान योजना कहीं पर भी धरातल पर नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : फिर तो आप झुन्झुनू में एयरपोर्ट की मांग मत कीजिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : अध्यक्ष जी, झुन्झुनू में पहले से ही हवाई पट्टी है, लेकिन वहां पर उड़ान नहीं है। वहां के उद्योगपति अपना निजी प्लेन लेकर आते हैं, उनके लिए निजी हवाई पट्टी भी है। अगर उड़ान बीकानेर में नहीं हुई तो मेरे यहां पर कहां से होगी? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कनक्लूड कीजिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत सारी बातें आई हैं। मेरा आपसे आग्रह यह है कि बिजली के सेक्टर में आपने राज्यों पर भार डाल दिया। पहले आप 'उदय योजना' लेकर आए थे, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लीजिए। इस बजट में कहा गया है कि हम पीपीपी मॉडल पर बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आप कनक्लूड करने के लिए बोल रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के एक-दो विषयों को उठाना चाहूंगा। पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि इस सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को 10 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। खेतड़ी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड है, जो कि मिनी नवरत्न है। वह उस धातु को बनाता है, जो हमारे देश की डिफेंस के लिए बहुत उपयोगी है। उस धातु का वहां पर खनन होता है। वहां पर पहले उसका संयंत्र था और वह धातु वहीं पर बनती थी, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। जब आप भारतीय इस्पात निगम को पैकेज दे सकते हैं तो फिर हमारे यहां के संयंत्र को भी देने का कष्ट करें।

झुन्झुनू जिले या मैं यह कहूँ कि शेखावटी में एक ही सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, जो कि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड है। आप वहां पर संयंत्र स्थापित करें। उसे आप अच्छे से चलाएं। एक समय था, वहां पर 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ था, लेकिन अब वहां पर सिर्फ 500 से 600 लोगों के पास रोजगार हैं। वहां से आप कच्चा माल निकालते हैं, जो दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस पर भी वित्त मंत्री जी ध्यान दें।

यह बजट न किसान का हितैषी है, न युवाओं के लिए हितैषी है, न आम आदमी का हितैषी है, न मध्यम वर्ग का हितैषी है। यह बजट सिर्फ कुछ कॉरपोरेट घरानों के हित का बजट है। आम आदमी के हित का बजट नहीं है, इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूँ।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : बजट में कुछ तो अच्छी बातें भी होती होंगी।

श्री इटेला राजेंदर जी।

1739 बजे

श्री इटेला राजेंदर (मल्काजगिरि) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले आठ महीनों से संसद की प्रोसिडिंग को देख रहा हूँ। मैं तेलंगाना राज्य का पूर्व वित्त मंत्री रह चुका हूँ। मैंने आज सुबह से कई माननीय सदस्यों के भाषण सुने। कांग्रेस पार्टी के ऑनरेबल मैम्बर ने जो बात की थी, उस बात को सुनने के बाद मुझे याद आया कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों से ज्यादा राज किया है।

(1740/RAJ/RCP)

वे बार-बार संविधान की प्रति को लेकर आते हैं और इसके बारे में बातें करते हैं। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान है। उनको इसके बारे में जानना चाहिए। अम्बेडकर जी ने डेवलपमेंट विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा था। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों से ज्यादा समय तक राज किया, लेकिन उन्होंने क्या किया?

कांग्रेस पार्टी आंकड़े के बारे में बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश के अलग-अलग राज्यों में भी राज किया है। स्टेट में अलग-अलग जिलों के बारे में बजट पेश नहीं किया जाता है। अगर देश के लिए बजट पेश होता है, तो अलग-अलग राज्यों के बारे में यह पेश नहीं किया जाता है। इसमें पूरे देश के किसानों के बारे में कहा जाता है। इसमें पूरे देश के युवाओं के बारे में प्लानिंग की जाती है। मगर ऐसा कभी नहीं होती। अगर कोई नई पार्टी जीत कर आई और यह बात की, तो वह सैड पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है।

महोदय, मैं 2 जून, 2014 को मंत्री बना था, तब यहां भी नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। जब दिल्ली में सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी नरेन्द्र मोदी जी ने एक ही बात कही थी कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास होगा। अगर राज्यों का विकास नहीं होगा, तो देश में भी विकास नहीं होगा। उन्होंने यह मूल मंत्र बताया था।

मोदी जी ने कहा कि केरल में 100 प्रतिशत लिटरेसी है, लेकिन बिहार में 100 प्रतिशत लिटरेसी नहीं है। स्टेट्स में गवर्नमेंट प्रायरिटी के हिसाब से डेवलपमेंट करना चाहती है। वर्ष 2014 तक टैक्स डेवोल्यूशन 32 प्रतिशत था। मोदी सरकार आने के बाद राज्यों के विकास के लिए टैक्स डेवोल्यूशन 42 प्रतिशत हो गया, जिसके कारण रेवोल्यूशनरी चेंजेज आया है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार कभी भी एक राज्य को दस हजार करोड़ रुपए या बीस हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन नहीं करती है। मैंने भी छ: सालों में माननीय वित्त मंत्री जी को अनेक दरख्वास्त दी थीं। मगर ऐसा नहीं हो सकता है।

टैक्स डेवोल्यूशन से राज्यों के पास पैसा आता है। सीएसएस के रूप में राज्यों के पास पैसा आता है। वहां कुछ विपत्ति आती है, तो पैसे दिए जाते हैं। 14वाँ वित्त आयोग ग्राम पंचायत और अर्बन बॉडीज के लिए फंड एलोकेट करता है। ऐसे पैसे आते हैं। मगर आंध्र प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए देना है, बिहार को 10 हजार करोड़ रुपए देना है, ऐसा कभी भी नहीं होगा।

मैंने इसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज देखा था। इस बार बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए विदाउट इंट्रेस्ट, अलग-अलग राज्यों में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलते हैं, अलग-अलग राज्य आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग प्लान करते हैं, उनके लिए जीरो रेट ऑफ इंट्रेस्ट के माध्यम से सपोर्ट करने का निर्णय लिया गया था। वह बहुत रेवोल्यूशनरी है। वह दिखता है या नहीं दिखता है, यह छोड़ देना है।…(व्यवधान) मैं तेलंगाना के बारे में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना में आज ग्राम पंचायत, म्युनिसपैलिटी, कार्पोरेशंस के लोगों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं।

(1745/SK/PS)

स्टेट के पास पैसे नहीं है, मगर गांव में ड्रेनेज व्यवस्था का पैसा कौन दे रहा है? आज यहां से पैसा जा रहा है। … (व्यवधान) आज गांवों के अंदर जो बिजली आ रही है, लाइट जल रही है, पैदल जाने के लिए रोड्स बनी हैं, ड्रेनेज व्यवस्था है, इस सबके लिए और गांवों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है। स्टेट के पास कुछ नहीं है, यह कहना उचित नहीं है, मैं जानता हूं।… (व्यवधान)

अब मैं रेलवे के बारे में बताना चाहता हूं। तेलंगाना की बात हो रही है। वर्ष 2014 तक हमारे यहां के रेलवे स्टेशन्स के लिए दो या तीन करोड़ रुपये देकर व्हाइट वाश का काम करवाया जाता था। मोदी जी के आने के बाद कॉरपोरशन और बड़े-बड़े शहरों के नाम पर फैसिलिटीज़ बढ़ाने की बात कही गई। हैदराबाद में 2000 करोड़ रुपये खर्च करके रेलवे स्टेशन कैसे बनाए जा रहे हैं? आप चर्लापल्ली में जाकर देखिए, कांचगुडा, नामपल्ली रेलवे स्टेशन देखिए, कैसे बनाए जा रहे हैं? मैं 2000 करोड़ रुपये के बारे में कह रहा हूं न कि दो करोड़ रुपये के बारे में कह रहा हूं।

परसों माननीय रेलवे मिनिस्टर सोमन्ना जी वहां इनऑगरेट करने के लिए आए थे। रेलवे स्टेशन 450 करोड़ रुपये में बना, लेकिन मिनिमम फेसिलिटीज़ के लिए राज्य सरकार को पूछा तो 50-100 करोड़ रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सोमन्ना जी को कहा कि 100 करोड़ रुपये देकर भी फेस लिफ्ट करने की कोशिश करो, नहीं तो 450 करोड़ रुपये खर्च करके जो बनाया है, यूज में नहीं आएगा। तेलंगाना में रेल की सिंगल लाइन को डबल लाइंस, डबल लाइंस को ट्रिप्पल लाइंस और ट्रिप्पल को फोर लाइंस में कंवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली ट्रंक लाइन बनाई जा रही है। हजारों करोड़ रुपये खर्च करके रेलवे के काम किए जा रहे हैं।

आज स्मार्ट सिटीज, अमृत सिटीज के नाम से अर्बन एरियाज़ में हजारों करोड़ रुपये में काम चल रहा है, लोगों के लिए फेसिलिटीज बढ़ रही हैं। ये काम इसी पैसे से हो रहे हैं। यह इन लोगों का पैसा नहीं है।

मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं। हम जानते हैं कि सर्विस सैक्टर में टैक्स ज्यादा आता होगा, इनकम टैक्स से ज्यादा टैक्स आता होगा, लेकिन एग्रीकल्चर से कितनी आमदनी होगी, यह नहीं बोल सकते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 50 परसेंट लोगों का जीवन एग्रीकल्चर से चलता है। राज्य सरकार ने क्या कभी एक पैसा फार्मर्स के लिए दिया है? माननीय मोदी जी की सरकार 11 करोड़ फार्मर्स को 6000 रुपये प्रति वर्ष दे रही है। इसके बारे में क्या उन्होंने पहले कभी सोचा है?

अब जीनोम का जमाना है। जेनिटिकल ज्ञान फार्मर्स को मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। एक पेपर में लिखा था – अगर दुनिया को भूख लगे तो भारत फूडग्रेन्स देने की क्षमता रखता है, भारत को अगर भूख लगेगी तो किसी देश की इतनी क्षमता नहीं है। यह एक पेपर में लिखा था।

अध्यक्ष जी, ये बात तो बोल सकते हैं लेकिन काम देखना भी जरूरी है। पहली बार इस देश के मछुआरों के लिए फिशरीज़ डिपार्टमेंट है। हमारे पास श्रिंप राजस्थान से आता था।

(1750/KN/SMN)

देश के अंदर शॉर्टेज़ हैं। श्रिंप के लिए स्कीम आई थी। केन्द्र सरकार 50 लाख रुपये सब्सिडी देती है। तेलंगाना के अंदर 200 लोगों के लिए सैंक्शन हुआ था, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बनी और उन लोगों को सब्सिडी नहीं मिली। उनको केवल 25 लाख रुपये दिये थे, बाकी 25 लाख रुपये अभी तक नहीं दिये हैं। वर्ष 2021 से … (व्यवधान) मैंने जाकर मीटिंग करवाई थी। आप क्या बात करते हैं? … (व्यवधान)

मैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। दुनिया के अंदर अमेरिका जैसी कंट्री में अगर भारत से विद्यार्थी वहां जाते थे तो वे पेट्रोल पम्पों पर काम करके स्टडी करते थे या सुपर मार्केट में काम करके स्टडी करते थे। लेकिन आज अमेरिका ने भी कैसा निर्णय लिया है, यह हमने देखा है। लास्ट बजट में हमारी गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 4 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा था। उसे टैकल करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वह क्या नहीं दिख रहा है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि देश में कोई भी स्कीम विदाउट स्टेट गवर्नमेंट नहीं आती थी, चाहे विश्वकर्मा स्कीम हो या जो दूसरी स्कीम्स हों, उन पर अमल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों में हमारी स्कीम्स पर अमल नहीं हो रहा है, इसके लिए थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। उन पर तुरंत अमल करने की कोशिश करनी चाहिए।

हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जर्मनी जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। एक काम करना जरूरी है कि अगर यहां पर एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, तो फर्स्ट मंथ सैलरी देने के लिए जो कंपनी सामने आती है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि पासपोर्ट, वीजा से लेकर वे लोग कौन सी कम्पनी में जा रहे हैं, उनको क्या तनख्वाह मिलती है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो अच्छा होगा। हमारे भारतवासी गल्फ कंट्री में एक कंपनी के नाम पर जाते हैं और दूसरी कंपनी में काम करते हैं। वहां पर वे जेल में रह रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसको ध्यान रखना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है, ताली बजाया करो न।

… (व्यवधान)

श्री इटेला राजेंदर (मल्काजगिरि) : सर, नेशनल हाइवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप जानते हैं कि ग्रीन फील्ड हाइवे बना रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

श्री इटेला राजेंदर (मल्काजगिरि) : सर, ग्रीन फील्ड हाइवे में एक नेगेटिव थिंग क्या है? हम तो समझ रहे हैं कि इतना अच्छा-अच्छा रोड बना रहे हैं। यह ठीक है कि रोड बना रहे हैं, लेकिन स्टेट के अंदर एक एकड़ जमीन की कीमत एक करोड़ रुपये होती है, वहां पर रजिस्ट्रेशन वैल्यू दो लाख रुपये होती है। दो लाख रुपये को 2.5 से मल्टीप्लाई करे तो दस लाख रुपये भी नहीं आता है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट चन्द्र शेखर जी।

… (व्यवधान)

श्री इटेला राजेंदर (मल्काजगिरि) : जब स्टेट के अंदर लैंड एक्विजिशन होता है, तो वह अलग होता है। नेशनल हाइवे के लिए, रेलवे के लिए जो लैंड एक्वायर होती है, उस लैंड्स के लिए कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी जाए। क्या रेट है, उस रेट के हिसाब से देंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, अन्यथा किसान दिल्ली में आकर दस-दस दिन … (व्यवधान) कुछ तकलीफ हो रही है। … (व्यवधान) मेरी रिक्वैस्ट है कि … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट चन्द्र शेखर जी।

श्री इटेला राजेंदर (मल्काजगिरि) : अध्यक्ष महोदय, अभी सात मिनट है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चन्द्र शेखर जी, एक मिनट रुकिये। आप एक मिनट में अपनी बात कनक्लूड कर दीजिए।

श्री इटेला राजेंदर (मल्काजगिरि) : अध्यक्ष महोदय, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने अलग-अलग राज्यों में लोगों की समस्या देखी थी, अलग-अलग वर्ग की समस्या देखी थी। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

एडवोकेट चन्द्र शेखर जी, आप बोलिये।

(1755/VB/SM)

1755 बजे

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

गरीबों को बजट से बहुत आशा थी, लेकिन जब बजट आया, तो सिर्फ निराशा थी। मैं अपनी बात की शुरुआत मान्यवर कांशी राम जी के नारे से करूँगा।

"जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।"

सर, वर्ष 2024-25 में, एससी, एसटी के लिए टोटल बजट में से 3.43 परसेंट राशि मिली थी, जबकि उनकी आबादी लगभग 25 परसेंट है। इस बार के बजट में, शिड्युल्ड कास्ट्स के लिए 3.3 परसेंट कर दिया गया है, जो पिछली बार से भी कम है। ऐसा लगता है कि सरकार ने एससी, एसटी की हालत सुधार दी है, लेकिन धरातल पर क्या है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कुल 16,45,424.28 करोड़ रुपए में से मात्र 93,963.41 करोड़ रुपए रिलीज किये गये हैं, जो ई-उत्थान की वेबसाइट पर दिया गया है। यानी यह राशि लगभग 60 परसेंट है। इस तरह से, पैसे तो हैं, लेकिन वे रिलीज नहीं कर रहे हैं। यह वेबसाइट पर है, जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ।

वर्ष 2024-25 में, शिड्युल्ड ट्राइब्स के लिए 3.47 करोड़ रुपए थे। वर्ष 2025-26 के बजट में यह लगभग न के बराबर बढ़ा है। स्ट्रेंथनिंग टीचर-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स में पिछली बार 210 करोड़ रुपए था, जिसे घटाकर इस बार 145 करोड़ रुपए कर दिये गये हैं।

सर, पीएम स्कूल्स के हालात बहुत खराब हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोई बड़ी घटना घट सकती है। वर्ष 2024-25 के बजट में इसके लिए 1220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष के बजट में इसके लिए मात्र 1 परसेंट की बढ़ोतरी करते हुए, इसे 1310 करोड़ रुपए किया गया है।

पीएम पोषण योजना के तहत 2512 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे इस बार घटाकर 2500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह सरकार की विफलता है।

नैशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप योजना में पिछले वर्ष दी जाने वाली राशि 70 करोड़ रुपए थी, इस बार भी यह राशि 70 करोड़ ही है, जबकि जनसंख्या बढ़ रही है और जरूरत भी बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में पिछली बार 315 करोड़ रुपए का बजट था और इस बार 258 करोड़ रुपए दिये गये हैं। सरकार ने कहा था कि हम लोग वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बनाएंगे। पिछली बार इसके लिए 341 करोड़ रुपए का बजट था, इस बार 90 करोड़ रुपए हैं।

सर, एससी, एसटी एट्रोसिटी होती है, उसका बजट समय से नहीं मिलता है। परिवारों को बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बजट का तो तभी फायदा होगा, जब सुरक्षा होगी। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि इतनी एट्रोसिटी हो रही हैं। आप राजस्थान से हैं। यह राजस्थान में बहुत हो रही हैं और यह देश भर में हो रही हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि इनकी सुरक्षा हो।

मेडिकल की पढ़ाई बहुत महँगी हो रही है, इस ओर कोई विशेष काम नहीं हुए हैं। गरीब बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल की महँगी शिक्षा के कारण उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं।

बजट में एडवोकेट और लॉयर्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं है। मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र के लिए एम्स की माँग की थी। हाल ही में, कुम्भ की घटना हुई। अगर हाइयर सेन्टर न होती तो बड़ा नुकसान हो जाता। बड़ौत की घटना हुई, वहाँ हाइयर सेन्टर नहीं था, इसलिए वहाँ बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे सारे क्षेत्रों में, जहाँ हाइयर सेन्टर्स नहीं होंगे, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वहाँ की जनता को भी जीने का अधिकार है।

इस तरह से, एम्स की माँग पूरी नहीं हुई, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना। वहाँ लकड़ी का शानदार काम होता है। उसकी बेहतरी के लिए आगे कोई काम नहीं हुआ। रोज़गार नहीं हैं। रोज़गार की वजह से ही अमेरिका ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे देश के नौज़वान रोज़गार की कमी के कारण ही वहाँ जाते हैं।

हमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली। बजट में मुसलमानों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए क्या दिया?

सर, आपके माध्यम से, मेरी एक विशेष माँग है। यहाँ पर बहुत-से मिनिस्टर्स बैठे हैं। हम देश में इसलिए सुरक्षित हैं कि बॉर्डर्स पर सेना खड़ी है। एयरपोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक अर्द्ध-सैनिक बल तैनात हैं। उनकी वजह से, हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार से मेरी माँग है कि हमारी फौजों, हमारे अर्द्ध-सैनिक बलों के वेतन को टैक्स फ्री किया जाए। अगर उनके वेतन पर भी टैक्स लगेगा, तो आप समझ सकते हैं, वे अपनी पीड़ा को किसी से नहीं कहते हैं, न ही उनकी कोई यूनियन है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि सेना और अर्द्ध-सैनिक बल के जवानों के वेतन इनकम टैक्स से मुक्त होने चाहिए ताकि वे भी अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें।

सरकार ने पुरानी पेंशन के बारे में कुछ नहीं कहा। इसको लेकर बहुत से बुजुर्ग लोग परेशान हैं। नौजवानों के लिए क्या है? आज पढ़े-लिखे नौजवान बेकार घूम रहे हैं। स्किल के बाद क्या है? माँ-बाप अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? अगर रोज़गार नहीं मिलेगा, तो वे कहाँ जाएंगे?

किसानों के लिए कुछ नहीं है। इतने किसानों की जानें गई थीं, उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा।

सरकार ने पिछली बार न्यूनतम वेतन के बारे में कहा था, लेकिन धरातल पर उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मनरेगा में जॉब नहीं मिल रही है। मैं गांवों में गया था। जॉब कार्ड्स बने हुए हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। इसमें एक सौ दिनों के काम की गारंटी थी।

सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। अंत में, मैं कहना चाहूंगा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट बना दीजिए। ये लोग सीवर में मरते हैं। यह पूरे देश के लिए अपमान का विषय है। ये सम्मान का विषय नहीं है। जब देश के सफाई कर्मचारियों के साथ

ऐसा होता है, तो इससे पूरे देश का अपमान होता है। कुम्भ में देखिए, वहाँ क्या सफाई की व्यवस्था है? यह किसकी देन है, यह नेता-मंत्रियों की देन है या सफाई कर्मचारियों की है? वे सफाई कर्मचारी, जो सीवर में उतरते हैं, वे गांव-देहात में सिर पर मैला उठाते हैं। यह बहुत ही तकलीफ का विषय है।

मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सरकार अन्य स्टेट्स से भी बात करे। इसका बजट बढ़ाए क्योंकि इस देश में बेटियों की रक्षा होनी चाहिए।

(1800/PC/RP)

इस देश में बेटियों की रक्षा होनी चाहिए। जब तक बेटियों की रक्षा नहीं होगी, जिनको हम धार्मिक रूप से देवियों की तरह पूजते हैं, जब तक उन बेटियों की रक्षा नहीं होगी, तब तक देश मजबूत नहीं होगा।

मैं वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि मैंने जो सवाल उठाए हैं, वे जब अपना जवाब दें, तो उसमें बताएं कि उन्होंने ये सारी कटौतियां क्यों कीं? क्या एससी, एसटी के पढ़ने का अधिकार छीनकर सरकार तरक्की कर सकती है? यह संभव नहीं है।

धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1801 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 फरवरी 2025 / 21 माघ 1946 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।